चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

अन्ना की दस ग़लतियां

पेज-3

पीस पार्टी बनी ख़तरे की घंटी

पेज-4

नेता सिर्फ़ ज़ख्म कुरेदते हैं, मरहम नहीं देते

पेज-5

साई की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 4 जुलाई–10 जुलाई 2011 | मूल्य 5 रुपये

मनमोहन सिंह राष्ट्रपति और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

संतोष भारतीय

भारत के एक ताक़तवर मंत्री ने सीबीआई के डायरेक्टर को मिलने के लिए बुलाया. जब वे मिलने आए तो उस मंत्री ने चाय मंगवाई. जब चाय का पहला घूंट मंत्री और सीबीआई डायरेक्टर ने ले लिया तो मंत्री ने कुछ कहना चाहा. सीबीआई डायरेक्टर ने उन्हें रोकते हुए विनम्रता से कहा कि मंत्री जी, आपने बुलाया, मैं प्रोटोकाल के तहत आपसे मिलने चला आया. प्रोटोकाल कहता है कि जब भी कोई केंद्रीय मंत्री बुलाए, मुझे जाना चाहिए. पर अब जो भी आप मुझे कहेंगे या आदेश देंगे, उसे मुझे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करना पड़ेगा. डायरेक्टर सीबीआई की बात सुनते ही उन केंद्रीय मंत्री के हाथ की प्याली कांप गई और चाय छलक गई.

सोनिया गांधी का कोर ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचा है कि सरकार कोलैप्स की तरफ़ बढ़ रही है. चिंता यह है कि जब विपक्ष कमज़ोर है, जनता में उसकी साख नहीं है, तब भी सरकार के कामकाज के तरीक़े की वजह से पार्टी साख खोती जा रही है.

दिग्विजय सिंह का मानना है कि किसी भी दल में इन दिनों एकता नहीं है, सभी आपस में लड़ रहे हैं और जनता उनसे ख़ुश नहीं है. यही सही वक़्त है कि देश की सरकार का नेतृत्व बदला जाए और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक युवा सरकार बनाई जाए.

भारतीय जनता पार्टी के सूत्र कुछ अदालतों का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज कुछ परेशानी में पड़ने वाली हैं. वे परेशानी में पड़ें या न पड़ें, पर मुंडे कांड भारतीय जनता पार्टी में चल रहे अंदरूनी झगड़ों को एक बार फिर बेनक़ाब कर गया है. इसी आपाधापी में अन्ना हजारे और बाबा रामदेव अपने-अपने को तौल रहे हैं. अन्ना हजारे उत्तर भारत में भ्रमण की योजना बना रहे हैं. उनकी यात्रा में कितने लोग इकट्ठे होते हैं, तय करेगा कि उनका और लोकपाल बिल का कितना आकर्षण बचा है. देश की राजनीति में एक तीसरी घटना और होने वाली है. नए सिरे से दलों के संबंध बनने और बिगड़ने वाले हैं. हमारी पुख्ता जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र में शिवसेना, दलित नेता रामदास अठावले और शरद पवार का गठजोड़ बनने वाला है. शरद पवार की तरफ़ से यह प्रस्ताव शिवसेना के पास गया है कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी को छोड़े, उसके बाद शरद पवार कांग्रेस को छोड़ देंगे और ये तीनों मिलकर महाराष्ट्र में एक साथ कैंपेन करेंगे और सरकार बनाएंगे. अगर रामदास अठावले, शिवसेना और शरद पवार का गठजोड़ महाराष्ट्र में बनता है तो महाराष्ट्र का भविष्य आईने की तरह साफ़ है. फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी. राज ठाकरे को जितने वोट मिलने थे या जितना समर्थन मिलना था, वह पिछली बार मैक्सिमम मिल गया. अब राज ठाकरे को इससे ज़्यादा समर्थन नहीं मिलने वाला. यही सोचकर शरद पवार, उद्धव ठाकरे और रामदास अठावले तीनों मिलकर एक नए गठजोड़ के सूत्रपात की तैयारी कर रहे हैं, जो देश में बहुत बड़ा परिवर्तन भी ला सकता है. लेकिन इस हालत में और भ्रष्टाचार की नई खुलती कहानियों के बीच मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने मांग कर डाली है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए. दो दिन बाद उन्होंने कहा कि उनका मतलब यह नहीं था कि मनमोहन सिंह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए. दिग्विजय सिंह की इस महत्वपूर्ण मांग के पीछे एक सोची-समझी रणनीति है.

देश को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकार दो अलग-अलग चीज़ें हैं. इन दिनों दोनों आमने-सामने खड़ी हैं. कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी सहित अहमद पटेल, मोती लाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी. इन दिनों कांग्रेस पार्टी के कोर ग्रुप में दिग्विजय सिंह डोमिनेट कर रहे हैं. अहमद पटेल और मोती लाल वोरा अक्सर ख़ामोश रहते हैं और दिग्विजय सिंह व जनार्दन द्विवेदी तार्किक बहस कर रणनीति बनाते हैं. यह अलग बात है कि बैठक के बाद अहमद पटेल और सोनिया गांधी की फिर बात होती है. मोतीलाल वोरा तभी अपनी राय देते हैं, जब सोनिया गांधी उनसे पूछती हैं. एक व्यक्ति और है, जिससे सोनिया गांधी राय लेती हैं, उनका नाम है पुलक चटर्जी.

कांग्रेस सरकार के क्रियाकलाप, विपक्षी दलों में एक होने की छटपटाहट तथा अन्ना हजारे और रामदेव की संभावित रणनीति का मुक़ाबला करने की रणनीति दिग्विजय सिंह ने बनाई है. उनका मानना है कि किसी भी दल में इन दिनों एकता नहीं है. सभी आपस में लड़ रहे हैं और जनता उनसे ख़ुश नहीं है. इतना ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल में युवा नेतृत्व नहीं है और देश का नौजवान एक उपयुक्त नेता और उपयुक्त दल की तलाश में है. यही सही वक़्त है कि देश की सरकार का नेतृत्व बदला जाए और राहुल गांधी के नेतृत्व में एक युवा सरकार बनाई जाए. राहुल गांधी एक नया प्रोग्राम घोषित करें. संभवत: दिग्विजय सिंह के दिमाग़ में इंदिरा गांधी रही होंगी. इंदिरा गांधी ने पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और बाद में ग़रीबी हटाओ का लुभावना नारा दिया था तथा देश में एक नई आशा पैदा की थी. अब दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि पूरी कांग्रेस का कायाकल्प हो, इसकी शुरुआत दिल्ली की सरकार से हो.

राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना से केवल विपक्षी दल ही हैरान नहीं हुए हैं, बल्कि कांग्रेस के भीतर भी भिनभिनाहट शुरू हो गई है. कांग्रेस के भीतर लगभग इस बात पर एक राय है कि लोकसभा का चुनाव उनके लिए टेढ़ी खीर साबित होने वाला है. हालांकि उन्हें इस बात से आराम भी मिलता है कि भाजपा का भी ग्राफ बन नहीं रहा है. पर कांग्रेस नेतृत्व उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश की गंभीरता को समझ रहा है. कर्नाटक में भी वह देवगौड़ा से नज़दीकी बनाना चाहता है, पर उसकी शुरुआत दिल्ली से हो, इस पर एक राय बन गई है. उत्तर प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों में होने वाले चुनावों का सामना नए प्रधानमंत्री के चेहरे से हो, इस पर एक राय बन गई है. सोनिया गांधी इस पर ख़ामोश हैं, पर उन्हें भी लगता है कि दोबारा केंद्र में सरकार बनाने के लिए जो भी किया जा सकता है, करना चाहिए. एक और पेंच बीच में फंसा है. सुब्रमण्यम स्वामी पर राजनीतिक हलकों में भरोसा नहीं था, लेकिन वे टू जी मामले पर विश्वास में थे और उनके सतत प्रयास से इस मामले में ए राजा, कनीमोई सहित कई बड़े नाम तिहाड़ में हैं. ऐसा लगता है कि सीबीआई की पूरक एफआईआर में दो बड़े उद्योगपतियों के नाम भी आ सकते हैं. अब स्वामी कह रहे हैं कि टू जी की आंच टेढ़े ढंग से दस जनपथ तक पहुंच सकती है.

ऐसे माहौल में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की योजना मास्टर पीस योजना है. राहुल गांधी का राजनीतिक शिक्षण दिग्विजय सिंह कर रहे हैं. राहुल गांधी की परेशानी यह है कि हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की समस्याएं, यहां के अंतर्विरोध और यहां के सामाजिक तनाव उनकी समझ में नहीं आ रहे. कभी उनका सामना ही ऐसे सवालों से नहीं हुआ. यहां के जातीय ढांचे, सामाजिक ढांचे का राजनीति पर प्रभाव तथा राजनीति पर वर्गों और जातियों के गठबंधनों के परिणामस्वरूप उसके बदलते चेहरे का सामना कभी राहुल गांधी ने किया ही नहीं है. उत्तर पूर्व की समस्याएं, कश्मीर, चीन का हमारे अर्थतंत्र पर हमला जैसे सवाल राहुल गांधी के दरवाज़े पर खड़े हैं. इतना ही नहीं, मुसलमानों की परेशानियां और हिंदुओं की भावनाओं का कैसे फंडामेंटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, इसे राहुल गांधी जानते ही नहीं हैं.

राहुल की एक समस्या और है, वे ज्ञान की जगह सूचनाओं द्वारा संचालित होते हैं. इसका अभी-अभी का उदाहरण है भट्टा पारसौल, जहां किसानों के बीच राहुल बैठे थे. उन्होंने दिल्ली आकर कहा कि बहुत से किसानों को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मारकर जला दिया है. उस गांव का कोई आदमी ग़ायब नहीं है, कोई मारा नहीं गया. लेकिन जो व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार है, वह ऐसा बयान

(शेष पृष्ठ 2 पर)

सुब्रमण्यम स्वामी पर राजनीतिक हलकों में भरोसा नहीं था, लेकिन वे टू जी मामले पर विश्वास में थे और उनके सतत प्रयास से इस मामले में ए राजा, कनीमोई सहित कई बड़े नाम तिहाड़ में हैं. अब स्वामी कह रहे हैं कि टू जी की आंच टेढ़े ढंग से दस जनपथ तक पहुंच सकती है.

सोनिया गांधी, अहमद पटेल, मोती लाल वोरा, जनार्दन द्विवेदी और दिग्विजय सिंह इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो शायद कांग्रेस दोबारा सत्ता में नहीं आ पाएगी. एक व्यक्ति और है, जिससे सोनिया गांधी राय लेती हैं, उनका नाम है पुलक चटर्जी.

"Cotton ki Jhappi!"

T.T.

Healthy Innerwear

Vest • Brief • Bra-Panties • T-Shirts

Ph. : 011-45060708, E-mail: export@tttextiles.com

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक पी एच कुरियन की ज़रूरत केरल में सत्ता में वापस आई कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

एनएचएआई चेयरमैन की खोज जारी

कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परिवहन मंत्री सी पी जोशी को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को पुनर्गठित करने का काम करें. दरअसल, इस एजेंसी में एक पूर्णकालिक चेयरमैन की नियुक्ति का मामला कई महीने से अटका हुआ है. निश्चित तौर पर जोशी और उनके बाबुओं की पहली प्राथमिकता अब इस एजेंसी के लिए एक पूर्णकालिक चेयरमैन की तलाश करना है. यह पद छह महीनों से रिक्त है, जब पिछले साल दिसंबर में ब्रजेश्वर सिंह इस पद से रिटायर हुए थे. सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय के भीतर कई सुझावों पर चर्चा हो रही है. इसमें एक सुझाव यह भी है कि इस पद के लिए किसी टेक्नोक्रेट के नाम पर भी विचार किया जाना चाहिए. जोशी और परिवहन मंत्रालय के सचिव आर एस डब्ल्यू गुजराल (गुजराल अभी एनएचएआई के कार्यवाहक चेयरमैन हैं) एक निजी सड़क विकास एजेंसी के उस सुझाव पर भी ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि एनएचएआई के प्रत्येक सदस्य को एक विशेष कार्य सौंपा जाए. सूत्रों के मुताबिक, मंत्रालय ने ये सारे सुझाव प्रधानमंत्री कार्यालय को भेज दिए हैं. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि प्रस्तावित बदलावों को मान लिया जाएगा.

कुरियन की वापसी

इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी कार्यालय (आईपी ऑफिस) में काफी महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत करने वाले बाबू के बारे में खबर है कि वह अपने 5 साल के कार्यकाल को बीच में ही छोड़ कर अपने मूल कैडर केरल वापस जा रहे हैं. सूत्रों के मुताबिक, पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क के महानियंत्रक पी एच कुरियन की जरूरत केरल में सत्ता में वापस आई कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है. केरल में कुरियन की वापसी प्रधान सचिव के तौर पर होगी. वह सिर्फ अभी केंद्र से मंजूरी मिलने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि कार्यकाल के बीच में ही कुरियन के वापस जाने को लेकर यह अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है कि उन्होंने आईपी ऑफिस में जो सुधारात्मक कार्य शुरू किए थे, वे प्रभावित होंगे. लेकिन अभी तो कुरियन सिर्फ अपने गृहराज्य की ही बात सुनने के मूड में हैं.

dilipcherian@gmail.com

साउथ ब्लॉक

राजू आईईएफ के महासचिव

कर्नाटक कैडर और 1984 बैच के आईएएस अधिकारी डी एन नरसिम्हा राजू अभी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं. खबर है कि राजू सऊदी अरब के रियाद स्थित इंटरनेशनल एनर्जी फोरम सेक्रेटेरियट के महासचिव बनाए जा सकते हैं.

संजीव नए चेयरमैन

1969 बैच के स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस अधिकारी संजीव हांडा को रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन बनाए जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है. हांडा अभी रेलवे बोर्ड के तकनीकी सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

राजीव नेफेड के एमडी

पिछले साल नेफेड के एमडी सी वी आनंद बोस को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था. अब इस पद पर 1979 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव गुप्ता को नियुक्त किया जाएगा. यह पद संयुक्त सचिव के समकक्ष है.

मुरुगनंनदम बने जेएस

तमिलनाडु कैडर और 1991 बैच के आईएएस अधिकारी एन मुरुगनंनदम अभी जहाज रानी मंत्री के पी एस के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्हें संयुक्त सचिव (जेएस) के पद पर प्रोन्नति दे दी गई है. मुरुगनंनदम को ग्रामीण विकास मंत्रालय में अमिता शर्मा की जगह संयुक्त सचिव के पद पर भेजा गया है.

आलोक समन्वय सचिव

1977 बैच के आईएएस अधिकारी आलोक रावत कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय एवं पीजी) नियुक्त किए जा सकते हैं. आलोक अभी यूपीएससी में सचिव हैं. वह अजीत सेठ की जगह लेंगे, जिन्हें कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है.

मनमोहन सिंह राष्ट्रपति और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे

पृष्ठ एक का शेष

दे दे, तो उसे क्या कहेंगे. राहुल गांधी ने ऐसा बयान सिर्फ़ छोटे कार्यकर्ताओं की अति उत्साही बचकानी सूचनाओं के आधार पर दिया. अगर उन्हें प्रधानमंत्री बनना है तो तथ्यों की जांच कर बोलने के बुनियादी सिद्धांत का पालन करना चाहिए.

राहुल गांधी के लिए आवश्यक है कि वे अपने परनाना पंडित जवाहर लाल नेहरू की कुछ किताबें अवश्य पढ़ें, जिनमें भारत एक खोज और पिता के पत्र पुत्री के नाम प्रमुख हैं. उन्हें महात्मा गांधी की हिंद स्वराज और कार्ल मॉर्क्स की कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो अवश्य पढ़नी चाहिए. हिंदुस्तान को समझने के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया का साहित्य पढ़ना उनके लिए आवश्यक है, जिसके बारे में जनार्दन द्विवेदी से ज़्यादा उन्हें आज और कौन बता सकता है. राहुल गांधी को ज्ञान और सूचना का फ़र्क़ समझना चाहिए. अगर नॉलेज ओरिएंटेड व्यक्ति नहीं होगा तो वह लॉजिक या तर्क आधारित होगा और उससे हमेशा ग़लतियां होंगी. तर्क या लॉजिक या सूचना को कसौटी पर कसने का काम नॉलेज या ज्ञान करता है. यही दिग्विजय सिंह की बड़ी कमज़ोरी और चुनौती भी है कि वे राहुल गांधी को कैसे इसके लिए तैयार करते हैं. आने वाला समय ख़तरनाक है. दिग्विजय सिंह राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का फ़ैसला तो कर सकते हैं, लेकिन सफल होने का रास्ता तो राहुल गांधी को ही तलाशना होगा. अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उन्हें इतिहास के सबसे असफल प्रधानमंत्री की उपाधि न मिल जाए, इस ख़तरे से बचने के उपाय अभी से तलाशने होंगे.

राहुल गांधी के ऊपर पार्टी के भीतर भी वार हो रहे हैं, लेकिन वे सीधे नहीं हैं. उनका निशाना केयर ऑफ दिग्विजय सिंह हैं. दिग्विजय सिंह पर भाजपा से ज़्यादा वार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं. अभी हाल ही में दो घटनाएं हुईं. दिग्विजय सिंह के आज़मगढ़ आधारित अभियान को बर्बाद करने की कोशिश हुई. वहीं रामदेव के ख़िलाफ़ दिग्विजय सिंह की रणनीति का मखौल सबसे पहले कांग्रेस के एक शक्तिशाली गुट ने उड़ाया. उन्होंने सोनिया गांधी तक से कहा कि रामदेव के ख़िलाफ़ बोलने से दिग्विजय सिंह को रोकना चाहिए, लेकिन दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी और फिर सोनिया गांधी को समझा लिया कि रामदेव से राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहिए. आज कांग्रेस अधकचरी ही सही, पर एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है.

राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत सुधारना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने उम्मीदवार आधारित संगठन बनाने का फ़ैसला लिया है. ज़िले के सारे विधानसभा उम्मीदवार बूथ स्तर तक की कमेटी बनाएंगे और इन्हीं पर आधारित ज़िला कमेटियां तथा बाद में प्रदेश कमेटी बनेगी. यह रणनीति दिग्विजय सिंह की है, जिसे राहुल गांधी के नाम से पार्टी में भेजा गया है. लेकिन दिग्विजय सिंह भूल जाते हैं कि जाति आधारित कोई संगठन कभी मज़बूत नहीं होता. सबसे बड़ा सवाल विचारधारा का है. कांग्रेस की विचारधारा है क्या, इसे कांग्रेस ही नहीं जानती. कांग्रेस के पास अब विचारधारात्मक किताबें नहीं हैं. विभिन्न सवालों पर राय बताने वाला साहित्य नहीं है. इसके लिए किसी के पास वक़्त ही नहीं है. दिग्विजय सिंह द्वारा उत्प्रेरित कांग्रेस की राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की रणनीति में छोटी-मोटी कमियां हैं, जिन्हें कांग्रेस ठीक कर सकती है. वह राहुल गांधी को सामने रख विपक्षियों को उलझा सकती है, लेकिन ख़ुद कांग्रेस के भीतर पेंच है. काल्पनिक सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस योजना का साथ देंगे. सोनिया गांधी का कोर ग्रुप उन्हें राष्ट्रपति बनाने के बारे में विचार कर रहा है.

अगर मनमोहन सिंह न माने, क्योंकि वे प्रधानमंत्री बन चुके हैं और यह भारत का सबसे ताक़तवर पद है. अगर उन्हें लगे कि जनता को साथ लेकर कुछ नया किया जा सकता है तो क्या होगा. ऐसी ख़बरें सरकारी अधिकारी बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह ने अब सोनिया गांधी की, उनके कोर ग्रुप की बातें सुनना कम कर दिया है. इतना ही नहीं, जिन अधिकारियों के रिटायरमेंट में साल या दो साल रह गए हैं, उन्होंने तो काम करना ही बंद कर दिया है. एक तरफ़ सोनिया गांधी का नाम लेकर काम करने का दबाव तो दूसरी तरफ़ किसी अधिकारी का बचाव मनमोहन सिंह सरकार नहीं कर रही है. टेलीकॉम स्कैंडल में कई बड़े अधिकारी जेल में हैं, जबकि उनका दोष इतना ही है कि उन्होंने बड़े राजनीतिक लोगों की बात मान फाइलें क्लीयर कर दी थीं.

सोनिया गांधी का कोर ग्रुप इस नतीजे पर पहुंचा है कि उनकी सरकार कोलैप्स की तरफ़ बढ़ रही है. उनकी चिंता है कि जब विपक्ष कमज़ोर है, जनता में उसकी साख नहीं है, तब भी सरकार के काम करने के तरीक़े की वजह से पार्टी साख खोती जा रही है. ऐसे में उड्डयन मंत्री रहते प्रफुल्ल पटेल का कोई बड़ा घोटाला सामने आ जाए या फिर तेल मंत्री मुरली देवड़ा का कोई कारनामा सामने आ जाए तो क्या होगा. संसद के आगामी सत्र के दौरान सीएजी की रिपोर्ट इन दोनों के ख़िलाफ़ आने वाली है. अन्ना हजारे का संभावित अनशन, उसके पहले उनका कई राज्यों का दौरा और अब सरकार के कई मंत्रियों का कच्चा चिट्ठा सामने आने का डर. इससे बचने का एक ही तरीक़ा है कि इंदिरा गांधी की तरह एक नया सपना देश को दिखाया जाए.

नया प्रधानमंत्री, नया चेहरा, नए वायदे और युवाओं को सत्ता में आने का आमंत्रण, इसके इर्द गिर्द रणनीति बनाई जा रही है. आशा की जा रही है कि इससे न केवल उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी प्रासंगिक हो जाएगी, बल्कि गुजरात में भी नई आशा कांग्रेस को लेकर पैदा होगी. पर इसके लिए राहुल गांधी को कालिदास की इमेज से बाहर निकलना होगा. अभी तो माना जा रहा है कि वे दिग्विजय सिंह की भाषा बोल रहे हैं. आपको कालिदास की कहानी याद होगी कि वे जिस डाल पर बैठे थे, उसी को काट रहे थे. विद्योत्तमा को हराने के लिए पंडितों ने उन्हीं को चुना. कांग्रेस का कोर ग्रुप विपक्ष को धराशायी करने के लिए जो रणनीति बना रहा है, वह सफल नहीं होगी, क्योंकि अब सैकड़ों साल बाद का ज़माना है.

अब जिसे प्रधानमंत्री बनना है, उसे योग्यता के आधार पर अपना दावा ठोंकना होगा. राहुल गांधी को देश के सवालों के जवाब खुलकर अख़बार वालों के माध्यम से देने होंगे. सवालों के जवाब और उन्हें देखने का तरीक़ा ही देश के लोगों के मन में उनके लिए समर्थन का निर्माण करेगा. चेहरा राहुल गांधी का और भाषा दिग्विजय सिंह की, यह अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है. आख़िर में फिर मनमोहन सिंह की बात बताना चाहता हूं. कॉमनवेल्थ गेम्स की जांच करने वाली शुंगलू कमेटी ने सुरेश कलमाडी के साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर फिर उंगली उठाई है. शुंगलू समिति की रिपोर्ट के अगले हिस्सों में कुछ ऐसे भी नाम हैं, जो सोनिया गांधी के लिए परेशानी पैदा कर सकते हैं. एक काल्पनिक सवाल है कि मनमोहन सिंह अगर प्रधानमंत्री पद छोड़कर भ्रष्टाचार का नाम लेकर देश में निकल पड़ते हैं तो देश का इतिहास बदल जाएगा. वे महापुरुष बन जाएंगे. उनका नाम नेहरू के समकक्ष लिया जाएगा. पर मनमोहन सिंह ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वे ही हैं, जिन्होंने देश में अमेरिकन हितों को भरपूर बढ़ावा भी दिया और देश को अघोषित गुलामी की हालत में पहुंचा दिया है. पर राजनीति एक ऐसी चीज़ है, जिसमें तार्किक परिणति के लिए बहुत कम जगह होती है. राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना और मनमोहन सिंह के लिए भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन करना ऐसे ही सवाल हैं. यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं, जो हमेशा लोकसभा का चुनाव हारे और राज्यसभा में रहते हुए उन्होंने अपना मंत्री पद का पूरा कार्यकाल काट दिया. उन्होंने इच्छा भी व्यक्त नहीं की कि वे लोकसभा का चुनाव लड़ें. जबकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं तो वे राज्यसभा में आई थीं, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी राज्यसभा से इस्तीफ़ा देकर लोकसभा का चुनाव लड़ा. और आदर्श स्थिति यह है कि देश का प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुने जाने योग्य या उनका भरोसा पाने योग्य कोई व्यक्ति होना चाहिए.

एक नया संकट देश के सामने खड़ा होने वाला है. भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल वी के सिंह के जन्मदिन का विवाद सरकार हल नहीं करना चाहती. भारत के सुप्रीम कोर्ट के तीन भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस खन्ना, चीफ जस्टिस लहोटी और चीफ जस्टिस जे एस वर्मा ने अपनी लिखित राय जनरल वी के सिंह के पक्ष में दी है. नीरा राडिया के संपर्क में रहे भारत के एटार्नी जनरल वाहनवती ने जनरल वी के सिंह के ख़िलाफ़ राय दी है. जनरल वी के सिंह की उम्र क्या है, यह विवाद तब उठा है, जब वे रिटायरमेंट के नज़दीक हैं. इस विवाद को बढ़ाने में सेना के दूसरे नंबर के जनरल और ख़ुद प्रधानमंत्री निवास में रहने वाली एक महिला हैं. जनरल वी के सिंह के पक्ष में यदि निर्णय नहीं होता है तो उन्हें मजबूरन अपने को सच साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. माना जा रहा है कि यह देश का पहला ऐसा मामला होगा और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है. तकनीकी तौर पर भारत की राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाध्यक्ष हैं और फ़ैसला उन्हें ही लेना है. भारत की सरकार कैसे समस्याएं पैदा करती है और उन्हें बढ़ाती है, सेनाध्यक्ष की उम्र का सवाल इसका जीवित उदाहरण है.

पर ऐसे सवालों से राहुल गांधी को दो-चार तो होना ही पड़ेगा, अगर कांग्रेस उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए संसदीय दल का नेता चुन लेती है तो. कांग्रेस संसदीय दल में अगस्त से शुरू होने वाले सत्र में एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाने वाला है, जिसमें राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने वाले सांसदों के दस्तख़त होंगे. अगर दो सौ दस्तख़त हो जाते हैं तो मनमोहन सिंह के सामने क्या रास्ता रह जाएगा, यह सवाल आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा.

editor@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 3 अंक 17
दिल्ली, 4 जुलाई –10 जुलाई 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4+4+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

अन्ना और उनकी टीम ने अपने आंदोलन के पहले और बाद में भी जिस एक मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वह था एक मज़बूत संगठन का निर्माण.

अन्ना की दस ग़लतियां

आख़िर क्या वजह रही कि अन्ना हज़ारे एंड टीम लोकपाल के मुद्दे पर अपनी बात सरकार से मनवा पाने में असफल रही, क्यों सरकार जन लोकपाल के महत्वपूर्ण प्रावधानों से सहमत नहीं हुई, अन्ना टीम की किस ग़लती ने महीनों की मेहनत पर पानी फेर दिया और क्या दोबारा अनशन की चेतावनी का असर देखने को मिलेगा?

इस आंदोलन में भारत के 6 लाख से ज़्यादा गांवों का प्रतिनिधित्व शायद ही दिखता है. इस आंदोलन से किसानों, मज़दूरों एवं आदिवासियों की उपस्थिति ग़ायब है यानी अन्ना टीम अपने आंदोलन में ग्रामीण भारत की भागीदारी की ज़रूरत नहीं समझती.

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

शशि शेखर

अन्ना का आंदोलन एक अच्छे लोकपाल के गठन को लेकर हुआ था. पांच दिनों तक जंतर–मंतर पर अन्ना का अनशन चला, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अपार जन समर्थन मिलने के बाद भी अन्ना और उनकी टीम ने सरकार से समझौते के वक़्त जो मांगें रखीं, वे ठीक उस कहावत की तरह थीं कि खोदा पहाड़, निकली चुहिया. ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी की मांग करके अन्ना टीम ने सरकार की मुश्किलें आसान कर दी थीं और ख़ुद को राजनीतिक चालबाज़ियों के दलदल में धकेल दिया था. वह भी तब, जब अन्ना को राजनीतिक लोगों पर न तो भरोसा है और न ही वह उन्हें अपने मंच पर आने देते हैं. इसके बाद सरकार और तथाकथित सिविल सोसायटी के सदस्यों की नौ बैठकें हुईं. दो–तीन बैठकों के बाद ही अन्ना टीम को यह महसूस हो गया कि उन लोगों को सरकार ने बेवकूफ़ बना दिया. शुरुआत में जिन 40 बिंदुओं वाले एजेंडे के साथ सिविल सोसायटी के सदस्य बैठक में गए थे, उनमें से कुछेक को छोड़कर सरकारी सदस्यों ने किसी भी प्वाइंट पर सहमति नहीं दी. सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं मसलन, लोकपाल की नियुक्ति, उसे हटाने के तरीक़े, जन शिकायत, प्रधानमंत्री एवं न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने जैसे मुद्दे पर तो बिल्कुल भी सहमति नहीं बनी. अब, जबकि ज्वाइंट कमेटी की बैठकें ख़त्म हो गई हैं और गेंद अब पूरी तरह से सरकार और राजनीतिक दलों के पाले में चली गई है, अन्ना ने एक और अनशन की चेतावनी दी है. उन्होंने 16 अगस्त तक का अल्टीमेटम दे दिया है. बहरहाल, 16 अगस्त और उसके बाद क्या होगा, इसका तो इंतज़ार जनता को रहेगा ही, लेकिन इस बीच का समय अन्ना और उनकी टीम के लिए आत्ममंथन का है, चिंतन का है. अपनी ग़लतियां ढूंढने, उसे स्वीकारने और सुधारने का है. यह इसलिए भी ज़रूरी है, ताकि अन्ना की दूसरी लड़ाई (आंदोलन) का हश्र रामदेव के आंदोलन की तरह न हो.

ग्रामीण भारत ग़ायब है

अन्ना के पूरे आंदोलन को देखने पर पता चलता है कि इसमें शहरी मध्य वर्ग और युवा ज़्यादा संख्या में शामिल हैं. इस आंदोलन में भारत के 6 लाख से ज़्यादा गांवों का प्रतिनिधित्व शायद ही दिखता है. इस आंदोलन से किसानों, मज़दूरों एवं आदिवासियों की उपस्थिति नदारद है यानी अन्ना टीम अपने आंदोलन में ग्रामीण भारत की भागीदारी की ज़रूरत नहीं समझती. शायद तभी इसके लिए वह अपनी तरफ़ से कोई कोशिश करती नहीं दिख रही है.

फेसबुकिया क्रांति का भरोसा

इंडिया अगेंस्ट करप्शन के झंडे तले चल रहे इस आंदोलन की झलक आपको सड़क से ज़्यादा इंटरनेट, फेसबुक और एसएमएस पर दिखेगी. फेसबुक और एसएमएस के ज़रिए लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है. ज़ाहिर है, यह नए ज़माने का आंदोलन है तो तरीक़ा भी नया चुना गया है. अब मशाल की जगह मोमबत्ती ने ले ली है. आंदोलन की गति सड़क से ज़्यादा इंटरनेट, फेसबुक और एसएमएस के सहारे तेज़ करने की कोशिश की जा रही है. इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सोचने की बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी की पहुंच किस तक है और कहां तक है. इसका सीधा अर्थ है कि इस आंदोलन के एजेंडे में गांव–देहात के लोगों की सहभागिता की बात शामिल ही नहीं थी.

विकल्प देने में असफल

अन्ना ने राजनीति और राजनेताओं को भ्रष्ट कहा, गंदा बताया, लेकिन उसका विकल्प क्या हो सकता है, वह यह नहीं बताते. अन्ना टीम कहती है कि अगर कांग्रेस जन लोकपाल का विरोध करे तो जनता उसे वोट न दे. अगर भाजपा जन लोकपाल का विरोध करे तो जनता उसे वोट न दे. अब सवाल यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही पार्टियां जन लोकपाल का विरोध करती हैं तो जनता फिर किसे वोट दे?

मज़बूत संगठन का अभाव

अन्ना और उनकी टीम ने अपने आंदोलन के पहले और बाद में भी जिस एक मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, वह था एक मज़बूत संगठन का निर्माण. पूरा आंदोलन शहरी मध्य वर्ग, वह भी कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित रहा. इसमें भी मीडिया की भूमिका ज़्यादा रही. जिन शहरों में आंदोलन की गूंज पहुंची, लोग इकट्ठा हुए. वहां इस टीम के साथ कुछ स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए थे. और ये लोग भी स्वत: स्फूर्त या मीडिया के ज़रिए ही इस आंदोलन से जुड़े, न कि अन्ना टीम ने उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोई कोशिश की थी और अब भी कोई ऐसी कोशिश होती नहीं दिख रही है. अन्ना टीम यह मानकर चल रही है कि मीडिया ख़ुद जनता को उनके साथ जोड़ देगा.

ज्वाइंट कमेटी की मांग बेवकूफ़ी

क्या अन्ना टीम यह मानकर चल रही थी कि वह सरकार से अपनी मांगें मनवा लेगी, आख़िर इस विश्वास की वजह क्या थी? जंतर–मंतर पर अनशन के पहले दिन ही अन्ना समर्थकों ने नेताओं के साथ जो सलूक किया था, उसे देखते हुए एक भी कांग्रेसी नेता जंतर–मंतर पर नहीं पहुंचा. अन्ना को जब नेताओं से इतनी ही चिढ़ थी तो फिर वह कैसे उन्हीं नेताओं के साथ कमेटी में बैठने को राज़ी हो गए, उन्होंने कैसे यह विश्वास कर लिया कि ये नेता उनके कहे मुताबिक़ एक अच्छा जन लोकपाल बिल बना देंगे? ज़ाहिर है, ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी की मांग करके अन्ना टीम जनता से मिले समर्थन का सही इस्तेमाल कर सकने में असफल साबित हुई.

कमेटी से विपक्ष ग़ायब

अन्ना टीम की शायद यह सबसे बड़ी ग़लती थी कि उसने ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी में न तो अपनी ओर से और न सरकार की ओर से विपक्ष के किसी नेता को शामिल कराया. अगर अन्ना अपनी ओर से ही विपक्ष के नेता को कमेटी में शामिल करते तो शायद उन्हें आज यह दिन नहीं देखना पड़ता. फिर लोकपाल पर विपक्ष का रुख़ भी तुरंत पता चल जाता.

नेताओं से दुर्व्यवहार

लोकपाल ड्राफ्ट पर अब कैबिनेट और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा होनी है यानी अब लोकपाल बिल को संसद और राजनीति के गलियारे से निकल कर ही जनता के बीच जाना है और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था भी है. लेकिन अन्ना और उनकी टीम शायद इस सच को जानते हुए भी झुठलाने की कोशिश कर रही थी. इसी का नतीजा था कि अन्ना ने अपने मंच पर किसी नेता को नहीं आने दिया और जिसने आने की कोशिश भी की, उसे बड़े बेआबरू होकर वहां से जाना पड़ा. हालांकि यहां भी वही हाल था कि गुड़ खाएं, गुलगुले से परहेज़. राजघाट पर अन्ना के एक दिवसीय अनशन में सीपीआई (माले) की एक महिला नेता को ज़बरदस्ती मंच से उतारा गया, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की ही इकाई आइसा के सदस्यों को मंच पर बुलाकर उनसे गाना गवाया गया और बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के राजा बुंदेला को मंच पर आने दिया गया.

मांग ठुकराने के बावजूद बैठक में हिस्सा

एक अहम सवाल यह है कि जब दूसरी–तीसरी बैठक के दौरान ही अन्ना टीम को यह पता लग गया कि सरकार की मंशा एक अच्छा लोकपाल क़ानून बनाने की नहीं है और सिविल सोसायटी की मांग को लगातार अनसुना किया जा रहा है तो फिर बैठक में जाने की ज़रूरत क्या थी? क्यों नहीं उसी वक़्त ये सारे लोग कमेटी से इस्तीफ़ा देकर जनता के बीच गए? क्या इन्हें भरोसा था कि अंतिम बैठक तक ये सरकार को समझा पाने में सफल हो जाएंगे?

सदस्यों का विवादास्पद चयन

जब ज्वाइंट कमेटी में सिविल सोसायटी की ओर से सदस्यों के चयन की बारी आई, तब भी अन्ना टीम ने अपनी मर्ज़ी चलाई. इस प्रक्रिया में इन लोगों की ओर से न तो जनता का मत जानने की कोशिश हुई और न जनता को इसमें शामिल किया गया. मंच से जिस तरह 5 नामों की घोषणा हुई, वह ऐसा लग रहा था मानों ये पांच नाम पहले से तय थे और बस इन नामों की घोषणा एक औपचारिकता भर थी. चूंकि जनता जीत के उत्साह में थी, इसलिए उस वक़्त किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया. लेकिन यह तर्क कि इन्हीं पांच लोगों ने जन लोकपाल बिल को ड्राफ्ट किया है इसलिए यही नाम उचित हैं, कहीं न कहीं देश के बाक़ी ईमानदार और बुद्धिजीवी लोगों का उपहास ही था. बाद में भूषण पिता–पुत्र को लेकर जिस तरह की बातें सामने आईं, वे कहीं न कहीं अन्ना टीम के लिए भारी ही साबित हुईं. इस वजह से सरकार को अन्ना टीम पर हमला बोलने का मौक़ा भी मिला.

विरोधाभासी बयानों वाली टीम

रामदेव का सत्याग्रह 4 जून को शुरू हुआ. यह पहले से तय था कि अन्ना 5 जून को रामलीला मैदान पहुंचेंगे, लेकिन 4 जून को ही स्वामी अग्निवेश का बयान आता है कि रामदेव के मंच पर सांप्रदायिक लोग आ रहे हैं. अब अन्ना कहते हैं कि वहां जाने से पहले हम अपनी टीम के लोगों से बातचीत करेंगे. टीम के एक सदस्य संतोष हेगड़े अन्ना को दूसरी बार अनशन न करने की सलाह देते हैं. ज्वाइंट कमेटी की बैठकों के अलावा हेगड़े शायद ही कभी अन्ना की प्रेस कांफ्रेंस में दिखे हों. कुल मिलाकर ऊपर से एक दिखती अन्ना टीम के सदस्यों के बीच विचार और बयान के स्तर पर एकता का अभाव है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

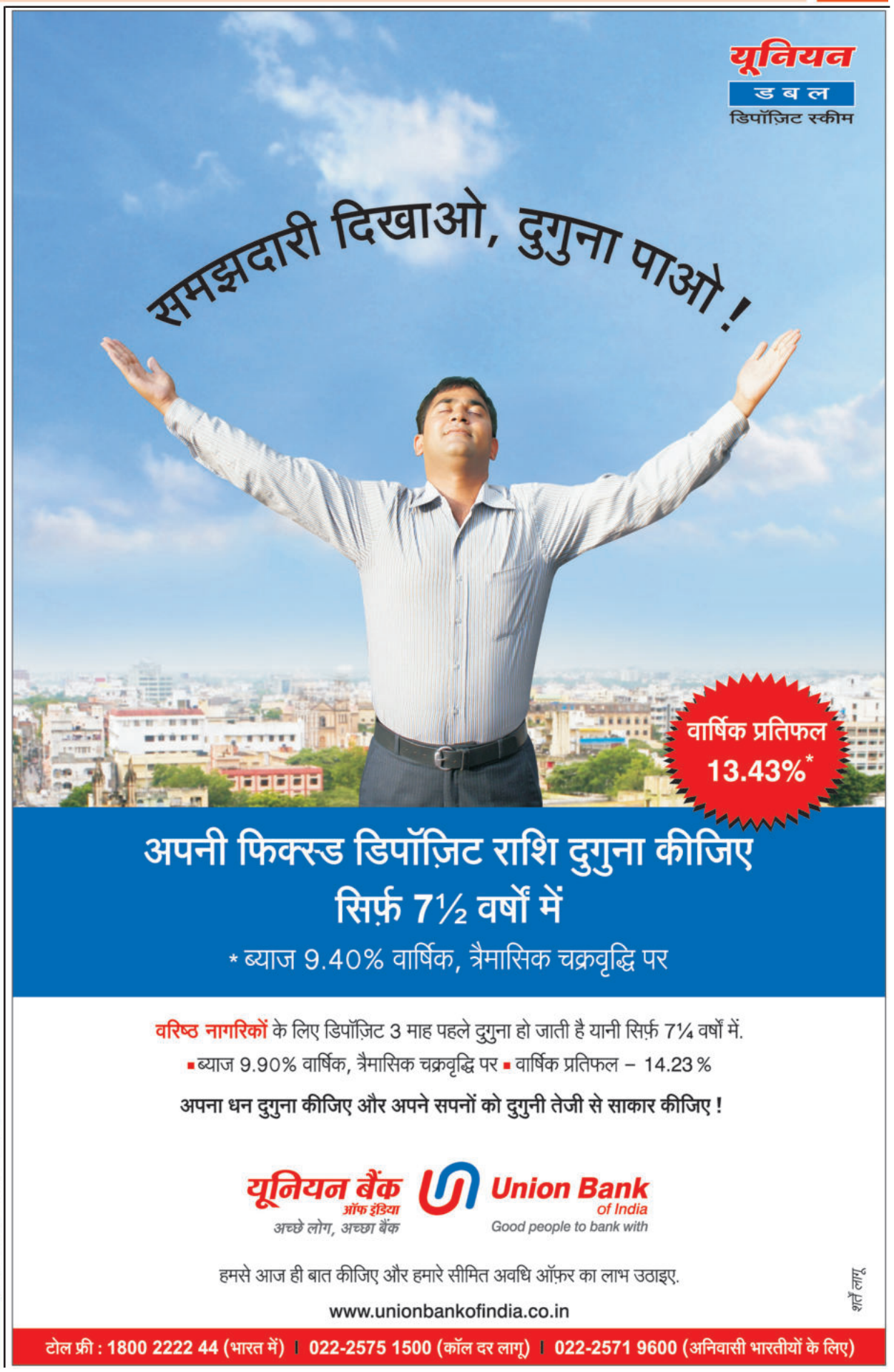

माया‌वती शासनकाल के कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिनकी तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी उन पर भी राजनीति करती नज़र आ रही है.

उत्तर प्रदेश

पीस पार्टी बनी ख़तरे की घंटी

अजय कुमार

अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव पीस पार्टी के लिए नया सवेरा ला सकता है. अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में कई बड़े दलों के लिए मुसीबत बने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद अयूब का प्रदेश में डंका बज रहा है. पार्टी किसी के लिए ख़तरा तो किसी के लिए राहत साबित हो रही. दुनिया में सिर्फ़ दो जातियों यानी अमीर और ग़रीब की धारणा वाले डॉ. अयूब हमेशा ग़रीबों की वकालत करते रहे हैं, लेकिन इसे इत्तेफ़ाक़ ही कहा जाएगा कि उनकी पार्टी में धन्ना सेठों की दस्तक सुनाई देती है. पीस पार्टी धन्ना सेठों के सहारे अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी करना चाहती है, वहीं वोट बटोरने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को अपने साथ खड़ा देखना चाहती है. दोनों ही कौमों में वह राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग–समाज को साथ लेकर चलने पर विश्वास करती है. मुसलमानों में अंसारी और पसमांदा समाज, हिंदुओं में दलितों एवं पिछड़े वर्ग के अलावा अपरकास्ट होते हुए भी राजनीतिक रूप से पिछड़े वैश्य–कायस्थ समाज को वह अपनी ताक़त बनाना चाहती है. लक्ष्य किसी भी तरह 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है. इसके लिए प्रदेश के कोने–कोने में पार्टी की जनसभाएं और बैठकें हो रही हैं. लोगों को जोड़ने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. सत्ता में घुसपैठ का समीकरण बनाने को आतुर पीस पार्टी ने कई छोटे–छोटे दलों को साथ लेकर लोक क्रांति मोर्चा भी बना लिया है. मोर्चे में राष्ट्रीय लोकदल, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, जनवादी पार्टी, भारतीय लोकहित पार्टी के अलावा अति पिछड़ा वर्ग महासंघ, मोमिन कांफ्रेंस जैसे संगठन भी शामिल हैं. डॉ. अयूब पूर्वांचल के बाद अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं. जनसभाओं के लिए उन ज़िलों का चयन ख़ासकर किया जा रहा है, जिन्हें दीगर पार्टियों के दिग्गज अपना गढ़ समझते हैं. पिछले दिनों राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के वर्चस्व वाले बागपत में जनसभा करने के बाद बरेली, मेरठ, इटावा एवं बुलंदशहर आदि ज़िलों में सभाएं करके पार्टी ने यह भ्रम तोड़ दिया कि वह पूर्वांचल तक ही सीमित है. डॉ. अयूब की कुछ जनसभाओं से लगभग तय हो गया कि मुस्लिम वोटों के हिसाब से उपजाऊ ज़मीन माने जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार कांग्रेस, भाजपा, सपा और बसपा के लिए पीस पार्टी की चुनौती आसान नहीं होगी. यही वजह है कि सपा और बसपा पीस पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रही हैं. समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि पीस पार्टी भाजपा और बसपा द्वारा खड़ा किया गया भस्मासुर है, जो मुसलमानों की एकता को तार–तार कर देना चाहता है.

दरअसल, पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब के बसपा का मुस्लिम चेहरा समझे जाने वाले दिग्गज नेता नसीमुद्दीन से अच्छे संबंध हैं. इसी बात का फ़ायदा उठाकर सपा नेता पीस पार्टी को बसपा की देन बताते हैं. यही नहीं, वह यह भी साबित करने में जुटी है कि मायावती हिंदुत्व की भाजपा से भी बड़ी खेवनहार हैं. तर्क यह दिया जा रहा है कि जिस लखनऊ को इतिहास में नवाबों के शहर की उपमा से नवाजा गया था और देश–विदेश में इसकी यही पहचान थी, उस शहर की तस्वीर मायाराज में ऐसी हो गई है कि मानों यहां के मानस में बाबा साहब और कांशीराम आदि बसते हों. पहले लोग लखनऊ की जमीं पर क़दम रखते ही इमामबाड़ा, भूलभुलैया, पिक्चर गैलरी, चौक आदि देखना चाहते थे, लेकिन आज जो लखनऊ घूमने आता है, उसे अंबेडकर पार्क, समतामूलक चौराहा, परिवर्तन चौक, अंबेडकर मैदान एवं स्मृति विहार जैसे स्थान ज़्यादा आकर्षित करते हैं. इन नए दर्शनीय स्थलों ने लखनऊ की पुरानी यादों को समेटने में अहम भूमिका निभाई है. मायावती शासनकाल के कुछ बिंदु ऐसे हैं, जिनकी तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी उन पर भी राजनीति करती नज़र आ रही है. मायावती ने अपने क़रीब चार साल के शासन में कभी हिंदू–मुस्लिम कार्ड नहीं खेला. अयोध्या मसला हो या फिर बरेली के सांप्रदायिक दंगे अथवा अन्य कोई घटना, मायावती ने क़ानून व्यवस्था तोड़ने वालों पर ही सख्ती की. लेकिन विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है, इसलिए सपा इसे सही कैसे ठहरा सकती है. वह तो अभी भी हिंदू–मुस्लिम और मंदिर–मस्जिद के विवाद में ही उलझी है. इसी सोच के तहत वह बसपा और भाजपा पर पीस पार्टी को संरक्षण देने का आरोप लगा रही है. उधर पीस पार्टी की बढ़त का ग्राफ जारी है. लोकसभा चुनाव में पीस पार्टी को एक फ़ीसदी वोट मिला था, ज़िला पंचायत चुनाव में मऊ में अध्यक्ष पद पर इसका उम्मीदवार विजयी रहा और 72 ज़िला पंचायत सदस्य जीते. मुज़फ़्फ़रनगर में पीस पार्टी का ब्लॉक प्रमुख जीता. पीस पार्टी दूसरे के लिए भले ही ख़तरा हो, लेकिन विरोध के स्वर इस पार्टी में भी फूटने लगे हैं. भ्रष्टाचारियों का नार्को टेस्ट कराने की बात करने वाले डॉ. अयूब अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए किसी भी दल या व्यक्ति से समझौते को तैयार दिखते हैं. पिछले दिनों पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह का पार्टी से जुड़ना काफी चर्चा में रहा. यशपाल सिंह की पत्नी गीता सिंह भू–माफ़िया के नाम से मीडिया में काफी चर्चा बटोर चुकी हैं. हाल में पूर्वांचल के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के पार्टी से जुड़ने की चर्चा गर्म रही. मुसलमानों की हमदर्द बनकर सामने आई पीस पार्टी में इन दिनों इस बात को लेकर भी तनातनी है कि तमाम सीटों पर ब्राह्मण और क्षेत्रीय उम्मीदवारों को ही क्यों चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है. इसके चलते कई मुस्लिम नेताओं ने, जो पार्टी के गठन के समय से जुड़े हुए थे, किनारा कर लिया है. इन सब बातों से बेफ़िक्र पीस पार्टी रैली पर रैली कर रही है. उसे जहां एक ओर लोकजन शक्ति पार्टी के रामविलास पासवान का सहयोग हासिल है, वहीं ओमप्रकाश राजभर भी इन रैलियों में बराबर दिखते रहे, लेकिन दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली पीस पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव के वक़्त इन्हीं वर्गों से किनारा कर लेने से वह आजकल कुछ नाराज़ हैं.

समाजवादी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के प्रांतीय अध्यक्ष हाजी रियाज़ अहमद आरोप लगाते हैं कि पीस पार्टी को रैलियों के लिए भाजपा और बसपा पैसा दे रही है. यह रकम प्रति माह 6 करोड़ रुपये के क़रीब होने की बात कही जा रही है. उनका कहना है कि एक सर्जन के पास इतना पैसा कहां से आ सकता है. इसके जवाब में पीस पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कोआर्डीनेटर मुहम्मद इसराइल कहते हैं कि पीस पार्टी की रैलियों में जुटी भीड़ देखकर सपा नेता बौखला गए हैं. वहीं डॉ. अयूब कहते हैं कि इल्ज़ाम लगता है कि हम भाजपा को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं. लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़े, एक जगह भी भाजपा नहीं जीत पाई. पीस पार्टी के हौसलों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में 350 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का दावा करती है. कुछ राजनीतिक दल पीस पार्टी की बढ़ती ताक़त को देखकर इससे गठजोड़ की कोशिश में हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष डॉ. अयूब किसी बड़े दल से समझौता करके अपना कद कम नहीं करना चाहते. पार्टी ने कुछ छोटे–छोटे, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अपने साथ जोड़ा है. पीस पार्टी की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि वह मुस्लिमों से अधिक हिंदू प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने को तरजीह देती है, ताकि मुसलमानों के साथ–साथ हिंदुओं के भी वोट उसे मिल जाए. यह समीकरण पीस पार्टी के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है. पीस पार्टी उसी फ़ार्मूले के तहत सत्ता के क़रीब पहुंचना चाहती है, जिस तरह बसपा आई थी. डॉ. अयूब का कहना है कि असली मक़सद जनता के सामने मज़बूत विकल्प पेश करना है. गठबंधन के नज़रिए से पीस पार्टी के लिए कोई दल अछूत नहीं है. उन्होंने भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी, इंडियन जस्टिस पार्टी, लोकजन शक्ति पार्टी, भारतीय लोकहित पार्टी एवं मोमिन कांफ्रेंस के अपने साथ होने का दावा किया. पार्टी गठजोड़ ज़रूर कर रही है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़िलेवार प्रस्तावित रैलियों में वह अकेली ही रहेगी.

feedback@chauthiduniya.com

विरोधी मेरी हत्या करना चाहते हैं : अयूब

पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अयूब पिछले दिनों फ़ैज़ाबाद में एक सड़क हादसे में घायल हो गए, जिसमें उन्हें गंभीर चोटे आईं. पुलिस भले ही इसे हादसा बता रही हो, लेकिन अयूब इसे उन सांप्रदायिक शक्तियों की साजिश बताते हैं, जिनसे उन्हें जान का ख़तरा महसूस होता है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं है. पेश हैं बातचीत के मुख्य अंश:–

फ़ैज़ाबाद सड़क हादसे से आपका मिशन 2012 प्रभावित हुआ है...

सड़क हादसे में मेरा घायल होना अकस्मात या संयोगवश नहीं, बल्कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी. इस संबंध में फ़ैज़ाबाद शहर कोतवाली में मुक़दमा दर्ज करा दिया गया है. जिस बिना नंबर वाली स्कार्पियों ने मेरी फार्चुनर गाड़ी को टक्कर मारी, वह लखनऊ से ही मेरे पीछे लगी थी.

आपके ख़िलाफ़ इस तरह की साजिश कौन रच सकता है?

पीस पार्टी मानववादी पार्टी है और सांप्रदायिकता, जातिवादी एवं भ्रष्टाचार की विरोधी है. यह साजिश ऐसी ही शक्तियों द्वारा रची गई. हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से सुरक्षा का मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस ओर गंभीरता से नहीं सोचा.

आप इस मामले में सरकार से कैसा सहयोग चाहते हैं?

घटना की उच्चस्तरीय जांच और दोषियों को बेनकाब करने के लिए मैंने केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों को पत्र लिखा है.

आपकी पार्टी में परिपक्व एवं कद्दावर नेताओं की कमी है, जबकि चुनाव प्रचार के लिए ऐसे नेताओं का होना ज़रूरी है...

जीत नेताओं से नहीं, विचारधारा से होती है. हमने पिछले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया था और हमारा प्रदर्शन सुधरता जा रहा है. अगर जीत का आधार नेता ही होते तो भाजपा जैसे दल आज विपक्ष में न बैठे होते.

पार्टी जिन लोगों को टिकट दे रही है, उनमें कई बाग़ी हैं. कहीं वे आगे चलकर पाला न बदल लें...

नहीं, हम उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं, जो हमारी विचारधारा से इत्तेफ़ाक़ रखते हैं. कई राजनीतिक दलों के नेता हमारी पार्टी में आ रहे हैं. इसके पीछे हमारी लोकप्रियता है.

कहा जा रहा है कि पीस पार्टी के मैदान में आने से मुस्लिम वोटों का विभाजन होगा...

मुस्लिम वोटों की सियासत कर रहे दलों को भारी नुक़सान पहुंचेगा, ख़ासकर समाजवादी पार्टी को. यह भ्रम जानबूझ कर फैलाया जा रहा है. ऐसा कुछ होने वाला नहीं. ऐसी बातें वे ही दल कर रहे हैं, जिन्होंने कई दशकों तक मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया. हम अपना काम कर रहे हैं. इससे किसे फ़ायदा होगा और किसे नुक़सान, यह देखना हमारा काम नहीं है. जनता जिसे चाहेगी, उसे चुनकर भेजेगी. राजनीति में कोई छोटा–बड़ा नहीं होता. कौन छोटा है और कौन बड़ा, यह दल नहीं, जनता तय करती है. अबकी जनता ने पीस पार्टी को देखने का मन बना लिया है. उत्तर प्रदेश में अगली सरकार हमारे दख़ल के बिना नहीं बन पाएगी.

यूडीएफ और नेलोपा भी मैदान में

पीस पार्टी की तर्ज पर कुछ अन्य मुस्लिम नेता भी अपनी ताक़त बढ़ाने को उतावले दिख रहे हैं. यूडीएफ के मुखिया डॉ. यूसुफ कुरैशी क़रीब सौ सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं, जिनमें 60 पश्चिमी क्षेत्रों में और 40 पूर्वांचल में होंगे. अपनी कयादत-अपनी सियासत के नारे पर यूडीएफ मुस्लिम प्लस अन्य बिरादरियों की गणित समझा कर चुनावी समीकरण बनाने में जुटी है. नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के मोहम्मद अरशद भी काफी समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठकों का सिलसिला छेड़े हुए हैं. अपने साथ भारतीय समानता पार्टी, जनसत्ता पार्टी एवं वंचित जमात पार्टी जैसे दलों के होने की बात कहने वाले अरशद अक्सर पूर्व सपा नेता एवं सांसद अमर सिंह के लोकमंच के कार्यक्रमों में भी नज़र आ जाते हैं. क्षेत्रीय स्तर पर शुरू हुई छोटे दलों की सरगर्मियों से बड़े दलों की नींद उड़ गई है. समय की नज़ाकत भांप कुछ बड़े दल इनसे हाथ मिलाने को लालायित दिखते हैं. राहुल गांधी तो यह बात खुलकर कह चुके हैं. इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने साफ़ कर दिया कि सियासी दोस्ती के लिए राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी पार्टी ने दरवाजे खोल रखे हैं. प्रदेश इकाई ने गठबंधन करने का अधिकार पूरी तरह पार्टी महासचिव राहुल गांधी को दे दिया है.

बीते 21 जून को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह एवं सदस्य शैयदा बिलग्रामी इमामी ने भी घटनास्थल और भजनपुर गांव पहुंच कर हालात का जायज़ा लिया.

फारबिसगंज गोली कांड

नेता सिर्फ़ ज़ख़्म कुरेदते हैं, मरहम नहीं देते

सरोज सिंह

फारबिसगंज के भजनपुर में अजीब बेचैनी बिखरी पड़ी है. पुलिसिया ख़ौफ़ के साये में यहां सांस लेते लोगों की ज़ुबान बंद है, पर पटना और दिल्ली से आए नेता उनके मुंह में उंगली डाल उनसे बुलवाने की रोजाना कोशिश करते हैं. अपने अजीज़ों को खोने वाले लोगों की आंखें न्याय की आस में रोज खुलती है और रोज बंद होती है, पर इंतज़ार ख़त्म नहीं हो रहा है. गांव के मज़दूरों की मज़दूरी और किसानों की खेती चौपट हो गइ है. एक तरफ़ भूख से कुलबुलाते बच्चे तो दूसरी तरफ़ मौत का ख़ौफ़. हर कोई आने वाला भजनपुर के लोगों को दर्द से छुटकारा दिलाने के बजाय उसे कुरेद कर बढ़ा जाता है और अपनी राजनीति चमका जाता है.

पुलिस की गोली से मारी गई सजमीना ख़ातून की सास वृद्ध बीबी जसीरा कहती हैं, मेरा बेटा ग्लूकोज़ फैक्ट्री में काम करता था. सजमीना जब हो–हल्ला सुनकर पति को देखने जा रही थी, तभी वह पुलिस की गोली की शिकार हो गई. अब मेरे ही सहारे बच्चों की परवरिश टिकी है. बच्चे क्या खाएंगे, इसके भी अब लाले पड़े हैं. घटना के शिकार अबोध शोएब उर्फ नौशाद के पिता सिद्दक अंसारी कहते हैं, मेरा सब कुछ लुट गया. कश्मीर में नौकरी करता था. घटना के बाद वहां से यहां आया. पत्नी रेहाना ख़ातून का इलाज भी नहीं हो पा रहा है. वह भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, पता नहीं क्या होगा. मां के बग़ैर बच्चों की क्या हालत होती है, यह तो सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है. रोजी–रोज़गार और खेती–बाड़ी सब कुछ चौपट हो गया है. दाने–दाने के लाले पड़े हैं.

गोलीकांड में मारे गए मुस्तफ़ा अंसारी के घर तो मातम पसरा हुआ है. घायल तजमून अंसारी, इकराम, इबादुल एवं रईस आदि के घरों में भी वीरानी छाई हुई है. हर तरफ़ भय का माहौल है और पुलिसिया ख़ौफ़ अब तक लोगों के मन से नहीं हटा है. गांव की हालत यह हो गई है कि क्या मर्द और क्या औरत, कोई भी अपने घर में नहीं रहना चाहता. उन्हें यह आशंका खाए जा रही है कि किस दिन, किस वक़्त कोई नया ज़ुल्म न हो जाए. हालांकि गृह सचिव आमिर सुबहानी के दौरे के बाद लोगों में न्याय का भरोसा जगा था, लेकिन घटना हुए एक पखवाड़ा बीतने के बावजूद अब तक पीड़ितों को न्याय न मिलना हैरानी की बात है. राजनीतिक दलों के लिए भजनपुर की घटना लॉटरी की तरह है, वे पीड़ितों के दर्द की आंच पर राजनीतिक रोटी सेंक अपनी क़िस्मत चमकाने में लगे हैं.

बीते 21 जून को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्लाह एवं सदस्य शैयदा बिलग्रामी इमामी ने भी घटनास्थल और भजनपुर गांव पहुंच कर हालात का जायज़ा लिया. दोनों पक्षों से गहनता से विस्तारपूर्वक पूछताछ हुई. हबीबुल्लाह ने यहां तक कहा कि राज्य सरकार द्वारा भेजी गई रिपोर्ट से आयोग संतुष्ट नहीं था, इसलिए आयोग को भजनपुर कांड की जांच स्वयं करनी पड़ी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में गोली चलाकर किसी भी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता. मामूली सड़क विवाद को बग़ैर गोली चलाए ही सुलझाया जा सकता था, लेकिन प्रशासन ने गोली चलाकर एक बड़ा जुर्म किया है.

गांव की हालत यह हो गई है कि क्या मर्द और क्या औरत, कोई भी अपने घर में नहीं रहना चाहता. उन्हें यह आशंका खाए जा रही है कि किस दिन, किस वक़्त कोई नया ज़ुल्म न हो जाए. हालांकि गृह सचिव आमिर सुबहानी के दौरे के बाद लोगों में न्याय का भरोसा जगा था, लेकिन घटना हुए एक पखवाड़ा बीतने के बावजूद अब तक पीड़ितों को न्याय न मिलना हैरानी की बात है.

हबीबुल्लाह ने कहा कि यहां जो कारखाना लगाया जाना है, उससे गांव और शहर का ही भला होगा, लेकिन कारखाना मालिकों को भी चाहिए कि वे गांव के लोगों से समन्वय बनाकर ही किसी काम को करें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आयोग इस प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए भी अनुशंसा करेगा. उधर नीतीश कुमार ने इस मामले में साफ कर दिया है कि क़ानून अपना काम करेगा और किसी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कांग्रेस, लोजपा और राजद मानने को तैयार नहीं हैं. कई मुस्लिम संगठनों ने भी विरोध जताया हैं. फिल्मकार महेश भट्ट तो इस मामले को लेकर सोनिया गांधी के दरबार तक चले गए. लगता है, इस घटना को लेकर सारा विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है.

नेता प्रतिपक्ष अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई सरकार इतनी संवेदनहीन भी हो सकती है. मासूमों का ख़ून बहा, ग़रीबों का ख़ून बहा, पुलिस वालों ने घायल के चेहरे पर चढ़कर नाच किया और सरकार पीड़ितों के आंसू पोंछने के बजाय न्यायिक जांच की रट लगा रही है. दोषी कौन है, सब जान रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिले. कांग्रेस की रंजीता रंजन कहती हैं, हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं. कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाएगी. रंजीता मानती हैं कि भजनपुर में जो कुछ हुआ, वह किसी भी सभ्य समाज में नहीं होता है. पुलिस की गोली से अगर सात महीने का बच्चा मरता है तो सारी कहानी समझी जा सकती है.

लोजपा प्रमुख राम विलास पासवान कहते हैं कि बिहार सरकार भाजपा के दबाव में दोषियों को बचा रही है, लेकिन लोजपा ने संकल्प लिया है कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता, संघर्ष जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि मुसलमानों की हितैषी बनने का नाटक करने वाली नीतीश सरकार का चेहरा इस घटना से बेनकाब हो चुका है. बिहार के मुसलमान इस अपराध के लिए नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे.

feedback@chauthiduniya.com

खाद्यान्न माफ़ियाओं ने दी हवा!

फारबिसगंज शहर के बियाडा औद्योगिक परिक्षेत्र स्थित ग्लूकोज़ व स्टार्च कंपनी और सुंदरम इंटरनेशनल फैक्ट्री भजनपुर गोली कांड के पीछे खाद्यान्न माफ़ियाओं के बंद हो रहे काले दरवाज़े भी हो सकते हैं. कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि विवादित सड़क से ही फैक्ट्री परिसर से सटे एफसीआई गोदाम से उठने वाले अनाज को खाद्यान्न माफ़िया सरगना सुरक्षित रास्ते से निर्धारित स्थल यानी क्षेत्र की कई फ्लोर मिलों एवं गोदामों में पहुंचाते थे. रास्ता बंद होने के कारण भजनपुर के ग्रामीणों को कम दिक्कत होती, बल्कि खाद्यान्न माफ़ियाओं को ज़्यादा दिक्कत होने की आशंका थी. बताया जाता है कि खाद्यान्न माफ़ियाओं को लगा कि अगर यह रास्ता बंद हो जाएगा तो उन्हें भारी नुक़सान हो सकता है. यही वजह रही कि इन लोगों ने पहले से ही नाराज़ ग्रामीणों के विरोध को हवा देना शुरू किया. माफ़ियाओं ने ख़ुद सामने आना उचित नहीं समझा. नतीजा यह हुआ कि पुलिस फायरिंग में चार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. लोगों का कहना है कि जांच के दायरे में खाद्यान्न माफ़ियाओं के नेटवर्क को भी रखा जाना चाहिए, ताकि घटना के कारणों का सही आकलन हो सके.

एस सोनी
feedback@chauthiduniya.com

अस्पतालों में ग़रीब मरीजों का इलाज होता ही नहीं है. सिर्फ़ सरकारी नियमों की ख़ानापूर्ति करके कमाई की जा रही है.

नागपुर

मरीज़ का शोषण, अस्पताल का पोषण

स्वास्थ्य सेवाओं का भी 90 फ़ीसदी निजीकरण कर दिया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं को चैरिटी के तहत मान्यता देते हुए सरकार ने बड़े-बड़े धन्ना सेठों और कारपोरेट समूहों को अस्पताल बनाने के लिए सस्ते दामों पर ज़मीन और अन्य सुविधाएं तो मुहैया करा दीं, लेकिन इसका लाभ ग़रीबों को नहीं मिल पा रहा है.

अंजीव पांडेय

देश के विकसित राज्यों में एक महाराष्ट्र में उन तमाम बड़े अस्पतालों की हालत ख़राब है, जो दावा करते हैं कि उनके यहां ग़रीबों के लिए इलाज की मुकम्मल व्यवस्था है, जबकि इसके उलट इन बड़े कारपोरेट अस्पतालों में ग़रीबों के लिए कोई जगह नहीं है. कमाल की बात तो यह है कि अस्पतालों को ज़मीन सरकार ने ही दी है. बदले में सरकार को वादा किया गया था कि अस्पताल में ग़रीबों का इलाज मुफ्त किया जाएगा. सरकारी नियम-क़ानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए ये अस्पताल सिर्फ़ धन की उगाही में लगे हैं और ग़रीब इलाज के अभाव में सड़कों पर मरने के लिए मजबूर हैं तथा सरकार आंखें बंद करके सो रही है.

दरअसल इन अस्पतालों में ग़रीब मरीजों का इलाज होता ही नहीं है. सिर्फ़ सरकारी नियमों की खानापूर्ति करके कमाई की जा रही है. इन अस्पतालों में निरंकुशता का आलम यह है कि यहां लाश पड़ी रहती है, लेकिन वह तब तक परिवारीजनों के हवाले नहीं की जाती, जब तक बकाया राशि अस्पताल में जमा नहीं कर दी जाती. आपरेशन के मामले में तो स्थिति और भी भयावह है. कितना भी जटिल और ज़रूरी आपरेशन हो, मगर वह तभी किया जाता है, जब मरीज के परिवारीजन उसके लिए 3-4 लाख रुपये अस्पताल में जमा कर देते हैं. जिस तरह किसी होटल में कमरा लेने पर एडवांस जमा करना पड़ता है, उसी प्रकार इन अस्पतालों में भी सब कुछ एडवांस में होता है. अगर एडवांस न दिया जाए तो मरीज को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया जाता है. जब मरीज को लेकर उसके परिवारीजन किसी सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां की दुर्दशा से दो-चार होना पड़ता है. एक सुनियोजित साजिश के तहत हर मूलभूत नागरिक अधिकार और सुविधा का निजीकरण किया जा रहा है. इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं का भी 90 फ़ीसदी निजीकरण कर दिया गया है. स्वास्थ्य सेवाओं को चैरिटी के तहत मान्यता देते हुए सरकार ने बड़े-बड़े धन्ना सेठों और कारपोरेट समूहों को अस्पताल बनाने के लिए सस्ते दामों पर ज़मीन और अन्य सुविधाएं तो मुहैया करा दीं, लेकिन इसका लाभ ग़रीबों को नहीं मिल पा रहा है.

ज़िंदगी और मौत से लड़ती एक महिला का एपेंडिक्स फट गया था. उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए तत्काल आपरेशन की आवश्यकता थी. वह हॉस्टल में रहती थी. उसके स्थानीय अभिभावक की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसकी तत्काल आर्थिक मदद कर पाते. उसके पिता नागपुर से लगभग 900 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में रहते हैं. शाम सात बजे उसे दर्द उठा, हालत बिगड़ती जा रही थी और उसकी सहेलियां उसे आटो रिक्शा में लिए अस्पताल दर अस्पताल भटक रही थीं. तभी किसी पत्रकार की नज़र उन पर पड़ी. उसने उनकी व्यथा सुनी और अपने एक मित्र के अस्पताल में तत्काल उसके आपरेशन की व्यवस्था कराई.

यह कोई पहला उदाहरण नहीं है. ऐसे कई अस्पताल हैं. नागपुर में लगभग 15 चैरिटी अस्पताल हैं. धारा 41-ए और हाईकोर्ट के निर्देशों के मुताबिक़ , इन अस्पतालों में 10 फ़ीसदी आरक्षण ग़रीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए होना चाहिए और 10 फ़ीसदी आरक्षण दुर्बल वर्ग के लोगों के लिए. सरकार की ओर से दावा किया जाता है कि असिस्टेंट चैरिटी कमिश्नर को इन अस्पतालों की मानीटरिंग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है और हर माह संबंधित अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी बैठक होती है. ज़िले का सिविल सर्जन भी उसमें शामिल होता है, मगर कोई भी अधिकारी इन अस्पतालों से संबंधित क़ानूनों और मानीटरिंग की जानकारी मीडिया को बताना नहीं चाहता. सिविल सर्जन डॉ. राठौड़ तो साफ़ कहते हैं कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाइए और ढूंढ लीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकता. डॉ. राठौड़ ने तीन घंटे तक लगभग 15 बार कोशिशों के बाद फोन उठाया, लेकिन बात करने से मना कर दिया.

सिविल सर्जन डॉ. राठौड़ तो साफ़ कहते हैं कि राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाइए और ढूंढ लीजिए, मैं कुछ नहीं बता सकता. डॉ. राठौड़ ने तीन घंटे तक लगभग 15 बार कोशिशों के बाद फोन उठाया, लेकिन बात करने से मना कर दिया. जो अस्पताल चैरिटी के अंतर्गत नहीं आते, वहां भी दुर्दशा है. कई अस्पतालों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जहां पार्किंग की व्यवस्था है भी, वहां बाकायदा शुल्क लिया जाता है.

जो अस्पताल चैरिटी के अंतर्गत नहीं आते, वहां भी दुर्दशा है. कई अस्पतालों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और जहां पार्किंग की व्यवस्था है भी, वहां बाकायदा शुल्क लिया जाता है. जब कहा जाता है कि यह ग़ैर क़ानूनी है तो छोड़ दिया जाता है. अस्पतालों से निकलने वाला कचरा आसपास के इलाक़ों में बीमारी फैलने की वजह बन रहा है. एक बार तो सरकारी मेयो अस्पताल में कुत्ते एक नवजात शिशु की लाश ही खा रहे थे. कुल मिलाकर एक ओर नागपुर को हेल्थ हब बनाने की बात की जाती है, वहीं सरकार की लापरवाही के कारण चैरिटी अस्पताल वाले करोड़ों रुपये तो कमा रहे हैं, लेकिन चैरिटी के नाम पर ग़रीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... इतिहास पुरुष मनमोहन सिंह!

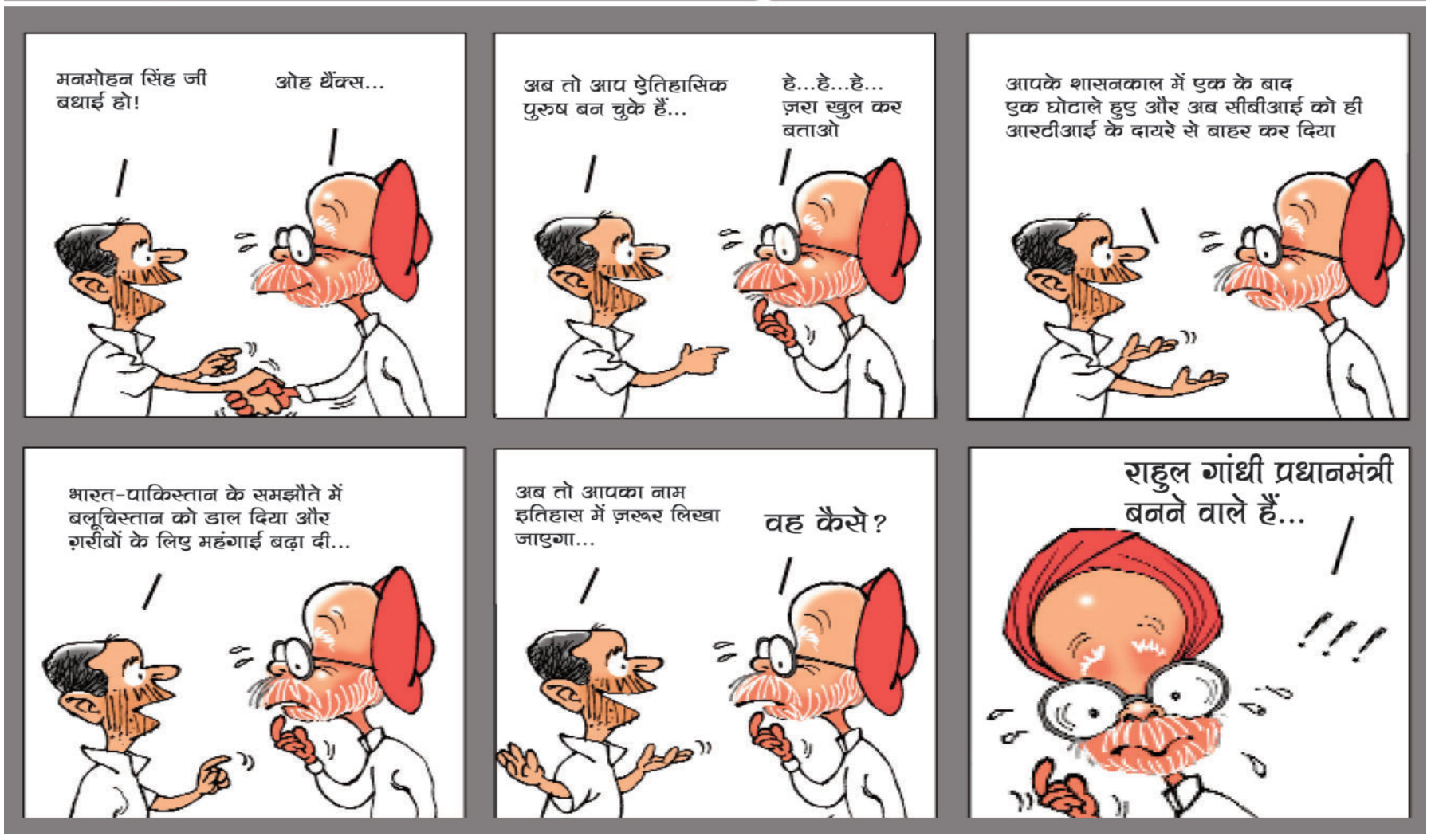

आज के बच्चे कल का भविष्य हैं. इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि उन्हें भरपेट संतुलित आहार मिले. इसके लिए सरकार को पंचायती स्तर पर प्रयास करने होंगे.

मिड डे मील की कछुआ चाल

अध्यापकों का कहना है कि कई स्कूलों में पर्याप्त बर्तन भी नहीं हैं. कम बजट की वजह से हर रोज़ किराए के बर्तन नहीं लाए जा सकते, इसलिए बच्चों को मिड डे मील के लिए अपने घरों से ही थाली, कटोरी, चम्मच और गिलास लाना पड़ता है. इसके अलावा भोजन खाने के बाद बच्चों को ख़ुद बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं. इस तरह बर्तनों की साफ़-सफ़ाई में छात्रों का घंटे भर का वक़्त बर्बाद हो जाता है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है.

फ़िरदौस ख़ान

स्कूलों में मिलने वाला दोपहर का भोजन यानी मिड डे मील भी बच्चों को कुपोषण से बचाने में सहायक साबित नहीं हो पा रहा है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-3) की रिपोर्ट के मुताबिक़, देश में तीन साल से कम उम्र के क़रीब 47 फ़ीसदी बच्चे कम वज़न के हैं. इसके कारण उनका शारीरिक विकास रुक गया है. देश की राजधानी दिल्ली में 33.1 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 60.3 फ़ीसदी, झारखंड में 59.2 फ़ीसदी, बिहार में 58 फ़ीसदी, छत्तीसगढ़ में 52.2 फ़ीसदी, उड़ीसा में 44 फ़ीसदी, राजस्थान में भी 44 फ़ीसदी, हरियाणा में 41.9 फ़ीसदी, महाराष्ट्र में 39.7 फ़ीसदी, उत्तराखंड में 38 फ़ीसदी, जम्मू-कश्मीर में 29.4 फ़ीसदी और पंजाब में 27 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण का शिकार हैं.

केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 16,380 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि 10,380 करोड़ रुपये थी. इस राशि में छह सौ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. सरकार ने मिड डे मील की डाइट मनी में भी बढ़ोत्तरी की है यानी प्राइमरी स्तर पर प्रति बच्चे 20 पैसे और अपर प्राइमरी स्तर पर 30 पैसे का इज़ाफ़ा किया गया है. प्राइमरी स्कूलों में पहले प्रति विद्यार्थी दो रुपये 69 पैसे दिए जाते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर दो रुपये 89 पैसे कर दिया गया है. इसी तरह अपर प्राइमरी के प्रति विद्यार्थी पहले 4 रुपये 3 पैसे दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 4 रुपये 33 पैसे कर दिया गया है.

अब तक प्राइमरी स्कूलों के हर बच्चे को मिड डे मील के राशन में प्रतिदिन 145 ग्राम ख़ुराक दी जाती रही है. मिडिल तक के बच्चों को क़रीब ढाई सौ ग्राम तक ख़ुराक दी जानी तय है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी मेन्यू के मुताबिक़, सप्ताह के पहले दिन 80 ग्राम चावल, 50 ग्राम गुड़ या चीनी, 15 ग्राम सोयाबीन के हिसाब से 145 ग्राम ख़ुराक दी जाएगी. दूसरे दिन पुलाव में 85 ग्राम चावल, 64 ग्राम हरी सब्ज़ी, 10 ग्राम मूंगफली, 5 ग्राम तेल के हिसाब से कुल 164 ग्राम राशन दिया जाएगा. तीसरे दिन पौष्टिक खिचड़ी में 80 ग्राम चावल, 30 ग्राम मूंग दाल, 5 ग्राम रिफ़ाइंड, 10 ग्राम तेल के हिसाब से 125 ग्राम ख़ुराक दी जाती है. चौथे दिन के दलिया में 85 ग्राम दलिया, 10 ग्राम सोयाबीन, 2 ग्राम घी, 50 ग्राम गुड़ या चीनी के हिसाब से कुल 147 ग्राम ख़ुराक बच्चों को दी जानी निर्धारित है. पांचवें दिन बच्चों को बाकली दी जाती है, जिसमें गेहूं की मात्रा 60 ग्राम, चना 30 ग्राम, घी 2 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम, आलू 50 ग्राम और हरा धनिया 10 ग्राम के हिसाब से कुल 162 ग्राम की ख़ुराक देना तय है. मिड डे मील के मानदंड के मुताबिक़, प्राइमरी के बच्चों को 12 ग्राम प्रोटीन एवं 450 ग्राम कैलोरी और अपर प्राइमरी के बच्चों को 20 ग्राम प्रोटीन एवं 700 ग्राम कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना तय किया गया है. इसके बावजूद बच्चों को पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता.

इस बारे में राज्यों का कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ने से बच्चों को केंद्र के मानदंडों के मुताबिक़, पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है. राज्यों ने मिड डे मील योजना के लिए महंगाई के अनुपात में अतिरिक्त राशि दिए जाने की मांग की है. मिड डे मील के बारे में अध्यापकों का कहना है कि आटा 16 रुपये, चावल 30 रुपये, अरहर दाल 85 रुपये, मूंग दाल 65 रुपये, मसूर दाल 65 रुपये, सफ़ेद चना 50 रुपये, मूंगफली 80 रुपये, खाद्य तेल 90 रुपये, कच्चा सोयाबीन 60 रुपये, चीनी 35 रुपये, गुड़ 35 रुपये, आलू 10 रुपये, गोभी 40 रुपये, मटर 70 रुपये, गाजर 40 रुपये, पत्ता गोभी 20 रुपये, पालक 20 रुपये, शिमला मिर्च 20 रुपये, पेठा 20 रुपये और लौकी 20 रुपये प्रति किलो है. मिर्च मसाले भी इतने ही महंगे हैं. ऐसे में इतने कम पैसों में बच्चों को पौष्टिक आहार देना नामुमकिन है. स्कूल के मुखिया को बाज़ार से गुड़, चीनी, तेल या घी, हरी सब्ज़ियां और मिर्च मसाले ख़ुद ही ख़रीदने पड़ते हैं, जबकि गेहूं एवं चावल प्रदेश सरकार द्वारा मुहैया कराए जाते हैं.

अध्यापकों का कहना है कि कई स्कूलों में पर्याप्त बर्तन भी नहीं हैं. कम बजट की वजह से हर रोज़ किराए के बर्तन नहीं लाए जा सकते, इसलिए बच्चों को मिड डे मील के लिए अपने घरों से ही थाली, कटोरी, चम्मच और गिलास लाना पड़ता है. इसके अलावा भोजन खाने के बाद बच्चों को ख़ुद बर्तन साफ़ करने पड़ते हैं. इस तरह बर्तनों की साफ़-सफ़ाई में छात्रों का घंटे भर का वक़्त बर्बाद हो जाता है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ता है. इतना ही नहीं, समय पर राशन न पहुंचने पर अक्सर बच्चों को दोपहर का भोजन भी नहीं मिल पाता. कई बार सड़ा हुआ दूषित अनाज भी सप्लाई किया जाता है, जिससे बच्चों को सही भोजन दिया जाना मुश्किल हो जाता है. कई बार निदेशालय से मिड डे मील की ख़ुराक का बजट बढ़ाने की मांग की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ. इस मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वे शासन को इस मांग से अवगत करा चुके हैं. यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, इसलिए वे इसमें कुछ नहीं कर सकते.

ग़ौरतलब है कि मिड डे मील योजना 15 अगस्त, 1995 में शुरू हुई थी. इस योजना का मक़सद बच्चों को कुपोषण से बचाना है. साथ ही इसके ज़रिए दाख़िले बढ़ाने और स्कूलों में ग़ैर हाज़िरी कम करने पर भी ज़ोर देना है. यह दुनिया के सबसे बड़े पोषण कार्यक्रमों में से एक है. देश के क़रीब पचास हज़ार सरकारी स्कूलों और एजूकेशन गारंटी स्कीम केंद्रों के लगभग 12 करोड़ बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच रहा है. मिड डे मील योजना लापरवाही और भ्रष्टाचार की भी शिकार रही है. बच्चों के भोजन में छिपकली, मेंढक एवं कीड़े मिलना, बच्चों को दूषित भोजन दिया जाना, भोजन से बच्चों का बीमार हो जाना और तयशुदा मात्रा से कम भोजन दिए जाने की शिकायतें भी आम रही हैं.

मिड डे मील के अनाज में हेराफेरी की ख़बरें आएदिन सुनने को मिलती रहती हैं. नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में इस योजना की अनेक ख़ामियां उजागर की गई हैं, जिससे योजना की ज़मीनी हक़ीक़त का पता चलता है. कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड डे मील योजना में केंद्र सरकार की ओर से जारी सहायता राशि का इस्तेमाल दूसरी योजनाओं में हो रहा है. इसके अलावा इस राशि को ऑफिस ख़र्च के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार या ख़ुद राज्य सरकार की ओर से जारी फंड को सरकार ने ही इस्तेमाल नहीं किया. वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार ने मिड डे मील के लिए आवंटन राशि बढ़ाकर 7313 करोड़ रुपये कर दी थी, जबकि वर्ष 2002-03 में यह सिर्फ़ 1099 करोड़ रुपये थी. मिड डे मील के लिए कुल बजट आवंटन 19,797 करोड़ रुपये का था, जबकि राज्य सिर्फ़ 18,205 करोड़ रुपये ही ख़र्च कर पाए. इतना ही नहीं, मिड डे मील के तहत स्कूल में बच्चों तक दोपहर का भोजन पहुंचाने में प्रबंधन के स्तर पर भी भारी ख़ामियां दिखीं. कई राज्यों में अनाज पहुंचाने वाली एजेंसी का ख़र्च नहीं दिया गया, जबकि कई राज्यों में यह देखे बिना ही बिल का भुगतान कर दिया गया कि ठेकेदार सही क़िस्म के अनाज की सप्लाई कर रहा है या नहीं. साफ़ निर्देश होने के बावजूद सूखाग्रस्त इलाक़ों में गर्मी की छुट्टियों में मिड डे मील नहीं बांटा गया. साफ़-सफ़ाई और पोषण के स्तर पर निगरानी में भी भारी ख़ामी पाई गई.

दरअसल, कुपोषण के कई कारण होते हैं, जिनमें महिला निरक्षरता से लेकर बाल विवाह, प्रसव के समय जननी की उम्र, पारिवारिक खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल आदि मुख्य रूप से शामिल हैं. हालांकि इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, लेकिन इसके बावजूद संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आए हैं. देश की लगातार बढ़ती जनसंख्या भी इन सरकारी योजनाओं को धूल चटाने की अहम वजह बनती रही है, क्योंकि जिस तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उसके मुक़ाबले में उस रफ़्तार से सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा उदारीकरण के कारण बढ़ी बेरोज़गारी ने भी भुखमरी की समस्या पैदा की है. आज भी भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं, जिन्हें दो वक़्त की रोटी भी नहीं मिल पाती. ऐसी हालत में वे अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन भला कहां से मुहैया करा पाएंगे. एक कुपोषित शरीर को संपूर्ण और संतुलित भोजन की ज़रूरत होती है. इसलिए सबसे बड़ी चुनौती फ़िलहाल भूखों को भोजन मुहैया कराना है. हमारे संविधान में कहा गया है कि सरकार पोषण स्तर में वृद्धि और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में समझेगी, मगर आज़ादी के छह दशकों बाद भी 46 फ़ीसदी बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में हों तो ज़ाहिर है कि सरकार अपने प्राथमिक संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन में नाकाम साबित हुई है.

आज के बच्चे कल का भविष्य हैं. इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि उन्हें भरपेट संतुलित आहार मिले. इसके लिए सरकार को पंचायती स्तर पर प्रयास करने होंगे. हमारे देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं, ऐसी हालत में भी अगर बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं तो इसकी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में क़रीब 73 लाख बच्चे मिड डे मील से वंचित हैं. इतना ही नहीं, स्कूलों में 200 दिन के बजाय सिर्फ़ 131 दिन ही बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है. राजधानी दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आला अफ़सरों ने यह बात स्वीकार की कि मिड डे मील के मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड अन्य राज्यों के मुक़ाबले काफ़ी पीछे हैं. इन राज्यों में सिर्फ़ 20 फ़ीसदी बच्चों को मिड डे मील मिल पा रहा है.

firdaus@chauthiduniya.com

केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए 16,380 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में यह राशि 10,380 करोड़ रुपये थी. इस राशि में छह सौ करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है. सरकार ने मिड डे मील की डाइट मनी में भी बढ़ोत्तरी की है यानी प्राइमरी स्तर पर प्रति बच्चे 20 पैसे और अपर प्राइमरी स्तर पर 30 पैसे का इज़ाफ़ा किया गया है.

भारत में एकेपी की तरह कोई ग़ैर धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है. एकेपी ने कभी भी ख़लीफ़ा पद को फिर से स्थापित करने की कोशिश नहीं की.

वैसे हमारे देश में पारदर्शिता के संदर्भ में जागरूकता तो पाई जाती है. स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इस दिशा में ध्यान दिलाया.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

मांग के मुताबिक़ मूल्य

पहली योजना है कि हर आदमी जितना वह उपार्जन करे, अपनी मेहनत से पैदा करे, उतना पाए. यह योजना देखने में बड़ी उचित और सुंदर प्रतीत होती है, पर जब इसे कार्यरूप में परिणित करना चाहें तो बड़ी कठिनाइयां पेश आती हैं. पहले तो यह निश्चय कर सकना कि किसने कितना पैदा किया, असंभव सा है. दूसरे, काम या मेहनत पैदा करने में ही नहीं, बल्कि रूपांतर करने में या दूसरे की सेवा-सुश्रुषा करने में भी करनी पड़ती है.

एक किसान जब अपना खेत जोतता-बोता है, तब वह और उसके मज़दूर खेत साफ करते हैं, हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, खेती की देखभाल करते हैं. जब अनाज पककर तैयार हो जाता है, तब फसल काटते हैं, अनाज घर लाते हैं. प्रकृति की अनुकंपा से अनाज पैदा हो गया. अब आप बतलाइए, उन लोगों में से किस-किसने कितना अनाज पैदा किया? इसी तरह एक मशीन को चलाने वाले हैं, उसमें रोज़ाना 10 हज़ार सुइयां बनती हैं. अब कहिए उस मशीन को चलाने वाले ने कितनी सुइयां बनाईं, मशीन का आविष्कार करने वाले का क्या भाग है, मशीन डिज़ाइन करके जिस इंजीनियर ने मशीन खड़ी कर दी उसने कितनी सुइयां बनाईं? इसके अलावा विभिन्न कामों में लगे फैक्ट्री के मज़दूरों का सम्मिलित कार्य जो सुइयां बनाने के उपयोग में आया है, उनका हिस्सा कैसे किया जाएगा? इस तरह से यह बतलाना क़रीब-क़रीब असंभव हो जाता है कि किस-किसने कितना-कितना उपार्जन किया.

किसी चीज का उदाहरण स्वरूप ले लीजिए. यह टेबल या कुर्सी है. उसके बनाने में पहले जंगल लगाने वाले का भाग है, पेड़ काटकर लकड़ी को चीरकर स्लीपर बनाने वाले का भाग है. बाद में बढ़ई, जो उसे साफ कर मेज या कुर्सी का ढांचा बनाता है, उसका भाग है. इनमें लगने वाले लोहे या पीतल के कील-कांटे बनाने वालों का भाग है. कपड़ा, गद्दा या जितनी चीजें उनके बनाने में काम आती हैं, उनके बनाने वाले अनेक आदमियों का इसमें भाग है. फिर पालिश, रंग रोगन करने वालों का भी भाग है और जो-जो उपकरण लगते हैं, उनके विभिन्न निर्माताओं का भी भाग है. अब आप ही अंदाज़ा लगाइए कि एक मेज या कुर्सी बनाने में कितने आदमियों के परिश्रम से कितना उपार्जन हुआ है? किसका कितना-कितना भाग है, यह निश्चय कर सकना असंभव ही है. इसका वितरण करने के लिए कई लोगों ने राय दी कि जिस आदमी ने जितना समय मेज या कुर्सी बनाने के कार्य में ख़र्च किया हो, उसको उसी अनुपात से उसमें साझीदार बनाया जाए.

यह भी विकट समस्या है. समय की क़ीमत समान लगाना कहां संभव नहीं. साधारण कुली मज़दूर है, जो एक रुपये रोज की मज़दूरी में काम करने को तैयार है. जो कारीगर हैं, वे 5, 7, 10 रुपये प्रतिदिन की मज़दूरी पाते हैं. कई ऐसे भी काम करने वाले हैं, जो 50, 100 रुपये प्रतिदिन पाते हैं. कई इससे भी कई गुना अधिक पाते हैं. इन्हीं मेज या कुर्सी बनाने में जो-जो व्यक्ति काम करने के लिए आवश्यक हुए, उनमें जंगल में लकड़ी काटने वाला या सिलाई करने वाला दर्ज़ी संभवतः 2 रुपये रोज़ाना मज़दूरी में मिल जाता. उस इंजीनियर को जिसने प्रथम डिज़ाइन बनाई थी, 50 रुपये रोज़ाना मिल रहा होगा. एक अच्छे वकील को आप 50 रुपये फी घंटा दे देंगे. एक अच्छे सर्जन को आप अपने अपेंडिक्स के आपरेशन करने का 1000 रुपये फी घंटा देने में भी नहीं हिचकेंगे. एक प्रसिद्ध बैरिस्टर को मुकदमे की पैरवी करने के लिए इतनी ही तगड़ी फीस आप सहर्ष चुका आएंगे. सारांश यह निकला कि समय के अनुपात से हर एक आदमी को एक ही मज़दूरी देना संभव नहीं है. इनकी मज़दूरी की क़ीमत प्रसिद्ध मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर टिकी है. लकड़हारा 2 रुपये दैनिक मज़दूरी में क्यों मिलता है, प्रसिद्ध डॉक्टर या बैरिस्टर 1000 रुपये दैनिक में भी कठिनाई से क्यों मिलते हैं? उत्तर यही है कि लकड़हारों की, मज़दूरों की बहुतायत है. एक ढूंढो, सैकड़ों मिलते हैं. डॉक्टरों या बैरिस्टरों की बहुतायत नहीं, इसीलिए वे महंगे हैं.

इसके अलावा एक चीज बनाने में कितना समय किस आदमी का लगा है, यह निर्णय कर सकना भी दुर्गम है. एक कुली या बोझ ढोने वाले मज़दूर को समय के अनुपात से वेतन दिया भी जा सकता है, पर उसके साथ एक डॉक्टर का वेतन समय के हिसाब से कैसे संभव है, जबकि डॉक्टर बनने के पहले उसने 10 वर्ष डॉक्टरी शिक्षा ग्रहण करने में ख़र्च किए हैं. उतने वर्षों में उपार्जन करने का त्याग भी किया है. उसने वर्षों में उपार्जन तो नहीं ही किया, बल्कि वह काफी रकम शिक्षा ग्रहण करने में ख़र्च हुई. इसलिए यह सब हिसाब भी लगाना ही चाहिए. उसका यह कहना सर्वथा उचित होगा कि रोगी को देखने जाने और उसके रोग की

परीक्षा करने में समय आधा घंटा लगता है, पर उस आधे घंटे के पीछे उसका 10 वर्ष का अध्ययन भी तो है. उसी तरह एक कारीगर भी कह सकता है कि अमुक काम को सीखने में, हाथ जमाने में उसका 7 वर्ष का अनुभव है. इसका हिसाब भी उसकी कारीगरी के पीछे है. यह एक हथौड़े की चोट मारता है, उसमें कारीगरी की जो झलक होती है, वह नौसिखिए के हथौड़े की चोट में नहीं हो सकती. गवैए ने वर्षों तक अभ्यास कर-करके गला बनाया है. अगर वह 2 घंटा गाना सुनाकर आपका मनोरंजन करता है तो उन दो घंटों की मेहनत के पीछे उसकी वर्षों की तपस्या भी तो है. हर आदमी स्वीकार करेगा कि हां इसमें अंतर तो पड़ता है, पर कितना अंतर पड़ना चाहिए, इस बारे में मतभेद है. इसी तरह का फ़र्क़ एक होशियार आदमी द्वारा या एक मूर्ख आदमी द्वारा किए हुए काम में भी होता है. निश्चय ही होशियार द्वारा किए हुए काम की क़ीमत ज़्यादा होनी चाहिए. पर कितनी ज़्यादा, इसका निर्णय फिर उसी मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर किया जाता है.

इन उदाहरणों के अलावा कतिपय ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जिनमें काम करने वाला असल में कुछ भी उपार्जन करता नहीं दिखता. एक बढ़ई एक खेत के लिए दरवाज़ा बनाता है, जिससे कि पशु खेत में घुसकर फ़सल न ख़राब कर दें. बढ़ई का काम तो प्रत्यक्ष दीखता है, पर मान लीजिए, उसी खेत में गोफिया से पक्षी या टिड्डियों को उड़ाने के लिए एक लड़का रखा गया है, जो दिन भर हल्ला करके या ढोल पीटकर पक्षियों को उड़ाया करता है और फ़सल की रक्षा करता है. उसका काम भी उतना ही ज़रूरी है, पर उसका काम प्रत्यक्ष दिखता नहीं है. एक डाकिया कुछ भी उपार्जन नहीं करता, वह तो ख़ाली चिट्ठियां बांटता फिरता है. एक पुलिस का सिपाही तो ख़ाली गली में निगरानी रखता हुआ इधर-उधर फिरता रहता है, पर पैदा तो कुछ भी नहीं करता. सैनिक कभी कोई चीज नहीं बनाता, हां कभी-कभी नष्ट ज़रूर करता है. डॉक्टर सिर्फ़ सलाह देता है कि यह दवा लो, गोली लो. बैरिस्टर सिर्फ़ सलाह देते हैं, कोई चीज नहीं बनाते, पैदा नहीं करते. इनमें किसी का भी काम नापा या तौला नहीं जा सकता. फिर भी इन सबकी सेवाओं का उचित मूल्यांकन होना आवश्यक है.

इसके अलावा भौतिक चीजें बनाने वाले हैं, बनाने के तरीक़े बतलाने वाले हैं, कब बनानी चाहिए यह बतलाने वाले हैं, कितनी बनानी चाहिए यह बतलाने वाले हैं इत्यादि. कई व्यक्तियों की सहायता अपेक्षित है. सरल भाषा में काम करने वाला और सोचने वाला, ये दो विभाग एक-दूसरे के लिए आवश्यक हैं. भारत के छोटे गांवों, देहातों में सोचने वाले और करने वाले अलग नहीं होते. सुनार, लोहार, दर्जी, बढ़ई या राज स्वयं ही सोचते हैं कि क्या बनाना है और उसी के अनुसार बनाते हैं. अब बात यह है कि जो आदमी ज़्यादा सोचता है, वह अच्छा कर्ता नहीं बन सकता और जो अच्छा कर्ता है, वह अच्छा विचारक हो सके, यह आवश्यक नहीं. इसी कारण से उनके कामों की किस्म कुछ घटिया रह जाती है. इसी तरह पारिवारिक जीवन देखिए. स्त्रियां बच्चों का पालन-पोषण करती हैं, रसोई बनाती हैं, उनके परिश्रम से कोई स्थायी संपत्ति बनती देखने में नहीं आती. फिर भी उनका मूल्य तो है ही. एक पुरुष को स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा वेतन मिलता है, वह इसलिए कि उसके ऊपर परिवार का पालन-पोषण का भार माना जाता है. पर फिर भी अपनी कमाई वह परिवार पर ख़र्च न करके शराब और जुए में ख़र्च कर देता है तो क़ानून उसे कुछ नहीं कहता. जो स्त्री उसकी विवाहिता पत्नी है, उसका भी कुछ वश नहीं चलता. पर अगर वह पत्नी नहीं है, नौकरानी हुई तो वह क़ानूनन अधिकार से अपना हिस्सा वसूल कर सकती है. उसी तरह पारिवारिक पोषण के लिए लाई हुई रकम में से पत्नी चोरी करके साड़ी ख़रीद लाए या और कोई व्यसन में उड़ा दे तो पति महोदय कुछ भी नहीं कर सकते. जबकि नौकरानी हो तो उसे चोरी के अपराध में जेलखाने भिजवा सकते हैं.

अब आप निर्णय कीजिए कि एक पुरुष का समय एक स्त्री के समय से ज़्यादा क़ीमती क्यों है या किसी का समय किसी दूसरे के समय से क़ीमती या कम क़ीमती क्यों है? आप निश्चय ही इस निदान पर पहुंचे होंगे कि यह योजना कि जो जितना पैदा करे, उतने का अधिकारी हो, संभव नहीं है, क्योंकि किसने कितना पैदा किया, यह जानना कठिन है और उसका अनुपात लगा सकना भी संभव नहीं है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

जब तोप मुक़ाबिल हो

संतोष भारतीय

सरकार पारदर्शिता की पक्षधर नहीं है

मामला चाहे लोकपाल का हो या फिर काले धन का, दरअसल इन सबके पीछे असल मुद्दा सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही का है. आज भ्रष्टाचार को लेकर देश में जो माहौल बना है, उसमें सीबीआई सहित सभी जांच एजेंसियों में सुधार की ज़रूरत है. सरकार उल्टा सोचती है. सीबीआई को पारदर्शी बनाने की जगह उसे आरटीआई के दायरे से ही बाहर कर दिया गया. मतलब यह कि सीबीआई के दफ्तर से अब कोई जानकारी आरटीआई के ज़रिए बाहर नहीं आ सकती. सरकार और कांग्रेस पार्टी सूचना का अधिकार क़ानून यूपीए सरकार की पहली प्रमुख उपलब्धि मानती है. जनसभाओं में कांग्रेस नेता और सरकार के मंत्री यह कहते हैं कि चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, कोई भी नागरिक इस क़ानून के माध्यम से सरकार से सवाल पूछ सकता है और जवाब की आशा कर सकता है. वे यह दावा करते हैं कि इस क़ानून से यूपीए ने सरकार के कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित की है. सरकार सीबीआई को सूचना के क़ानून के दायरे से बाहर रखकर अपनी प्रमुख उपलब्धि से हाथ धो बैठी है. वैसे यह मामला अब मद्रास हाईकोर्ट में पहुंच चुका है. हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को अगले दो सप्ताह में जवाब देना है. अगर कोर्ट ने सरकार के फ़ैसले को ग़लत करार दिया तो वैसे भी सरकार और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी होने वाली है.

सूचना का अधिकार क़ानून 2005 में लागू हुआ. इस क़ानून ने पिछले 6 सालों से लोगों में एक नई आशा, एक नई उम्मीद जगाने का काम किया. अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि सरकार ने सीबीआई को इस क़ानून के दायरे से बाहर रखने का फ़ैसला ले लिया. सरकार ने अगर ऐसा कर दिया तो साथ में यह उसका दायित्व था कि इस आदेश के साथ-साथ देश की जनता को यह बताया जाता कि किन परिस्थितियों में सरकार यह फ़ैसला लेने को मजबूर हुई. सीबीआई ऐसा क्या काम कर रही है, जिसकी सूचना जनता में आने से देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए ख़तरा बन जाता. जहां तक मुझे ख़बर है, सुप्रीम कोर्ट की वजह से सीबीआई आजकल पिछले कुछ सालों में हुए बड़े-बड़े घोटालों की जांच में व्यस्त है. सीबीआई के अधिकारी मंत्रियों की बातों को मानने से इंकार कर रहे हैं. ऐसे में क्या यह समझा जाए कि सरकार की तरफ से सीबीआई को लुभाने की कोशिश है. सवाल तो यह है कि जब आज तक सीबीआई के किसी डायरेक्टर ने यह मांग नहीं की तो फिर सरकार ने यह फ़ैसला क्यों लिया.

सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का सुझाव एटॉर्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने दिया था. वाहनवती ने अपने सुझाव 11 पेज की रिपोर्ट के रूप में दिए. उन्होंने यह दलील दी कि ख़ुफ़िया एजेंसी को आरटीआई के दायरे से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि इससे राष्ट्र की सुरक्षा का मामला जुड़ा है. वाहनवती की रिपोर्ट को आधार बनाकर सरकार ने सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का आदेश दे दिया. मज़ेदार बात यह है कि वाहनवती के सुझाव के ठीक उल्टा सुझाव क़ानून मंत्रालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने दिया. आरटीआई को लागू कराने की ज़िम्मेदारी डीओपीटी के पास है. मज़ेदार बात यह है कि इसे चोरी-छुपे किया गया. सरकार ने इस फ़ैसले को देश की जनता या संसद को बताने की जरूरत नहीं समझी, जो इस क़ानून का उल्लंघन है. इस बात का पर्दाफ़ाश भी एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया. हैदराबाद के आरटीआई एक्टिविस्ट सी जे करीरा ने नार्थ ब्लॉक स्थित डीओपीटी के दफ्तर में इस आदेश की फाइल को देखा. इसे देखने के लिए उन्होंने एक आरटीआई डाली थी. उन्हें पूरी फाइल देखने में पचास मिनट लगे. सीबीआई को दायरे से बाहर रखने के लिए आरटीआई क़ानून के सेक्शन 24 को आधार बनाया गया है. अब सवाल यह है कि इसका सेक्शन 24 क्या कहता है.

सेक्शन 24 के पहले हिस्से में साफ़-साफ़ लिखा है कि आरटीआई क़ानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा. जिन संगठनों को इस क़ानून में छूट दी गई है, उनके नाम इसके दूसरे शेड्यूल में शामिल किए गए हैं. मज़ेदार बात यह है कि इस सेक्शन के अगले वाक्य में यह भी लिखा है कि भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले में इन संगठनों को छूट नहीं दी जाएगी. सेक्शन 24 का दूसरा भाग यह कहता है कि केंद्र सरकार को अधिकार है कि वह एक नोटिफिकेशन जारी करके दूसरे शेड्यूल में शामिल संगठनों के नामों में फेरबदल कर सकती है. मतलब यह कि सरकार किसी ख़ुफ़िया व सुरक्षा संगठन को जोड़ सकती है या हटा सकती है. सेक्शन 24 के तीसरे भाग के मुताबिक़, अगर सरकार किसी संगठन को जोड़ने या हटाने के लिए नोटिस जारी करती है तो उसे यह मामला संसद के दोनों सदनों में रखना ज़रूरी है.

पहली बात तो यह है कि सूचना का अधिकार क़ानून सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को इसके दायरे से बाहर रखने की अनुमति नहीं देता है. दूसरी बात यह है कि अगर एक जांच एजेंसी को इससे छूट मिली तो क्या भविष्य में ईडी, पुलिस या अन्य जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन्हें भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का इरादा है? ऐसी ही मांग अगर राज्य सरकारों की जांच एजेंसियों की तरफ़ से उठने लगे तो इस सूचना के अधिकार क़ानून में क्या बचा रह जाएगा?

सीबीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का फ़ैसला चौंकाने वाला है. यह फ़ैसला क्यों लिया गया, क्या संसद में इस बात पर चर्चा हुई? आरटीआई के क़ानून के मुताबिक़, सुरक्षा और ख़ुफ़िया विभाग को आरटीआई से छूट मिली है. सीबीआई का रिश्ता न तो देश की सुरक्षा से है और न यह ख़ुफ़िया विभाग है. सीबीआई सिर्फ़ एक जांच एजेंसी है. इससे सरकार की मानसिकता को लेकर कई सवाल उठते हैं. क्या यह शुरुआत है. पहली बात तो यह है कि सूचना का अधिकार क़ानून सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को इसके दायरे से बाहर रखने की अनुमति नहीं देता है. दूसरी बात यह है कि अगर एक जांच एजेंसी को इससे छूट मिली तो क्या भविष्य में ईडी, पुलिस या अन्य जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, उन्हें भी आरटीआई के दायरे से बाहर रखने का इरादा है? ऐसी ही मांग अगर राज्य सरकारों की जांच एजेंसियों की तरफ से उठने लगे तो इस सूचना के अधिकार क़ानून में क्या बचा रह जाएगा? एक दलील दी जा सकती है कि आरटीआई क़ानून के सेक्शन 8 के मुताबिक़ जिन मामलों की जांच चल रही है, उनके बारे में कोई सूचना नहीं दी जा सकती है. सीबीआई को आरटीआई क़ानून के तहत ही यह छूट मिली है. एक बार मामले की जांच हो गई तो फिर सीबीआई को उस मामले के बारे में सूचना देने में क्या परेशानी हो सकती है. एक तर्क यह दिया गया कि जिन मामलों की जांच पूरी हो जाती है, उनके काग़ज़ात वैसे भी कोर्ट में जमा हो जाते हैं.

यह वक़्त सीबीआई और सरकार, दोनों की साख बचाने का है. सीबीआई पहले से ही आरोपों के घेरे में है. सीबीआई का राजनीतिक इस्तेमाल होता है. सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल सीबीआई से अपने हिसाब से काम कराते हैं. सरकार सीबीआई के जरिए विरोधियों पर शिकंजा कसती है और सहयोगी राजनीतिक दलों के मामलों को भुला देती है. सीबीआई में नियुक्ति के लिए लॉबिंग होती है. ऐसे कई आरोप हैं, जो देश की इस प्रीमियर जांच एजेंसी पर अक्सर लगाए जाते हैं. क्या सरकार यह समझती है कि इस देश के लोग एक साफ़-सुथरी और सक्षम जांच एजेंसी के लायक भी नहीं हैं या फिर यह समझा जाए कि यूपीए गठबंधन सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का पक्षधर नहीं है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

यह धर्म निरपेक्षता नहीं है

भारतीय इतिहास में तुर्की की एक अहम भूमिका रही है. भारत के विभाजन के केंद्र में भी इसका नाम रहा और इसके बाद भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षवाद अपनाए जाने के पीछे भी वजह तुर्की ही था. प्रथम विश्व युद्ध के वक़्त जब ओटोमन सुल्तान की हार हुई, तब उसे अपने खलीफा पद पर भी ख़तरा मंडराता नज़र आया. उस वक़्त ऐसी अफवाहें थीं कि येरुशलम के मुफ्ती को नया खलीफा बनाया जाएगा. गांधी जी ने इस मौक़े को पहचाना और अंग्रेजों के ख़िलाफ़ एक ऐसे संघर्ष का आगाज़ किया, जिसमें हिंदू और मुसलमान एक होकर आगे आए. 1857 के संघर्ष के बाद ख़िलाफ़त आंदोलन ही पहला ऐसा आंदोलन था, जो इतना अधिक सफल हुआ था. यह आंदोलन भारत के कोने-कोने में फैला.

गांधी जी ने चौरी चौरा की घटना के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया. इससे मुसलमान तो निराश हुए ही, कांग्रेस को भी नुक़सान हुआ. इसके बाद अंग्रेजों के ख़िलाफ़ फिर इतना बड़ा और संयुक्त (हिंदू-मुस्लिम) आंदोलन नहीं खड़ा किया जा सका. कांग्रेस ने जिन्ना की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोती लाल नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के अधिकारों की गारंटी की बात हो. अपनी मांग नामंजूर होने के कारण जिन्ना नाख़ुश होकर लंदन चले गए और वहां जाकर उन्होंने 6 सालों तक वकालत की. जब वह वापस आए, तब तक अल्पसंख्यकों के अधिकार की उनकी मांग एक अलग राष्ट्र में बदल चुकी थी. कांग्रेस मुसलमानों का विश्वास खो चुकी थी. 1946 में कांग्रेस एक भी मुस्लिम सीट नहीं जीत पाई. आगे सबने देश का विभाजन भी देखा. लेकिन थोड़ा पीछे जाएं तो देखते हैं कि 1923 में जब तुर्की में कमाल अता तुर्क आए तो उन्होंने खलीफा पद ही ख़त्म कर दिया. उन्होंने तुर्की को एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने पर जोर दिया. धर्मनिरपेक्षवाद से उनका तात्पर्य अल्पसंख्यकों के विश्वास की रक्षा की गारंटी या सभी धर्मों के साथ समान बर्ताव से नहीं था. उनका धर्मनिरपेक्षवाद असल में मानवतावाद था. वह राजनीतिक जीवन से धर्म को पूरी तरह से हटाना चाहते थे. वह सोचते थे कि धर्म ने ही तुर्की को पिछड़ा बनाया है. यहां आधुनिकीकरण का अर्थ धर्म को खारिज करना रह गया. तुर्की में सेना को संविधान और धर्मनिरपेक्षवाद की सुरक्षा का ज़िम्मा सौंप दिया गया. अब 90 साल बाद तुर्की में एक धार्मिक रूझान वाली पार्टी एकेपी (जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी) 2002 से लगातार तीन चुनाव जीत चुकी है और अपनी सरकार चला रही है. एकेपी ने धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को दो-तिहाई बहुमत से हराया है. एकेपी एक इस्लामिक पार्टी है, लेकिन वह इस्लामिस्ट नहीं है. अपने पहले कार्यकाल में यह पार्टी तब विवादों में आई, जब इसने महिलाओं को सिर पर स्कार्फ़ बांधने की बात कही, लेकिन बाद में एकेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारी निवेश करके ख़ुद को एक आधुनिक विचारों वाली पार्टी के रूप में स्थापित किया. एकेपी ने यह दिखाया है कि धर्मनिरपेक्ष न होते हुए भी देश की तरक्की और आधुनिकीकरण के लिए काम किया जा सकता है. तुर्की में धर्मनिरपेक्षवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि अब इस पर वाद-विवाद के लिए कोई जगह ही नहीं बची है. अब यहां सिर्फ़ एक ही चुनौती है, विकास और आधुनिकीकरण करने की.

भारत में एकेपी की तरह कोई ग़ैर धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है. एकेपी ने कभी भी खलीफा पद को फिर से स्थापित करने की कोशिश नहीं की. भाजपा के पास कुछ पुराने मुद्दे और पुराने सपने हैं, जिन्हें वह फिर से स्थापित करना चाहती है. दूसरी ओर आरएसएस है, जिसे बीसवीं शताब्दी में भी ख़ुद को एडजस्ट कर पाना मुश्किल लग रहा है. भारत का धर्मनिरपेक्षवाद एक नारा बन गया है. एक ऐसी रूढ़िवादी ताक़त, जिसके सहारे कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी करती है. नेहरू और सुभाष चंद्र बोस अता तुर्क की तरह ज़रूर धर्मनिरपेक्ष थे. ये दोनों धर्म के किसी भी स्वरूप के ख़िलाफ़ थे. अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धार्मिकता का अति प्रदर्शन हो गया है. जैसे सार्वजनिक समारोहों में दीप जलाना, इफ्तार पार्टी देना, स्वामियों-बाबाओं का सत्कार और नेताओं द्वारा शिरडी-सत्य साईं आश्रम एवं अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाना.

अंधविश्वास, किवदंतियों की आलोचना और आधुनिकता को तरजीह देने वाली बातें नेहरू के बाद ही ख़त्म हो गईं. अब तो राजनीतिक गलियारों में हस्तरेखा विशेषज्ञ, ज्योतिषी और अंकशास्त्री को आसानी से घूमते हुए देखा जा सकता है. यहां तक कि अब तो कैबिनेट में फेरबदल भी ग्रहों की चाल अनुकूल न होने की वजह से स्थगित कर दिया जाता है. नए चुने गए मंत्री अपने ज्योतिषी से शपथ ग्रहण के लिए सटीक समय के बारे में सलाह लेते हैं. शायद किसी दिन भारत में एक ऐसी पार्टी होगी, जो धर्म के इन विवादित मुद्दों को अस्वीकार करने का साहस दिखाएगी. धर्मनिरपेक्षवाद ने कांग्रेस को और ज़्यादा धर्म के क़रीब ला दिया है. आज कांग्रेस को स्वतंत्र पार्टी या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरह और ज़्यादा आधुनिक होने की ज़रूरत है. इन पार्टियों के लिए कभी भी संप्रदायवाद-धर्मनिरपेक्षवाद एक सवाल नहीं रहा. ये बातें उनके लिए अप्रासंगिक थीं. वे भारत के सभी लोगों को भारतीय की तरह देखती थी, न कि हिंदू या मुसलमान की तरह.

feedback@chauthiduniya.com

डॉ. मुहम्मद मंज़ूर आलम

भारत में पारदर्शिता आंदोलन और मुसलमान

समाज में पारदर्शिता को बहुत महत्व प्राप्त है, क्योंकि इसका सीधा संबंध समाज को पाक-साफ रखने और ईमानदारी को बढ़ावा देने से है. इस संदर्भ में हर जगह कोशिश होती रहती है. वर्ष 1993 में पैट्रोजन द्वारा स्थापित की गई ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल अपने 70 राष्ट्रीय चैप्टरों के सहयोग से विभिन्न देशों में इस संदर्भ में जायज़ा लेते हुए प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों को बताकर पारदर्शिता की दर्जाबंदी करती है. इससे उन देशों में वर्तमान परिस्थितियों का अंदाज़ा होता है और इस विषय में वे परिस्थिति को बेहतर बनाने में अधिक ध्यान दे पाते हैं. पिछले दिनों ट्यूनीशिया एवं मिस्र में भ्रष्टाचार और अन्य सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध जो जनांदोलन हुए, उनका प्रभाव विश्व के विभिन्न देशों में कहीं कम तो कहीं अधिक पड़ा. हमारा देश भारत इससे अछूता नहीं है, क्योंकि यहां अपारदर्शिता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है. ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की 2010 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत का स्थान भ्रष्टाचार के मामले में विश्व के 178 देशों की सूची में 87वां है, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 84वां था. इससे साफ पता चलता है कि एक वर्ष में पारदर्शिता के ग्राफ में तीन अंकों की कमी आई है.

वैसे हमारे देश में पारदर्शिता के संदर्भ में जागरूकता तो पाई जाती है. स्वाधीनता संग्राम के दौरान भी महात्मा गांधी एवं अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने इस दिशा में ध्यान दिलाया. कहा जाता है कि भाजपा आंदोलन के दौरान भी यह पहलू सोच की सीमा तक ही था. केंद्र में कांग्रेस नेतृत्व में पहले वाले यूपीए की साझा सरकार के दौर में संसद द्वारा सूचना अधिकार क़ानून का बनना और उसका लागू होना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी. वास्तव में यही वह परिस्थिति है, जिसके आलोक में केंद्रीय रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने बीते 8 जून को अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत पारदर्शिता आंदोलन से गुज़र रहा है. इस संदर्भ में उन्होंने सूचना अधिकार क़ानून की सराहना करते हुए कहा कि इसके लागू होने के बाद मुख्यत: राजदारी की दीवारें भस्म हो रही हैं, चाहे वह कोई भी विभाग हो-राजनीति, कार्यपालिका अथवा उद्योग जगत. उनके अनुसार, पारदर्शिता के संदर्भ में रुझान बनने लगा है और आंदोलन की शुरुआत भी हो चुकी है, इसे अब रोका नहीं जा सकता है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग इस देश में प्रमुख पदों पर आसीन हैं, वे अभी तक इस बदलाव के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि फ़िलहाल इस पारदर्शिता के संदर्भ में अनेक कठिनाइयां है, किंतु कुछ वर्षों के बाद परिस्थितियों में बदलाव होगा और पारदर्शिता पूरे तौर पर हमारे समाज में आ जाएगी.

ए के एंटनी ने इस संदर्भ में भारतीय मीडिया, ग़ैर सरकारी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के योगदान की भी सराहना की. उल्लेखनीय है कि पारदर्शिता के संदर्भ में देश का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय मुसलमान भी पूरे तौर पर इस आंदोलन में भागीदार है, तभी तो 1992 में स्थापित ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने आज़ादी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर कारवां-ए-आज़ादी निकाला. एक कारवां मिल्ली काउंसिल के महासचिव मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी के नेतृत्व में 21 सितंबर, 1997 को टीपू सुल्तान की कब्र श्रीरंगापटनम (कर्नाटक) और दूसरा कारवां मिल्ली काउंसिल के सहायक महासचिव मौलाना असरारुल हक़ कासमी, जो अब उपाध्यक्ष एवं सांसद हैं, के नेतृत्व में मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) से सिराजुद्दौला के मक़बरे से आरंभ हुआ. दोनों कारवां देश के 50 प्रमुख नगरों से गुजरते और आज़ादी, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता के वास्तविक अर्थ को बताते हुए 7 नवंबर, 1997 को एक साथ दिल्ली पहुंचे तथा निज़ामुद्दीन स्थित हुमायूं टॉम्ब के निकट लॉन में संपन्न हुए. इस अवसर पर श्वेतपत्र और मांगपत्र जारी किए गए. इन दोनों कारवां की सबसे प्रमुख बात यह थी कि इन्होंने मुसलमानों को यह एहसास दिलाया कि आप इस देश में अजनबी नहीं हैं, किराएदार नहीं हैं, इस देश के आप भी भागीदार हैं और बुरे-भले की ज़िम्मेदारी आप पर भी आती है. आपको अपने अधिकारों को समझना चाहिए और देश के प्रति अपना दायित्व भी. भारतीय समाज में जो बुराइयां पैदा हो रही हैं, उन्हें मिटाना और अच्छे कामों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना भी आपका दायित्व है और इस समय की सबसे बड़ी बुराई भ्रष्टाचार है. ऐसी बुराइयों को मिटाने के लिए संघर्ष करना आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है और यह आपके ईमान एवं आस्था से जुड़ा हुआ मामला है. खैरे उम्मत का एक व्यक्ति होने के नाते अपने आचरण को दुरुस्त करना, इन बुराइयों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाना और देश को इन बुराइयों से बचाने के लिए ठोस प्रयत्न करना आपका महत्वपूर्ण दायित्व है तथा दायित्व के निर्वहन के लिए सार्वजनिक जागरूकता लाना भी अत्यंत आवश्यक है.

मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी की अध्यक्षता में आयोजित दिल्ली के ऐतिहासिक समारोह को इतिहासकार एवं स्वतंत्रता सेनानी बी एन पांडेय, जस्टिस एच आर खन्ना, जस्टिस ए एम अहमदी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जाने-माने पत्रकार अजीत भट्टाचार्य, कुलदीप नैयर एवं राजेंद्र पुरी, लेफ्टिनेंट जनरल एम एल छिब्बर, एडमिरल आर नहलियानी, एयर चीफ मार्शल आई एच लतीफ, हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. एम खलीलुल्लाह एवं डॉ. सैयद निहाल अहमद रिजवी, ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक डॉ. एस जेड कासिम और वरिष्ठ उर्दू कवि हफ़ीज मेरठी ने भी संबोधित किया था. बीते 10 जून को अंग्रेजी दैनिक दि स्टेट्समैन के अपने स्थायी कॉलम में यूपीए एंड अन्ना हजारे के संदर्भ में वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र पुरी, जो कारवां-ए-आज़ादी के अनेक कार्यक्रमों के चश्मदीद गवाह हैं, लिखते हैं कि 26 अगस्त से एक सितंबर, 1997 तक तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष पी ए संगमा ने संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र तलब किया, जो भारत की स्वतंत्रता की पचासवीं वर्षगांठ के संदर्भ में था. इस विशेष सत्र में देश की परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते हुए भविष्य का राष्ट्रीय एजेंडा तय किया गया. इस एजेंडे के तहत भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और सांप्रदायिता के उन्मूलन की मांग की गई. अध्यक्ष ने भारतीय संसद के इतिहास में सर्वप्रथम विशेष सत्र का उद्घाटन करते हुए दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया. उन्होंने एजेंडे को कार्यरूप देने हेतु दूसरी स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने का न्योता दिया. तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने जनता से इस संदर्भ में शांतिपूर्ण प्रयास करने की अपील की और स्वयं गिरफ़्तारी देने का आश्वासन भी दिया. सभी लोगों ने इसके लिए उनकी प्रशंसा की. राजेंद्र पुरी अपने कॉलम में आगे लिखते हैं कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने अपनी कारवां-ए-आज़ादी मुहिम के दौरान दूसरी स्वाधीनता के इस राष्ट्रीय आह्वान की हिमायत करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाया और एजेंडा भी बनाया, जो केवल मुस्लिमों के लिए नहीं था, उसमें उन नीतियों की वकालत की गई थी, जो पूरे देश के हित में थीं.

मिल्ली काउंसिल के कारवां-ए-आज़ादी के चंद वर्षों बाद जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी, पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैंने देश की आम समस्याओं में मुसलमानों की दिलचस्पी के बारे में कहा कि हैरत तो इस बात पर होती है कि इस संदर्भ में मुसलमान आगे बढ़ता है तो उसका हौसला नहीं बढ़ाया जाता. उदाहरणस्वरूप, जब मिल्ली काउंसिल ने कारवां-ए-आज़ादी के दौरान देश के 50 नगरों में दूसरी स्वाधीनता के कार्य को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली में 7 नवंबर, 1997 को समापन रैली की तो उसमें 88 पत्रकारों ने भाग लिया, लेकिन अगले दिन उर्दू के अतिरिक्त किसी भी भाषा यानी अंग्रेजी और हिंदी मीडिया ने इसका नोटिस नहीं लिया और जब इस संदर्भ में कुछ समाचारपत्रों के नुमाइंदों से ब्लैक आउट का कारण मालूम किया गया तो उनका उत्तर था कि प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें इस कार्यक्रम को नज़रअंदाज़ करने के इशारे मिले थे. इस पर पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की.

जहां तक मीडिया का संबंध है, वह ख़ुद भी ठीक नहीं है. उसके लिए कभी मुसलमानों की कम महत्व वाली समस्याएं ज़्यादा अहम बन जाती हैं और वह उनमें ऐसे व्यस्त हो जाता है, जैसे लगता है कि शायद उस समय उसके लिए यह प्रमुख मिशन बन गया है. विगत वर्षों में शाहबानो, गुड़िया एवं इमराना और वर्तमान में दारूल उलूम देवबंद के कुलपति से संबंधित समस्याएं इसका उदाहरण हैं. इसके विपरीत जब मुसलमान और उनके संगठन राष्ट्रीय मुद्दों में दिलचस्पी लेते हैं तो उन्हें ब्लैक आउट किया जाता है और फिर यह शिकायत भी की जाती है कि मुसलमानों को केवल अपनी समस्याओं में दिलचस्पी रहती है. पारदर्शिता के संदर्भ में जो वातावरण हमारे देश में पाया जा रहा है, उसमें मुस्लिम समुदाय का योगदान है. रक्षा मंत्री एंटनी के इस विचार से किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती कि इस आंदोलन में ग़ैर सरकारी संगठनों का भी योगदान है. ग़ैर सरकारी संगठनों में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल भी निश्चित रूप से शामिल है, जिसने कारवां-ए-आज़ादी के बाद भी इस कार्य को आगे बढ़ाया. कुछ ही वर्ष पूर्व दिल्ली के रामलीला मैदान में राजनीतिक जागरूकता रैली और वार्षिक अधिवेशनों में भी पारदर्शिता की मांग की गई. कुछ महीने पहले केरल के मंजेरी मुल्लापुरम के वार्षिक अधिवेशन के दौरान पास किए गए प्रस्तावों में भी पारदर्शिता की मांग की गई है. उक्त तमाम तथ्य बताते हैं कि मुसलमानों को राष्ट्रीय मुद्दों में पूरी दिलचस्पी रहती है और वे मुख्य धारा से पूरे तौर पर जुड़े हुए हैं.

मिल्ली काउंसिल के कारवां-ए-आज़ादी के चंद वर्षों बाद जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी, पूर्व प्रधानमंत्री गुजराल का ध्यान आकृष्ट करते हुए मैंने देश की आम समस्याओं में मुसलमानों की दिलचस्पी के बारे में कहा कि हैरत तो इस बात पर होती है कि इस संदर्भ में मुसलमान आगे बढ़ता है तो उसका हौसला नहीं बढ़ाया जाता.

(लेखक ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महासचिव हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

मुसलमानों को जागरूक करना होगा

वह समाज कभी नहीं बदल सकता, जिसमें बदलने की चाह और एहसास न हो. मशहूर कहावत है कि सोते हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो जाग रहा हो, उसे कैसे जगाया जा सकता है. दीनी रहनुमाओं ने मुसलमानों को कुछ ऐसा ही बना दिया है. उन्हें मौत के बाद की ज़िंदगी के सब्ज़बाग़ दिखाकर उनके वर्तमान को ही बदल दिया. वे मौत के बाद मिलने वाली असल ज़िंदगी के चक्कर में अपनी वर्तमान ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं.

–मो. रफ़ीक़ चौहान, *ईमेल से.*

ज़ख्म तो हमने इन आंखों से देखे

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख–ज़ख्म आज भी ताज़ा हैं, पढ़ा. आज भी अगर वही हैवानियत दोहराई जाती है तो सुरक्षा की क्या गारंटी है? सरकार के पास अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए कोई विशेष योजना नहीं है. राजनीतिक पार्टियों का मक़सद सिर्फ़ अपना वोट बैंक बनाए रखने से ज़्यादा कुछ नहीं रहता.

ज़ख्म तो हमने इन आंखों से देखे हैं,
लोगों से सुनते हैं, मरहम होता है.

–जीजी शेख़, *भरूच, गुजरात.*

किसानों की दयनीय हालत

देश में किसानों की हालत बदतर होती जा रही है. सरकार की क़र्ज़ माफ़ी योजना का लाभ लघु एवं सीमांत किसानों को नहीं मिला. केंद्र सरकार की क़र्ज़ माफ़ी योजना पर पानी फिर गया है. दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए 2 मार्च, 2008 को नोटिफिकेशन जारी करके उन सभी लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल कर लिया गया, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2007 से पहले क़र्ज़ लिया था.

–राम सागर पांडेय, *फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

■ सरकार की क़र्ज़ माफ़ी योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला. लगता है कि इसमें भी घोटाला हो गया है. सरकार ने लघु एवं सीमांत किसानों के लिए योजना बनाई, लेकिन उनमें से भी 70-80 फ़ीसदी वंचित हो गए.

–भरत राम शुक्ल, *फ़ैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ पत्र

सबको साथ लेकर चलना होगा

मलियाना और हाशिमपुरा की घटनाएं इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग़ हैं. यह बेहद शर्म और अफ़सोस की बात है कि जिन पर नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व होता है, उन्होंने ही बेक़सूर लोगों का बेरहमी से क़त्ल किया. दंगों के वक़्त पूरी सरकारी व्यवस्था हिंदू बन जाती है. पुलिस अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करके दंगाइयों का साथ देने लगती है. मामला दंगों का हो, सरकारी सुविधाओं का हो या सरकारी नौकरियों का, हर जगह मुसलमानों के साथ भेदभाव बरता जाता है. हमें यह समझना होगा कि जब तक देश के सभी समुदाय, सभी तबक़े तरक़्क़ी नहीं करेंगे, तब तक यह देश भी तरक़्क़ी नहीं कर सकता. इसलिए ज़रूरी है कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए.

–सरफ़राज़ ख़ान, *हिसार, हरियाणा.*

शर्मनाक टिप्पणियां

नेताओं और मंत्रियों द्वारा इन दिनों एक-दूसरे पर काफी अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही हैं. देश का भविष्य तय करने वाले लोग ऐसी अशोभनीय टिप्पणियां करेंगे, ऐसी उम्मीद बापू या फिर भीमराव अंबेडकर ने कभी नहीं की होगी. नेताओं को गंभीर और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए. आज भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोज़गारी और आतंकवाद से निपटने की ज़रूरत है, न कि आरोप-प्रत्यारोप और अमर्यादित-असंसदीय भाषा के माध्यम से भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करने की.

–डॉ. रवींद्र कुमार सिंह, *सहरसा, बिहार.*

feedback@chauthiduniya.com

राजकमल प्रकाशन समूह
1-बी, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-110 002
फोन 011-23274463, 23288769, फैक्स 011-23278144
www.rajkamalprakashan.com Email : info@rajkamalprakashan.com
शाखा : अशोक राजपथ, पटना-800006 फोन 0612-2672280
पहली मंजिल, दरबारी बिल्डिंग, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-211001 फोन 0532-3293838, 2427274

लेखन विधा सम्मान 2011
'चौथी दुनिया' में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को दी जाने वाली 700 रुपए की किताबें

राष्ट्रीय जीवन के महत्त्वपूर्ण युग को पुनर्जीवित करनेवाले के.के. बिड़ला की आत्मकथा। प्रस्तावना सोनिया गांधी ने लिखी है।
संथाल विद्रोह का जीवन्त चित्रण करनेवाला महाश्वेता देवी का कालजयी उपन्यास जिसमें तिलका मांझी, सिद्धू और कान्हू का जीवनदर्शन है।

राजकमल प्रकाशन समूह की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें
हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी
हेल्पलाइन : 09311196029

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ- 2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश), पिन - 201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

कई वर्षों तक चली क़ानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपियों को दिसंबर 2009 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सरकारी स्कूलों का लें हिसाब

शिक्षा का अधिकार क़ानून के तहत छह साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होगा. इस क़ानून से उन करोड़ों बच्चों को फ़ायदा मिलेगा, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूलों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है? शायद नहीं. एक ओर जहां स्कूलों की कमी है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की संख्या भी उतनी नहीं है, जितनी आवश्यकता है. हालत यह है कि अधिकांश प्राथमिक स्कूलों के पास अपनी इमारत तक नहीं है. बच्चे खुले मैदान या झोपड़ी में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं. जहां इमारतें हैं भी, वे साल-दो साल के भीतर ढहने लगती हैं. आख़िर इसकी वजह क्या है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आम तौर पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि स्कूल बनाने के लिए जितना पैसा आता है, उसमें से आधा भी इस मद पर ख़र्च नहीं किया जाता. प्रधानाध्यापक और ठेकेदार की मिलीभगत से कमज़ोर इमारत बनाकर बाक़ी पैसा हजम कर लिया जाता है. ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बाक़ी पैसा सचमुच कहां चला जाता है, क्योंकि यह पैसा आपका है, जो आप टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं और जिससे आपके बच्चों के लिए स्कूल की इमारत बन सकती है. इसलिए आप इस एक-एक पाई का हिसाब अधिकारियों से मांग सकते हैं. इस अंक में हमने इसी से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित किया है, जिसका इस्तेमाल करके आप स्कूल की इमारत बनने के लिए आए पैसों का हिसाब-किताब मांग सकते हैं. चौथी दुनिया किसी भी समस्या के समाधान या सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301, ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप
(सरकारी स्कूल की इमारत से संबंधित जानकारी)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम.....
पता.....

दिनांक.....

विषय: सूचना का अधिकार क़ानून 2005 के तहत आवेदन

कृपया स्कूल (स्कूल का नाम और पता) से संबंधित निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराएं:-

1. वर्ष.....से वर्ष.....के बीच उक्त स्कूल को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई? यह सूचना निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:-
(क) राशि आवंटन का वर्ष
(ख) कितनी राशि आवंटित हुई?
(ग) किस उद्देश्य/कार्य के लिए राशि आवंटित की गई?
(घ) वास्तविक राशि, जो उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए ख़र्च की गई?
(च) किस उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए उक्त राशि ख़र्च की गई?

2. पिछले दो सालों में उक्त स्कूल पर ख़र्च की गई रकम का ब्यौरा निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:-
(क) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए कितनी राशि ख़र्च की गई?
(ख) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य का पूर्ण विवरण
(ग) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत राशि
(घ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को करने की स्वीकृति देने की तिथि
(च) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा हो गया या अधूरा है या अभी चल
रहा है?
(छ) उस एजेंसी का नाम, जो इन उद्देश्यों/कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है
(ज) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के शुरू होने की तारीख
(झ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के पूरा होने की तारीख
(ट) एजेंसी को किस दर पर प्रत्येक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया?
(ठ) एजेंसी को कितनी राशि दी जा चुकी है?
(ड) कार्य के स्केच की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं
(ढ) कब और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है? उस निर्णय की एक कॉपी उपलब्ध कराएं.
(त) उस सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का नाम बताएं, जिसने कार्य का निरीक्षण किया और एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी. कार्य के कौन से हिस्से का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया?

3. पिछले एक साल में उक्त स्कूल पर ख़र्च की गई रकम का ब्यौरा निम्न विवरण के साथ उपलब्ध कराएं:-
(क) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए कितनी राशि ख़र्च की गई?
(ख) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य का पूर्ण विवरण
(ग) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को पूरा करने के लिए स्वीकृत राशि
(घ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य को करने की स्वीकृति देने की तिथि
(च) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य की वर्तमान स्थिति, कार्य पूरा हो गया या अधूरा है या अभी चल रहा है?
(छ) उस एजेंसी का नाम, जो इन उद्देश्यों/कार्यों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है
(ज) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के शुरू होने की तारीख
(झ) प्रत्येक उद्देश्य/कार्य के पूरा होने की तारीख
(ट) एजेंसी को किस दर पर प्रत्येक कार्य पूरा करने के लिए दिया गया?
(ठ) एजेंसी को कितनी राशि दी जा चुकी है?
(ड) कार्य के स्केच की एक सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराएं
(ढ) कब और किस आधार पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है? उस निर्णय की एक कॉपी उपलब्ध कराएं.
(त) उस सहायक अभियंता और अधीक्षण अभियंता का नाम बताएं, जिसने कार्य का निरीक्षण किया और एजेंसी को भुगतान करने के लिए अपनी सहमति दी. कार्य के कौन से हिस्से का उनके द्वारा निरीक्षण किया गया?

मैं.....रुपये बतौर आवेदन शुल्क जमा कर रहा/रही हूं.

भवदीय
नाम.....
हस्ताक्षर.....
पता.....

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

यह सप्ताह अध्ययन-मनन, किसी ताजातरीन मूवी या थिएटर में समय गुजारने का है. क्लब जाकर मनोरंजन या दावत की व्यवस्था करना आपके लिए महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है. अपने परिवारीजनों और दोस्तों के बीच समय गुजार लेना काफी रहेगा.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

किसी शुभ काम या विवाह के विषय में इस सप्ताह आपकी सहमति ज़रूरी हो सकती है. घर के सदस्यों के लिए खाने-पीने का इंतज़ाम, सभी के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुओं का संकलन और उसके बाद नज़दीकी मित्रों से गपशप अथवा शतरंज-ताश की एक-दो बाजी.

मिथुन 21 मई से 20 जून

इस सप्ताह चिंताएं आपको एक साथ घेर रही हैं. वैसे तो आपका पूरा दबदबा अपने क्षेत्र में है, फिर भी अनुशासन और व्यवस्था को क़ायम रखने के लिए कुछ अधिकार आपको भी लोगों से ही मिले हैं. सप्ताहांत तक सबको कुछ बदलाव नज़र आएगा, जिसके लिए आपकी तारीफ़ ज़रूर होगी.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

इस सप्ताह कुछ फालतू लोगों के कारण आपका समय ख़राब हो सकता है. बेहतर होगा कि आप आउटिंग पर निकल जाएं और किसी कोने में बैठकर अपना रिसर्च पूरा करें, यही समय का सदुपयोग होगा. यदि आप परीक्षार्थी हैं तो अपने पूरे समय का इस्तेमाल करें, अन्यथा बाद में पछतावा होगा.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह आप कुछ आराम के मूड में रहेंगे. आप अनेक प्रकार के रखरखाव से जुड़े रहते हैं. कभी-कभी आप किसी लंबी यात्रा अथवा लोकल ड्राइव पर भी निकल जाते हैं. कुछ ऐसा ही प्लान इस सप्ताह आपने बना रखा है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

किसी महत्वपूर्ण कारोबारी मामले पर ग़ौर करने से इस सप्ताह आपको अच्छा लाभ मिल सकता है. यदि इस सप्ताह एक्स्ट्रा ड्यूटी का चक्कर न पड़े तो फिर अपने पार्टनर के साथ कोई ताजातरीन मूवी देख सकते हैं.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

यह सप्ताह आप रिज़र्व रखेंगे सिर्फ़ नज़दीकी संबंधियों एवं नए मित्रों से मिलने और इंटरनेट पर चैटिंग करने के लिए. सप्ताह मध्य में अच्छे भोजन या दावत की भी आपको आकांक्षा रहती है, जिसके लिए आपका पार्टनर सतर्क है.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

अपने हिसाब-किताब और आर्थिक ताने-बाने को दुरुस्त रखने के लिए यह सप्ताह आपके लिए उपयोगी है. घर का बजट संतुलित करना और सभी को पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराना आपका कर्तव्य है. सप्ताह मध्य तक आप किसी संस्था या समारोह के आमंत्रित अतिथि भी हो सकते हैं.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

इस सप्ताह आप अपने करियर या कारोबार के सिलसिले में किसी लंबी यात्रा के लिए तैयार रहें. चाहे आपका कारोबार मंदा हो या सामान्य, परंतु आपकी व्यस्तता आपके लिए ज़रूरी उपक्रम है. यदि कोई रिफॉर्म या सुधार आपके हाथ में हो तो तुरंत कर डालें.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

इस सप्ताह आपके क़रीब कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, जिनके साथ आप लंबी दौड़ की बात चला सकते हैं. आपका आर्थिक ढांचा कुछ कमज़ोर चल रहा है, जिसके कारण इस सप्ताह आप किफ़ायत का रास्ता अपनाएंगे.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

अपने जॉब या बिजनेस में इस सप्ताह आप अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं. यदि कोई गंभीर प्रॉब्लम हो तो फिर आप अपने अजीज़ों से संपर्क साधना शुरू कर देते हैं. कभी-कभी कोई काम नहीं होने पर पूजा-पाठ की आवृति भी आप कर लेते हैं.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

किसी प्राकृतिक अवस्था या पर्यावरण की समस्या पर आपका ध्यान केंद्रित हो सकता है. ऐसे कार्य से जहां आपकी ख्याति बढ़ेगी, वहीं कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की नज़र भी आप पर जाएगी और किसी बड़े राष्ट्रीय एजेंडे में आपकी शिरकत आगे चलकर पर्याप्त लाभ का साधन बन सकती है.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

भाग्यशाली क़ैदी

बात बड़ी अजीब है, लेकिन सच है. दुनिया का सबसे उम्रदराज कैदी अपनी सज़ा पूरी किए बग़ैर रिहा कर दिया गया. गोरखपुर जेल में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे 108 वर्षीय बृजबिहारी की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए जेल प्रशासन ने उसे घर जाने की इजाज़त दे दी. बृजबिहारी पर महाराजगंज के जगन्नाथ मंदिर के महंत रामानुज दास की हत्या का आरोप है. ग़ौरतलब है कि बृजबिहारी ने वर्ष 1987 में इस घटना को अंजाम दिया था. इसे देश की लचर क़ानून व्यवस्था कहें या फिर आरोपी की क़िस्मत कि हत्या के बाइस वर्ष बाद उसे सजा सुनाई गई. हत्या के बाद बृजबिहारी समेत 15 लोगों को गिरफ़्तार किया गया. फिर शुरू हुई क़ानूनी लड़ाई. आरोपियों ने अपने बचाव की काफी कोशिशें कीं, लेकिन पुलिस उनकी दलीलों को ग़लत साबित करती गई.

कई वर्षों तक चली क़ानूनी प्रक्रिया के बाद आरोपियों को दिसंबर 2009 में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई. उस वक़्त बृजबिहारी की उम्र काफी हो गई थी, लेकिन उसे जेल भेज दिया गया. जेल में उसका स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा. पिछले तीन वर्षों के दौरान वह जेल की कोठरी से अधिक अस्पताल में रहा. कैदी की मौत जेल में न हो जाए, इस डर से जेल प्रशासन ने सरकार की इजाज़त लेकर उसे घर भेज दिया. रिहाई के बाद बृजबिहारी को ठूठीवरी थानांतर्गत स्थित उसके गांव बरियापुर पहुंचा दिया गया.

हैकिंग में भारत सबसे आगे

अमेरिका की अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन (आईबीएम) का कहना है कि बीते वर्ष ई-मेल संदेशों में सेंधमारी (फिशिंग) के सबसे ज़्यादा मामले भारत में हुए. कंपनी की ओर से फिशिंग पर जारी रिपोर्ट एक्स फोर्स-2010 के मुताबिक़, वर्ष 2010 में भारत में ई-मेल संदेशों में सेंधमारी की घटना पूरी दुनिया में हुए ऐसे मामलों के 15 फ़ीसदी के क़रीब रही. रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हैकिंग से होने वाले ख़तरों को उजागर किया गया है. इसमें कहा गया है कि हैकिंग के मामले में भारत का पहला नंबर है, वहीं रूस दूसरे नंबर पर है. रिपोर्ट के मुताबिक़, स्पैम संदेशों के ज़रिए किसी के ई-मेल संदेशों की सुरक्षा भेदने के मामले में ब्राजील, अमेरिका, भारत और वियतनाम सबसे आगे हैं. पूरी दुनिया में भेजे जाने वाले स्पैम संदेशों का एक तिहाई हिस्सा इन देशों का है. आईबीएम ने कहा है कि उसने वर्ष 2010 के दौरान क़रीब डेढ़ लाख ई-मेल संदेशों की प्रति सेकेंड प्रेषण सुरक्षा की गहन छानबीन और विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. इस दौरान तक़रीबन आठ हज़ार ई-मेल संदेशों में हैकिंग के ख़तरे पाए गए, जो कि वर्ष 2009 की तुलना में 27 फ़ीसदी अधिक रहे. रिपोर्ट के मुताबिक़, वर्ष 2010 के दौरान हैकरों ने फिशिंग की एक ज़्यादा उन्नत तकनीक स्पीयर फिशिंग भी खोज निकाली है. इससे यह पता चलता है कि साइबर अपराधी अब संख्या के बजाय तकनीकी दक्षता पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि स्पीयर फिशिंग हैकरों द्वारा ईजाद की गई साइबर सेंधमारी की एक नई तकनीक है. साधारण फिशिंग में स्पैम संदेश जहां नामी-गिरामी कंपनियों या भारी-भरकम सदस्य संख्या वाली साइटों के नाम से भेजे जाते हैं, वहीं स्पीयर फिशिंग में ये संदेश व्यक्ति के विश्वसनीय और उससे जुड़े हुए लोगों के ई-मेल आईडी से भेजे जाते हैं. जैसे कि आपके पास आपकी ही कंपनी के आला अधिकारी के ई-मेल आईडी से ऐसा संदेश आ सकता है. ज़ाहिर है कि ऐसे संदेश व्यक्ति बिना शक खोल लेता है और इस तरह हैकर उसके मेल तक एक्सेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं. स्पीयर फिशिंग आम तौर पर साधारण हैकरों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि पेशेवर हैकर इसका इस्तेमाल करते हैं. इसका लक्ष्य वित्तीय, कारोबारी या सुरक्षा संबंधी जानकारियों में सेंध लगाना होता है. यह प्राय: किसी ख़ास कंपनी या समूह को निशाने पर रखते हुए सुनियोजित रूप से की जाती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पाकिस्तान अभी अपनी उलझनों में ही फंसा हुआ है. पी एन एस महरान पर हुआ हमला ओसामा की मौत का सटीक जवाब की तरह पेश किया गया है.

भारत-पाकिस्तान वार्ता

छोटे क़दम बढ़ाए जा सकते हैं

सिद्धार्थ राय

आज भी पाकिस्तान इतिहास की उस घटना, जिसे देश विभाजन कहते हैं, से बाहर नहीं निकल पाया है. पाकिस्तानी मानसिकता आज भी 1947 में ही फंसी हुई है. पाकिस्तान ने हमेशा से भारत विरोध को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा और एकमात्र लक्ष्य दिखाने का प्रयास किया है. पाकिस्तान आज भी भारत को एक पड़ोसी देश की तरह न देखकर हिंदू राष्ट्र की तरह देखता है और यही कारण है कि पाकिस्तान आज भी अपने भारत विरोध से निकल नहीं पाया है. दरअसल, पाकिस्तान ख़ुद को एक इस्लामी देश की तरह देखता है और राजनीतिक एवं विचारधारात्मक पटल पर अपने आपको पूरे इस्लामी जगत का नेता बताता है. इसी कारण पाकिस्तान राष्ट्र व्यवस्था में विश्वास रखते हुए भी एक असफल राष्ट्र बन बैठा है. पाकिस्तान ने कभी अपने आपको एक राष्ट्र के रूप में न देखकर इस्लाम की तलवार समझा है. ज़ाहिर सी बात है कि इस परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान भारत विरोध पर ही टिक सकता है.

वैसे भारत विरोध की भी अपनी राजनीति है. जब देश का विभाजन हुआ तो पाकिस्तानी नेता यह समझ गए थे कि पाकिस्तान को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में बहुत ही कड़े प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं था, जो इस काम को कर सकता. इस वजह से एक शॉर्टकट खोजा गया. यह शॉर्टकट था धर्म. पाकिस्तान की जनता को भी यही समझाया गया है कि भारत ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और जनता बहुत पढ़ी-लिखी नहीं थी, इसलिए उसने मान भी लिया. इसी धार्मिक कट्टरवाद की वजह से पाकिस्तान में आज तक जनतंत्र अपनी जड़ें नहीं जमा पाया है और गाहेबगाहे वहां पर सेना देश की कमान अपने हाथ में ले लेती है. इसी कारण जनतांत्रिक तरीक़े से चुनी गईं सरकारें जब भी भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश करती हैं तो जनता ही सेना को आमंत्रित करती है कि वह देश की कमान संभाल ले. वैसे सेना ने भी सत्ता की कमान आज तक भारत विरोध का बोगस नारा देकर ही अपने हाथ में रखी है.

भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तानी तंत्र का रवैया हमेशा से नकारात्मक रहा है और इसी कारण 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने किसी न किसी कारण भारत को परेशान करने के नए-नए उपाय खोजे. पहले कबायली आक्रमण, फिर खुला युद्ध और फिर कारगिल. पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत की दोस्ती का हाथ झिड़का. पाकिस्तान में यह विचारधारा आम है कि पाकिस्तान भारत विरोध के सहारे बहुत आगे बढ़ सकता है और यह भारत विरोध उसके लिए बहुत कारगर और फ़ायदेमंद साबित हुआ है. वैसे यह सोचना एक हद तक ठीक भी था, क्योंकि भारत विरोध की वजह से ही पहले अमेरिका और फिर चीन की दोस्ती पाकिस्तान की झोली में गिरी. पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीति ठीक समझता है, इसलिए उसे पता था कि यह दोस्ती बस समझौतावादी है, लेकिन जब तक फ़ायदा हो रहा है, तब तक इसे तोड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. इसी विचारधारा से निकला आतंकवाद का राक्षस और आज स्थिति यह हो गई है कि सही मायनों में यह आतंकवाद पाकिस्तान का भस्मासुर बन गया है. पाकिस्तान ने अफ़ग़ान तालिबान को संरक्षण दिया और अमेरिका की दोस्ती निभाई, लेकिन क्या हुआ?

भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिशें की हैं, लेकिन पाकिस्तानी तंत्र का रवैया हमेशा से नकारात्मक रहा है और इसी कारण 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने किसी न किसी कारण भारत को परेशान करने के नए-नए उपाय खोजे. पहले कबायली आक्रमण, फिर खुला युद्ध और फिर कारगिल. पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत की दोस्ती का हाथ झिड़का.

अमेरिका में 9/11 की घटना हुई और पाकिस्तान को आतंकियों से दोस्ती निभाने के लिए अमेरिका के विरुद्ध जाकर भी उन्हें संरक्षण देना पड़ा. वैसे पाकिस्तान ने खेल बहुत ही शातिर तरीक़े से खेला, लेकिन ओसामा का पाकिस्तान में बिना पाकिस्तानियों को बताए मारा जाना पाकिस्तान की कलई खोल गया. पाकिस्तान न चाहकर भी इस खेल में शरीक है. ओसामा के मारे जाने के बाद पाकिस्तान की अपनी हालत ही बद से बदतर हुई है. तालिबान और अलक़ायदा के लड़ाकों ने पाकिस्तान से इसका बदला लेने का ऐलान कर दिया है. देखने में आया है कि पाकिस्तान में आएदिन बम धमाके हो रहे हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी अलक़ायदा लेता है और बताता है कि पाकिस्तान की यही सज़ा है. ऐसे में सेनाध्यक्ष कयानी की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं. कयानी न तो अपने घर में मुंह दिखाने के काबिल रहे हैं और न अमेरिका के साथ लेन-देन का सौदा करने में सक्षम रहे हैं. वैसे अमेरिका ने अभी अपने तेवर बदल लिए हैं और पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद में भारी कटौती होने के आसार हैं. इसी वजह से कयानी अब चीन के सामने हाथ फैलाए बैठे हैं. वैसे यह मदद चीन से उन्हें मिल तो जाएगी, लेकिन यह बात बड़ी संदेहास्पद है कि चीन ने इसकी तुरंत मंज़ूरी नहीं दी. इस कारण कयानी और भी बैकफुट पर चले गए हैं. पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों और लोकतांत्रिक सरकार ने भी ओसामा के मुद्दे पर सेना की नकेल कसने का प्रयास किया है और ज़रदारी पूरे प्रकरण में कयानी के साथ नज़र भी नहीं आए. ज़रदारी की इस दूरी ने यह साफ़ कर दिया है कि कयानी को अपने द्वारा फैलाए आतंकवाद को खुद ही बटोरना पड़ेगा और इसमें वह अकेले हैं. कयानी इस बात से ज़रदारी से काफी खफा भी हैं.

पाकिस्तान में तेज़ी से बदलते हालात पर नज़र डाली जाए तो देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की अफ़ग़ान सरहद से जुड़े इलाक़ों में चरमपंथियों ने अपनी पकड़ इतनी मज़बूत कर ली है कि कयानी भी उनका कुछ बिगाड़ पाने की स्थिति में नहीं हैं. ये इलाक़े खासकर कबायली हैं और यहां पाकिस्तान सरकार की रिट नहीं चलती. अमेरिका ने पाकिस्तान के भारी विरोध के बावजूद इन इलाकों में अपने ड्रोन हमले जारी ही नहीं रखे, बल्कि और तेज़ कर दिए हैं. इसलिए अब पाकिस्तानी जनता को भी लगने लगा है कि कयानी के हाथ से सियासी कमान निकल रही है और इसी कारण अब जनता कयानी के विरोध में खड़ी होने लगी है. ऐसी हालत में निरूपमा राव की पाकिस्तान यात्रा से बहुत अपेक्षा रखना तर्कसंगत नहीं जान पड़ता. वैसे निरूपमा के इस्लामाबाद जाने से पहले बने हालात पर नज़र डाली जाए तो बात कम से कम आगे बढ़ती दिख रही है. अभी हाल में आई एन एस गोदावरी और पी एन एस बाबर के बीच हुई झड़प पर ग़ौर करें, अगर यही हादसा पाकिस्तान में सब कुछ पहले जैसा रहते हुए होता तो हायतौबा मच गई होती, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को बहुत तूल नहीं दिया. साथ ही इस वार्ता से पहले पाकिस्तान सरकार ने यह साफ़ कह दिया कि इस वार्ता में आतंकवाद पर कोई बात पाकिस्तान नहीं करेगा, लेकिन तुरंत ही भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया कि भारत 26/11 पर वृहद चर्चा करेगा. अगर यही सब तब हुआ होता, जब पाकिस्तान के लिए सब ठीक चल रहा होता तो मीडिया के माध्यम से वार्ता से पहले ही माहौल ख़राब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. यह सब कम से कम इस बात की ओर इशारा करता है कि भारत विरोध फ़िलहाल और मुद्दतों बाद पाकिस्तान की प्राथमिकता में एक नंबर पर नहीं है. यही कारण है, भारत इस वार्ता से कम से कम इतना तो लाभ उठा सकता है कि बात थोड़ी-बहुत ही, पर आगे बढ़े.

पाकिस्तान अभी अपनी उलझनों में ही फंसा हुआ है. पी एन एस महरान पर हुआ हमला ओसामा की मौत का सटीक जवाब की तरह पेश किया गया है. कयानी अब बहुत भारी दबाव में काम कर रहे हैं. वैसे भी अमेरिका के बदले तेवर दिखा रहे हैं कि उसने अफ़ग़ानिस्तान में अपने तालिबान विरोधी युद्ध के समीकरण से पाकिस्तान को बाहर निकालने की तैयारी कर ली है. अगर ऐसा नहीं होता तो अल जवाहिरी के अलक़ायदा प्रमुख बनने पर ऐसा बयान क्यों देता कि वह ओसामा की तरह जवाहिरी को भी मार गिराएगा और इस बार भी पाकिस्तान को इस बात की सूचना नहीं दी जाएगी. साथ ही अमेरिका ने अब अफ़ग़ानिस्तान से बाहर निकलने का रास्ता ख़ुद तलाश करना शुरू कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान की भूमिका को न्यूनतम रखा गया है. अमेरिका ने अफ़ग़ान तालिबान से बातचीत ख़ुद ही शुरू कर दी है, जो अब तक पाकिस्तान के माध्यम से होती थी. ज़ाहिर है, भारत विरोध कयानी के दिमाग़ में अभी पहले नंबर पर नहीं है. हो यह सकता है कि कयानी भारत के साथ संबंध सुधारें, ताकि उन पर थोड़ा दबाव कम हो. हो यह भी सकता है कि आशा के विपरीत कयानी भारत विरोध को चरम पर ले जाएं, ताकि पाकिस्तानी जनता और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दिमाग़ पाकिस्तान की कारस्तानियों से हटाया जा सके. ख़ैर जो भी हो, भारत की कूटनीतिक सफलता या विफलता इस बात पर टिकी हुई है कि वह मौजूदा समय को किस तरह, जबकि पाकिस्तान बैकफुट पर है, अपने लिए इस्तेमाल करता है.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

यदि तुमने अपना ख्याल या नज़रिया न बदला तो हज करना बेकार है. खुदा की इबादत करते हैं हम, इबादत का मतलब यही है कि हर मजहब और हर इंसान को अपने बराबर समझो.

बाबा और हज यात्रा

एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, हाजी दिखाई दे तो उससे कह देना कि इस मस्जिद में कभी न आए. यह बात सुनकर शिष्य परेशान हो गए कि साई बाबा ने आज तक किसी को भी मस्जिद में आने से नहीं रोका. केवल हाजी सिद्दीकी के लिए ही ऐसा क्यों कहा? हाजी सिद्दीकी को साई बाबा की बात बता दी गई. हाजी सिद्दीकी को बहुत दुःख हुआ. हज से लौटने के बाद उसने साई बाबा के पास न जाकर बहुत बड़ी भूल की है, उन्हीं की कृपा से तो उसे हज यात्रा नसीब हुई थी.

श्री साई महिमा

श्री साई राम परम सत्य, प्रकाश रूप, परम पावन शिरडी निवासी, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, प्रज्ञा प्रदाता, सच्चिदानंद स्वरूप, परम पुरूष योगीराज, दयालु देवाधिदेव हैं, उनको बार बार नमस्कार.

एक मुसलमान सिद्दीकी की बड़ी इच्छा थी कि किसी तरह वह पवित्र तीर्थ मक्का-मदीना की यात्रा पर जाए, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी न थी कि वह हज के लिए पैसा इकट्ठा कर पाता. वह प्रतिदिन द्वारिका माई मस्जिद में पौधों को पानी देता था. बाबा की धूनी के लिए भी जंगल से लकड़ियां काटकर लाता था, इस आशा से कि कभी साई बाबा की कृपा उस पर हो जाए और वह हज की मुराद पूरी कर दें. एक दिन सिद्दीकी द्वारिका माई मस्जिद के फर्श को पानी से धो रहा था कि अचानक साई बाबा आ गए. साफ-सुथरा फर्श देखा तो हंसकर बोले कि फर्श की सफाई करने में तुम बहुत ही माहिर हो, तुम्हें तो काबा में होना चाहिए था. मेरा ऐसा नसीब कहां, सिद्दीकी ने साई बाबा के चरण छूते हुए कातर स्वर में कहा.

चिंता न करो सिद्दीकी, तुम काबा अवश्य ही जाओगे, बस समय का इंतज़ार करो, साई बाबा ने सिद्दीकी के सिर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा. उस दिन से सिद्दीकी काबा जाने का सपना देखने लगा. सोते-जागते, उठते-बैठते उसे हर समय दिखाई देता कि वह काबे में है.

सिद्दीकी की छोटी सी दुकान थी, जो सामान्य ढंग से चलती थी, पर साई बाबा के आशीर्वाद से उसी दिन से दुकान पर ग्राहकों की भीड़ आश्चर्यजनक ढंग से आने लगी और कुछ ही महीनों में उसके पास हज यात्रा पर जाने के लायक़ रुपये इकट्ठा हो गए. फिर क्या था, वह मक्का-मदीना शरीफ की ओर चल पड़ा. कुछ महीनों के बाद सिद्दीकी हज करके लौट आया. अब वह हाजी सिद्दीकी कहलाने लगा, लोग उसे बड़े आदर-सम्मान के साथ हाजी जी कहकर बुलाते थे. सिद्दीकी को हज से आने के बाद अहंकार हो गया था. कई दिन बीत गए, वह साई बाबा के पास भी नहीं गया और द्वारिका माई मस्जिद भी नहीं गया. एक दिन बाबा ने अपने शिष्यों से कहा, हाजी दिखाई दे तो उससे कह देना कि इस मस्जिद में कभी न आए. यह बात सुनकर शिष्य परेशान हो गए कि साई बाबा ने आज तक किसी को भी मस्जिद में आने से नहीं रोका. केवल हाजी सिद्दीकी के लिए ही ऐसा क्यों कहा?

हाजी सिद्दीकी को साई बाबा की बात बता दी गई. हाजी सिद्दीकी को बहुत दुःख हुआ. हज से लौटने के बाद उसने साई बाबा के पास न जाकर बहुत बड़ी भूल की है, उन्हीं की कृपा से तो उसे हज यात्रा नसीब हुई थी. वह मन ही मन बहुत घबरा गया. साई बाबा का नाराज़ होना उसके मन में घबराहट पैदा करने लगा. किसी अनिष्ट की आशंका से वह रह-रहकर भयभीत होने लगा. उसने निश्चय किया कि वह साई बाबा से मिलने के लिए अवश्य ही जाएगा. साई बाबा नाराज़ हैं, उनकी नाराज़गी दूर करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है.

सिद्दीकी ने हिम्मत की और द्वारिका माई मस्जिद की ओर चल पड़ा.

हाजी सिद्दीकी ने डरते-सहमते मस्जिद में क़दम रखा. हाजी को देखते ही बाबा को क्रोध आ गया. साई बाबा का क्रोध देखकर वह कांप उठा. साई बाबा ने घूरकर उसे देखा. हाजी बुरी तरह से थर्रा गया, फिर भी वह साहस बटोर कर डरते-डरते पास गया और साई बाबा के चरणों पर गिर पड़ा.

सिद्दीकी, तुम हज कर आए, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हाजी का मतलब क्या होता है? बाबा ने क्रोध भरे स्वर में पूछा.

नहीं बाबा! मैं तो अनपढ़ ज़ाहिल हूं, हाजी सिद्दीकी ने दोनों हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा.

हाजी का मतलब होता है त्यागी, तुम में त्याग की भावना है ही नहीं. हज के बाद तुम में विनम्रता पैदा होनी चाहिए थी, लेकिन अहंकार पैदा हो गया. तुम अपने आपको बहुत ऊंचा और महान समझने लगे. हज करने के बाद भी जिस व्यक्ति का मन स्वार्थ और अहंकार में डूबा रहता है, वह कभी हाजी नहीं हो सकता.

मुझे क्षमा कर दो बाबा, मुझसे ग़लती हो गई, हाजी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और बाबा के पैरों से लिपट कर फूट-फूटकर रोने लगा. वह मन ही मन पछता रहा था. उसकी आंखें भर आई थीं. बाबा के पास आकर उसने अपनी ग़लती स्वीकार कर ली थी.

सुनो हाजी, याद रखो कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही खुदा या परमात्मा है. इस दुनिया में रहने वाले सब इंसान, पशु-पक्षी उसी के बनाए हुए हैं. पेड़-पौधे, पहाड़, नदियां उसी की कारीगरी का एक नायाब नमूना हैं. यदि हम किसी को अपने से छोटा या नीचा समझते हैं तो हम उस खुदा की बेअदबी करते हैं.

साई बाबा ने हाजी से कहा, यदि तुमने अपना ख्याल या नज़रिया न बदला तो हज करना बेकार है. खुदा की इबादत करते हैं हम, इबादत का मतलब यही है कि हर मजहब और हर इंसान को अपने बराबर समझो.

हाजी सिद्दीकी ने साई बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया और बोला, बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से आपको शिकायत का मौक़ा नहीं दूंगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

असफलता केवल यही सिद्ध करती है कि सफलता के लिए पूरे प्रयास नहीं किए गए.
स्व. मालती कपूर

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ ख़ाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

वेद में जिस तरह सब कुछ है, उसी तरह प्रेमचंद की कहानियों में सब कुछ है. जगत ब्रह्म का विवर्त है तो आज की ग्राम कथाएं प्रेमचंद की विकृति हैं.

अनंत विजय

दिलचस्प अनुभवों की शाम

बात अस्सी के दशक के अंत और नब्बे के दशक के शुरुआती वर्षों की है. पुस्तकों को पढ़ते हुए बहुधा मन में विचार आता था कि उस पर कुछ लिखूं, लेकिन संकोचवश कुछ लिख नहीं पाता था. ज़्यादा पता भी नहीं था कि क्या और कैसे लिखूं और कहां भेजूं. मैं अपने इस स्तंभ में पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि किताबों को पढ़ने के बाद चाचा भारत भारद्वाज को लंबे-लंबे पत्र लिखा करता था. फिर पत्रों में सहमति और असहमतियां भी होने लगीं. इस पत्र व्यवहार से मुझे समीक्षा का एक संस्कार मिला. जमालपुर में रहता था, वहां के कुछ साहित्यिक मित्रों के साथ उठना-बैठना होने लगा. फिर विनोद अनुपम के कहने पर जमालपुर प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ा, पदाधिकारी भी बना. प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ने के बाद कई गोष्ठियों-बैठकों में बोलने का मौक़ा मिलना शुरू हो गया. लिहाज़ा पुस्तकों और रचनाओं पर तैयारी करने लगा, जिसका फ़ायदा बाद में मुझे समीक्षा लेखन में हुआ. फिर मित्रों के आग्रह पर लघु पत्रिकाओं में कुछ समीक्षाएं भेजीं, जो प्रकाशित भी हुईं. इन सबके पहले मैं हिंदी आलोचना के शिखर पुरुष नामवर सिंह की कई किताबें पढ़ चुका था. सबसे पहले मैंने उनकी किताब-कहानी नई कहानी पढ़ा, फिर कविता के नए प्रतिमान. उन पर केंद्रित पत्र-पत्रिकाओं और समीक्षा ठाकुर द्वारा संपादित किताब-कहना न होगा भी पढ़ा. नामवर जी के लेखन और उनकी समीक्षकीय दृष्टि से गहरे तक प्रभावित था. कहानी नई कहानी में लिखी नामवर सिंह की एक पंक्ति अब तक याद है आज की ग्राम जीवन पर लिखी हुई कहानियां प्रेमचंद की स्वस्थ और प्रवृत्त प्रवृत्ति का अस्वाभाविक, परिवर्तित, कृत्रिम और डिस्टॉर्टेड पुन: प्रस्तुतीकरण है. वेद में जिस तरह सब कुछ है, उसी तरह प्रेमचंद की कहानियों में सब कुछ है. जगत ब्रह्म का विवर्त है तो आज की ग्राम कथाएं प्रेमचंद की विकृति हैं. कहानी नई कहानी में जो लेख संकलित हैं, वे नामवर सिंह ने 1956 से 1965 के बीच लिखे थे, लेकिन उनका उपरोक्त कथन आज भी पूरी तरह से समीचीन है. आज भी ग्रामीण जीवन पर लिखी जा रही कहानियों के संदर्भ में इस बात को कहा जा सकता है और मुझे लगता है कि यह टिप्पणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, जितनी उस वक़्त थी. ख़ैर मैं वर्तमान कहानी पर चर्चा नहीं कर रहा. बात नामवर सिंह की हो रही थी. जमालपुर में जब रह रहा था तो नामवर सिंह को पढ़ते हुए यह लगता था कि काश, उनसे परिचय होता, उनसे बातें कर पाता. कई बार उनको पत्र लिखा, लेकिन डाक में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन नामवर और उनसे जुड़ा कुछ भी मिल जाता तो फ़ौरन पढ़ लेता.

समय के चक्र ने मुझे देश की राजधानी दिल्ली पहुंचा दिया. एक गोष्ठी में नामवर जी को सुना तो उनकी वक्तत्व कला से खासा प्रभावित हुआ. फिर फ्रीलांसिंग का दौर शुरू हुआ. मित्र संजय कुंदन ने राष्ट्रीय सहारा के रविवारीय पृष्ठ के लिए कई परिचर्चाएं करवाईं. उसी के सिलसिले में एक-दो बार नामवर जी से बात हुई. जितनी बार उनसे बात होती तो मुझे कुछ न कुछ नया हासिल हो जाता. नामवर जी से आमना-सामना नहीं हुआ. हिंदी भवन में एक गोष्ठी में नामवर जी ने अपने भाषण के क्रम में बोलते हुए यह कह डाला कि आजकल हिंदी साहित्य में अनंत विजय भी तलवारबाज़ी कर रहे हैं. संदर्भ मुझे

अब याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि उसी दौरान आलोचना पर एक परिचर्चा में मैंने नामवर सिंह की राय को शामिल नहीं किया था. फिर धीरे-धीरे नौकरी की व्यस्तता में लिखना कुछ कम हो गया. नामवर जी से बात करने की इच्छा मन में बनी रही. कई बार उन व्यक्तिगत पार्टियों में बैठा, जिसमें नामवर जी थे. उनको और उनके संस्मरणों और टिप्पणियों को सुनकर हमेशा से उनकी स्मृति और उनके अपडेट रहने की क्षमता पर ताज्जुब होता था.

हाल ही में एक अनौपचारिक कवि गोष्ठी में नामवर सिंह जी से मुलाक़ात हो गई. यह कवि गोष्ठी हिंदी कवि तजेंद्र लूथरा की पहल पर हुई थी, जिसमें वरिष्ठ कवि विष्णु नागर, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, मदन कश्यप, लीलाधर मंडलोई, पंकज सिंह, सविता सिंह के अलावा राजेंद्र शर्मा, रोहतक की कवयित्री शबनम, रमा पांडे, हरीश आनंद और ममता किरण भी थीं. कवि मित्र अरुण आदित्य भी. उस दिन संयोग से विष्णु नागर जी का जन्मदिन भी था. सभी कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया. हमेशा की तरह अरुण आदित्य की कविताएं व्यंग्यात्मक लहज़े में बड़ी बातें कह जाती हैं. उनकी कविता-डर के पीछे कैडर है, सुनकर आनंद आ गया. तजेंद्र लूथरा ने अपनी बेहतरीन कविता-अंतराल का डर सुनाई. यह कविता मैं पहले ही पढ़ चुका था. इसमें कवि के अनुभव संसार का व्यापक फलक और उसको देखने-समझने की उनकी दृष्टि सामने आती है. लक्ष्मी शंकर वाजपेयी और ममता किरण की ख़ासियत यह है कि वे बिना पढ़े कविता बोलते हैं, सुनाते हैं. उनकी शैली उनके काव्य पाठ को एकदम से ऊपर उठा देती है. राजेंद्र शर्मा की हुसैन पर लिखी कविता एकदम से मौजूं थी, लेकिन मंडलोई की दो लाइनों ने महानगरीय जीवन की त्रासदी को एकदम से नंगा कर दिया, सांप काटने से नहीं हुई है देह नीली, कल रात मैं अपने दोस्त के साथ था. सभी कवियों ने दो-दो कविताएं सुनाईं, लेकिन चूंकि विष्णु नागर जी का जन्मदिन था, इसलिए उन्होंने अपने संग्रह से कई कविताओं का पाठ किया. सविता सिंह ने लंबी कविता सुनाई, लेकिन दूर बैठे होने की वजह से मैं कविता ठीक से सुन नहीं पाया. संभवत कविता का शीर्षक था- चांद, तीर और अनश्वर स्त्री. इस कवि गोष्ठी के बाद सबको उम्मीद थी कि नामवर जी कुछ बोलेंगे. संचालन कर रहे तजेंद्र लूथरा और रमा पांडे समेत कई लोगों ने उनसे आग्रह किया, लेकिन नामवर जी ने अपने अंदाज़ में मुंह में पान दबाए सिर्फ़ इतना कहा, आनंद आ गया.

गोष्ठी के बाद नामवर जी से मेरी पहली बार बेहद लंबी बात हुई. उन्होंने यह कहकर मुझे चौंका दिया कि चौथी दुनिया के अपने स्तंभ में तुम अच्छा लिख रहे हो. चौंकते हुए मैंने कहा कि सर, आप देखते हैं! तो उन्होंने फ़ौरन मेरे स्तंभों की कई बातें बताकर मुझे अचंभे में डाल दिया. अपनी प्रशंसा सुनना हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन ख़ुद से उसकी चर्चा अश्लीलता हो जाती है. नामवर जी से फिर हिंदी की रचनाओं पर बात शुरू हुई. हमारी लंबी चर्चा हिंदी के रचनात्मक लेखन में डिटेलिंग के न होने पर हुई. उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि हिंदी के लेखक डिटेलिंग नहीं करते हैं, इस वजह से बहुधा रचनाएं सतही हो जाती हैं. फिर हमारी चर्चा हुसैन पर हुई. नामवर जी ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया. एक बार वह, श्रीकांत वर्मा, हुसैन और कुछ मित्र दिल्ली में टी हाउस के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और हुसैन को एक थप्पड़ मारकर भाग गया. सारे लोग हतप्रभ. यह दौर वही रहा होगा, जब हुसैन हिंदू देवी-देवताओं के चित्र बनाकर विवादित हो चुके थे. इससे हम हुसैन के भारत छोड़ने के डर का सूत्र पकड़ सकते हैं. हालांकि हुसैन के भारत छोड़ने को लेकर मेरी काफी असहमतियां रही हैं. नामवर जी ने एक और बात बताई कि कल्पना के हर अंक में हुसैन के रेखाचित्र छपा करते थे और उसके संपादक बद्री विशाल पित्ती हुसैन के गहरे मित्रों में से थे. हुसैन के बाद नामवर जी से भारतीय राजनीति, लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार आदि पर भी बातें हुईं. नामवर जी का मानना था कि आज भारतीय राजनीति बेहद ख़तरनाक दौर से गुज़र रही है. कांग्रेस और भाजपा पर उन्होंने ख़ुश्चेव के बहाने से एक टिप्पणी की, एक बार ख़ुश्चेव से ग्रेट ब्रिटेन की दोनों पार्टियों यानी लेबर पार्टी और कंजरवेटिव पार्टी के बारे में उनकी राय पूछी गई. ख़ुश्चेव ने उत्तर दिया कि एक बाएं पांव का जूता है और दूसरा दाएं पांव का जूता है. कहने का अर्थ यह कि दोनों आख़िरकार जूते ही हैं.

नामवर जी से तक़रीबन घंटे भर की बातचीत उनको जानने-समझने के लिए काफी थी और यह मेरे लिए एक लाइफटाइम एचीवमेंट जैसा था. जिनके लिखे को पढ़कर लिखना सीखा हो, उनके सामने अपनी बात कहना मेरे लिए एक स्वप्न के सच होने जैसा था. नामवर जी से इतनी लंबी बात करने का अवसर सुलभ कराने के लिए मित्र तजेंद्र लूथरा का आभार.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

सपने इंसान को ज़िंदा रखते हैं

फोटो- प्रभात पाण्डेय

बहुमुखी प्रतिभा के धनी बने और अपने दम पर अंग्रेज़ी साहित्य, संस्कृत के धार्मिक ग्रंथों और व्यापार से जुड़े आर्थिक क़ानून में महारथ हासिल की. इस तरह उन्होंने अर्थशास्त्र, विज्ञान, समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र और खगोल शास्त्र में विद्वता प्राप्त की. 24 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ई डी सैस्सन मिल की बागडोर अंग्रेज़ों के हाथों से ले ली, जो उस समय भारत की सबसे बड़ी कपड़ा मिल थी. उन्होंने अपना समस्त जीवन विविध प्रकार के उद्यमों को विकसित और स्थापित करने में लगा दिया, जैसे चीनी, कपड़ा और अभियांत्रिकी आदि. इंदौर में वह हुकुमचंद मिल्स के चेयरमैन रहे और 1961 में उन्होंने प्रबंधन में मज़दूरों की भागीदारी के लिए एक योजना बनाई, जिसका शुभारंभ पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किया था. समाजवाद: एक अध्ययन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की किताब इंटेलिजेंट वोमंस गाइड टू सोशलिज्म का रूपांतरण है और इसे तभी छपवाया गया, जब जय प्रकाश नारायण ने इस किताब की प्रस्तावना लिखना स्वीकार किया. यह किताब 1962 में छपी.

फ़िरदौस ख़ान
firdaus@chauthiduniya.com

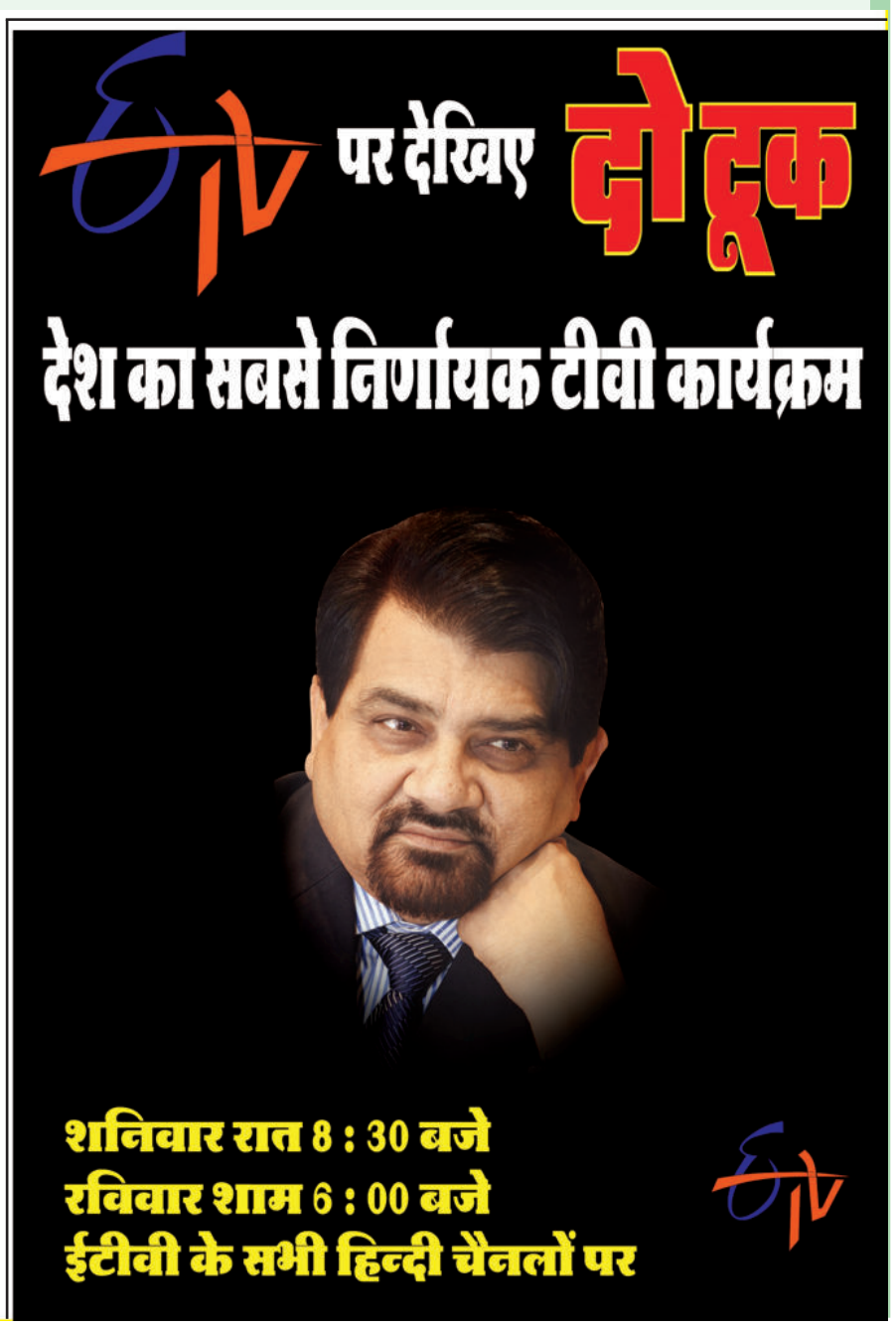

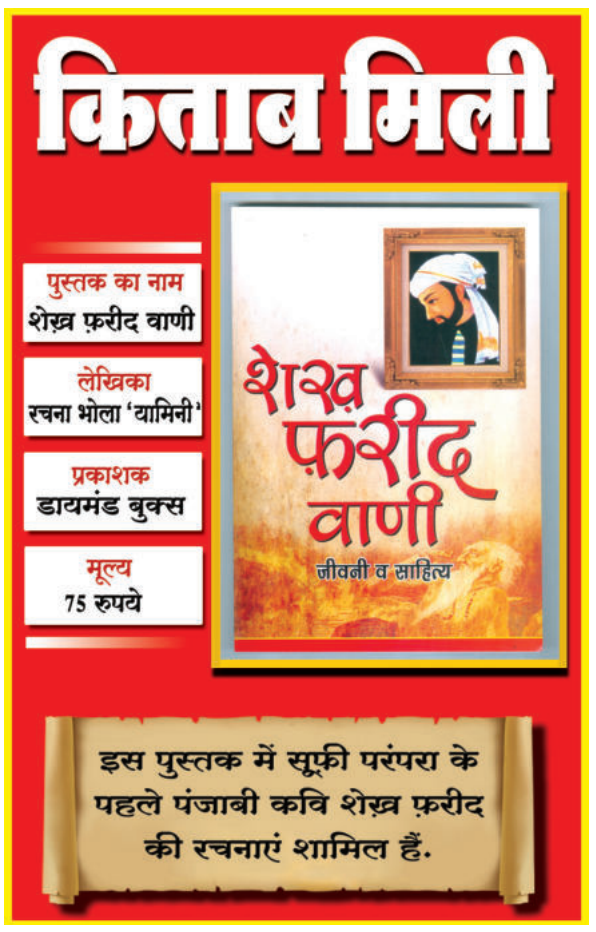

सपने कभी नहीं मरने चाहिए, क्योंकि सपने ही इंसान को ज़िंदा रखते हैं. हम लोग ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं, जब देश में अच्छे भविष्य की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है. यह उद्‌गार प्रख्यात साहित्कार डॉ. नामवर सिंह ने एम आर मोरारका फाउंडेशन और प्रज्ञा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में बीते 19 जून को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित तीन मूर्ति भवन में आयोजित एक समारोह में प्रख्यात उद्यमी एवं समाजसेवी महावीर प्रसाद आर मोरारका की पुस्तक समाजवाद: एक अध्ययन का लोकार्पण करते हुए व्यक्त किए. उन्होंने कहा कि हर तरफ़ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है. ऐसे में यह किताब हमें रोशनी की एक किरण दिखाती है. यह किताब वर्ष 1962 में लिखी गई थी, लेकिन इसका लोकार्पण कई दशकों बाद अब किया जा रहा है और कमल मोरारका जी ने कुछ सोचकर ही यह फ़ैसला किया होगा. इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं. समारोह की अध्यक्षता डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने की और मुख्य अतिथि शरद यादव थे. मुख्य वक्ता के तौर पर राहुल देव और अरविंद मोहन भी मौजूद थे.

इस अवसर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक शरद यादव ने कहा कि भारत में समाजवाद का रास्ता खेतों से होकर निकलता है. अगर देश में समाजवाद को मज़बूत करना है तो इसके लिए सभी खेतों को पर्याप्त सिंचाई जल मुहैया कराना होगा. खेतों को पानी मिलने पर ही संपन्नता आएगी और किसान ख़ुशहाल होंगे. डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि समाजवाद: एक अध्ययन के लेखक महावीर प्रसाद आर मोरारका ने अर्थव्यवस्था जैसे कठिन विषय को बहुत ही सरल शब्दों में प्रस्तुत किया, जिससे एक आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकता है. उन्होंने कहा कि कमाल की बात यह है कि समाजवाद जैसे विषय पर एक मारवाड़ी सेठ ने यह किताब लिखी है. हैरानी इस बात की है कि उन्होंने यह किताब उस समय लिखी थी, जब हिंदी में मार्क्स की प्रख्यात किताब दास कैपिटल का अनुवाद भी नहीं हुआ था. इसके अलावा इस किताब में महावीर प्रसाद जी ने कई अंग्रेज़ी लेखकों की किताबों का हवाला भी दिया है.

समारोह में सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने पुस्तक का संक्षिप्त परिचय दिया. उन्होंने कहा कि लेखक ने किसानों और मज़दूरों की पीड़ा को समझा और अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया, उसे उन्होंने इस पुस्तक के ज़रिये सबके सामने रखा. समारोह को राहुल देव और अरविंद मोहन ने भी संबोधित किया और इस किताब की सराहना की. मंच संचालन चौथी दुनिया के प्रधान संपादक संतोष भारतीय ने किया. समारोह में अनेक गणमान्य लोगों ने शिरकत की. ग़ौरतलब है कि महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म जुलाई, 1919 में झुंझुनू ज़िले के नवलगढ़ में एक सामान्य व्यापारी परिवार में हुआ था. यह क्षेत्र राजस्थान के शेखावाटी में आता है. उनका परिवार 1930 के दशक में मुंबई में बस गया. उनकी औपचारिक शिक्षा बहुत ही कम रही और 15 साल की कम आयु में ही वह पारिवारिक व्यापार से जुड़ गए. स्वाध्याय और कड़ी मेहनत से वह

ऍप्स के जरिए दर्शक टच स्क्रीन क्वर्टी की-बोर्ड का इस्तेमाल वॉल्यूम एडजस्ट करने से लेकर कंटेंट सर्च करने तक के लिए किया जा सकता है.

जम्मू-कश्मीर में पर्यटन विकास के संबंध में फिक्की द्वारा श्रीनगर में आयोजित एक बैठक में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री सुल्तान अहमद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एवं सुबोधकांत सहाय.

समर कैंप की मस्ती

एक तरफ मित्र मंडली तो दूसरी ओर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अभिभावकों एवं स्कूल के दबाव के चलते अक्सर बच्चों का बचपन कहीं खो जाता है. वे दिन भर घर में टीवी के सामने बैठे रहते हैं या फिर दोस्तों के साथ कुछ समय बिताते हैं. इस तरह वे एक फिक्स सी दिनचर्या बिताने को मजबूर होते हैं. वे कुछ नया सीखने, तलाशने और नए आयाम टटोलने से दूर रहते हैं. उनकी दिनचर्या की इसी एकरसता को तोड़ने के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक अनूठी पहल की है. अपने कर्मचारियों के साथ जुड़ाव को मजबूत बनाने के मकसद से एलजी ने पिछले दिनों दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न जाने-माने स्कूलों के साथ नाता जोड़ा और अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए वहां समर कैंप लगाए. एलजी इंडिया के मानव संसाधन प्रमुख उमेश ढल ने कहा, एलजी अपने कर्मचारियों के विकास पर बराबर ध्यान देती है और सिर्फ उन तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि उनके परिवारीजनों तक भी पहुंचती है. इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी हर साल अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन करती है, ताकि इस बहाने उनकी छिपी प्रतिभा सामने आ सके और भविष्य में उनके लिए सहायक साबित हो सके. इन कैंपों में हर साल करीब 300 बच्चे हिस्सा लेते हैं. इन कैंपों के प्रायोजन की पूरी जिम्मेदारी एलजी ने संभाली है और इनमें बच्चों को खेलकूद, आर्ट एवं क्राफ्ट, ड्रैमेटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग के अलावा गायन और नृत्य जैसी विभिन्न रोचक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिला. बच्चों ने अपनी पसंद और प्राथमिकता के मुताबिक गतिविधियों का चयन किया और विशेषज्ञों ने उनका मार्गदर्शन किया. इस प्रकार के कैंपों के आयोजन का मकसद बच्चों में ताज़गी का एहसास भरना और उन्हें अपने भीतर छिपे हुनर को सामने लाने का मौका प्रदान करना था. इन कैंपों में बच्चों का व्यक्तित्व निखारने के साथ-साथ उन्हें अनुशासन और बुनियादी मूल्यों के बारे में भी सिखाया जाता है. कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागी बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे उनके अभिभावकों के साथ-साथ एलजीईआईएल की प्रबंधन टीम ने भी देखा और सराहा.

एलजी की अत्याधुनिक स्मार्ट टीवी कार्य प्रणाली पर आधारित बीडी 670 में प्रयोग में आसान ऑन स्क्रीन इंटरफेस की सुविधा है, जिसकी बदौलत प्रीमियम कंटेंट की विस्तृत रेंज के साथ-साथ पिकासा, एक्यू वैदर, यू-ट्यूब, आई-प्ले टीवी, गूगल मैप्स और वी-ट्यूनर समेत कई प्रमुख ग्लोबल कंटेंट प्रदाताओं तक आसानी से एक्सेस सुविधा मिलती है.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स अपने ग्राहकों के लिए 3-डी होम एंटरटेनमेंट अनुभव में विस्तार करने जा रही है और इस मकसद से कंपनी ने ब्लू-रे थ्री डी प्लेयर-बीडी 670 बाजार में उतारा है, जो सर्वश्रेष्ठ 3-डी मनोरंजन के साथ-साथ अन्य डिजिटल उपकरणों से अबाधित कनेक्टिविटी की सुविधा दिलाता है. एलजी की अत्याधुनिक स्मार्ट टीवी कार्य प्रणाली पर आधारित बीडी 670 में प्रयोग में आसान ऑन स्क्रीन इंटरफेस की सुविधा है, जिसकी बदौलत प्रीमियम कंटेंट की विस्तृत रेंज के साथ-साथ पिकासा, एक्यू वैदर, यू-ट्यूब, आई-प्ले टीवी, गूगल मैप्स और वी-ट्यूनर समेत कई प्रमुख ग्लोबल कंटेंट प्रदाताओं तक आसानी से एक्सेस सुविधा मिलती है. बीडी 670 के स्मार्ट टीवी फंक्शन की बदौलत दर्शकों को एलजी ऍप्स की सुविधा भी मिलेगी. कनेक्टिविटी के लिए बीडी 670 में वाई-फाई डायरेक्ट लगा है, जिसकी मदद से दर्शकों को दूसरे उपकरणों पर भी मल्टी मीडिया कंटेंट को स्ट्रीम करने की सुविधा मिलती है और इसके लिए अलग से इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती.

इसके अलावा डिजिटल लिविंग नेटवर्क एलायंस डीएलएनए कार्य प्रणाली के चलते अनगिनत कंटेंट विकल्प मिलते हैं, जिनसे अन्य डीएलएनए-अनुपालक उपकरणों, जैसे डिजिटल कैमरों या पीसी आदि में स्टोर किए गए म्यूजिक़, मूवीज़ और फोटो आदि को आसानी से एक्सेस किया जा सकता है. यूज़र्स अपने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल फोन पर स्पेशल ऍप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो हैंडसेट को ही बीडी 670 के लिए रिमोट कंट्रोल में बदल देता है.

ऍप्स के जरिए दर्शक टच स्क्रीन क्वर्टी की-बोर्ड का इस्तेमाल वॉल्यूम एडजस्ट करने से लेकर कंटेंट सर्च करने तक के लिए किया जा सकता है. बीडी 670 3-डी ब्लू-रे डिस्क प्लेयर सभी तरह की खूबियों से लैस उपकरण है, जो फुल एचडी में ब्लू-रे 3-डी डिस्क प्लेबैक के साथ-साथ होम नेटवर्किंग और इंटरनेट आधारित कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है. इस रेंज में दो 3-डी ब्लू रे प्लेयर पेश किए गए हैं, बीडी 670 और बीएक्स 580, जिनकी कीमत क्रमश: 16,000 और 20,000 रुपये है.

कैच के लाजवाब ड्रिंक्स

गर्मी के मौसम में इस बार धूप की तपिश से आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास फिज़ी ड्रिंक्स के बदले अब है कैच की नई इंस्टैंट मिक्स एन ड्रिंक रेंज़, जो आपको तुरंत ऊर्जा और ताजगी से भर दे. कैच द्वारा पेश की गई नई रेंज़ में है मजेदार आम पन्ना, चटपटा जलजीरा और सदाबहार नींबू पानी, जो चुटकी में तैयार किया जा सकता है. ये पेय पदार्थ हमेशा पसंदीदा रहे हैं और इनके मिक्सचर में ठंडा पानी मिलाकर ताजगी का अनोखा अनुभव किया जा सकता है. यह न केवल ऊर्जा से भरपूर बनाकर आप में नई जान डाल देते हैं, बल्कि बिल्कुल घर जैसा स्वाद भी देते हैं.

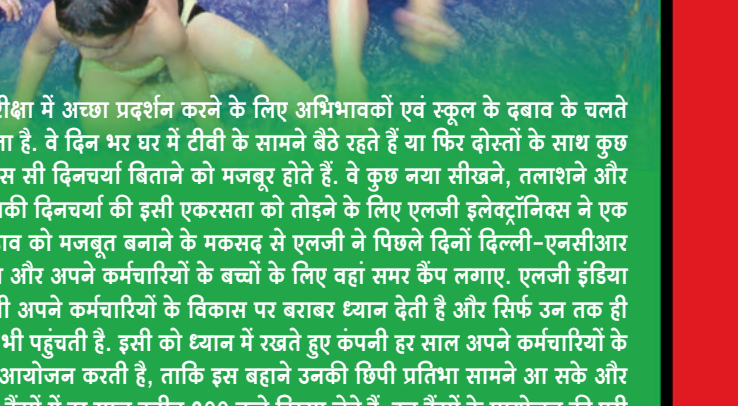

कैच उत्पादों की इस नई कैटेगरी में ग्राहकों को भारत के पारंपरिक पेय पदार्थों का मजा मिलेगा. इन्हें तैयार करना भी बहुत आसान है, मिक्सचर में केवल ठंडा पानी मिलाना पड़ता है. इनकी गुणवत्ता के मामले में रत्ती भर समझौता नहीं किया गया है.

नई रेंज़ की मार्केटिंग की जिम्मेदारी रागिनी खन्ना ने संभाली है. कैच की मिक्स एन ड्रिंक रेंज देश भर में मौजूद ग्रॉसरी स्टोर्स और सुपर मार्केट में उपलब्ध है. एक व्यक्ति के लिए एक सैशे पर्याप्त है, जिसकी कीमत 3 रुपये है और 5 रुपये वाला सैशे दो लोगों की जरूरत पूरी करता है. इतना ही नहीं, दक्षिण भारत के लिए आम पन्ना और नींबू के कई अन्य फ्लेवर हैं. इस नई रेंज के साथ कैच की उत्पाद शृंखला बेहतर और अधिक दमदार हो गई है.

वायरलेस कांपैनियन 2 की-बोर्ड माउस

जेब्रोनिक्स ब्रांड के तहत कंप्यूटर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामान, संचार उपकरणों से जुड़े उत्पाद और एसेसरीज की आपूर्ति करने वाली भारत की अग्रणी कंपनी टॉप नॉच इंफोट्रॉनिक्स ने की-बोर्ड और माउस का कॉम्बो वायरलेस कांपैनियन 2 पेश किया है, जो आपको वायर के जंजाल से मुक्ति दिलाता है. 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस तकनीक पर आधारित नया कांपैक्ट की-बोर्ड एवं माउस की रेंज काफी लंबी यानी 9 मीटर तक है. इसकी अल्ट्रा रिलायबल वायरलेस कनेक्टिविटी काम के दौरान किसी भी तरह की देरी, व्यवधान से भी पूरी तरह बचाती है. की-बोर्ड मल्टी मीडिया टाइप है, जिसमें 13 मल्टी मीडिया फंक्शन कीज हैं. इसका खूबसूरत डिजाइन और स्लिम प्रोफाइल इसे आकर्षक और इस्तेमाल में आसान बनाता है. इस सेट का माउस 800 डीपीआई हाई-प्रीसीजन ऑप्टिकल सेंसर वाला है. माउस 2 एएए बैट्री से चलता है, जबकि की-बोर्ड के लिए 1 एएए बैट्री चाहिए. यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करने में दोनों डिवाइस के लिए एक ही रिसीवर काम करता है. यह इतना छोटा है कि एक बार प्लग कीजिए और भूल जाइए. की-बोर्ड और माउस, दोनों में लगा स्मार्ट पावर मैनेजमेंट बैट्री की लाइफ बढ़ाता है.

जेब्रोनिक्स वायरलेस कांपैनियन 2 की-बोर्ड और माउस कॉम्बो स्टाइल में आधुनिक है. मैट-ब्लैक फिनिश हल्के लाल ट्रिम के साथ इसके खूबसूरत लुक को उभारता है. इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि इस्तेमाल में आराम हो और ज्यादा समय तक आप इसे उपयोग में ला सकें. साथ ही यह जहां आपके डेस्कटॉप की शान बढ़ाए, वहीं जगह की भी बचत करे. अपनी तमाम खूबियों के चलते यह किसी के लिए भी खरीदने लायक है. खूबसूरती और गुणवत्ता के मामले में बेजोड़ उत्पाद पेश करने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए जेब्रोनिक्स ने अपने वायरलेस कांपैनियन 2 की-बोर्ड और माउस को मात्र 825 रुपये की किफायती कीमत पर पेश किया है. इसके साथ एक साल की रीप्लेसमेंट वारंटी भी मिलती है. यह देश के किसी भी अग्रणी आईटी स्टोर पर उपलब्ध है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

मैदान पर तैनात अंपायरों ने टीम के कप्तान राम नरेश सरवन को गेल को संभालने की हिदायत दी. उस दौरान गेल को उनकी हरकत केलिए दंडित किया गया.

विवादों ने तोड़ी करियर की कमर

राजेश एस कुमार

वेस्टइंडीज क्रिकेट इस वक़्त अपने उसी दौर से गुजर रहा है, जिस दौर से भारतीय हॉकी टीम गुजर रही है. लगातार हार का सामना और खिलाड़ियों के बढ़ते विवाद ने इस टीम को आज ऐसे मुक़ाम पर खड़ा कर दिया है, जहां इसके भविष्य पर सवाल खड़े होने लगे हैं. क्रिकेट से लगाव रखने वाले हर एक शख़्स को वेस्टइंडीज क्रिकेट का स्वर्णिम दौर याद होगा. वह दौर ऐसा था, जब अफ़्रीकी खिलाड़ियों के सामने अच्छे-अच्छे बल्लेबाज़ों के बैट कांप जाते थे. उस वक़्त शायद ही किसी को इस बात का एहसास रहा होगा कि वेस्टइंडीज क्रिकेट का एक ऐसा दौर भी आएगा, जब ख़ुद उसके ही खिलाड़ी बग़ावत पर उतर आएंगे. इस दौर से वेस्टइंडीज एक दिन तो उबर ही जाएगा, लेकिन खामियाजे के तौर पर उसे कई बेहतरीन खिलाड़ी खोने पड़ रहे हैं. इसमें अव्वल नाम तो आईपीएल में जलवा बिखेरने वाले धुआंधार बल्लेबाज़ क्रिस गेल का है. इस बेहतरीन क्रिकेटर के करियर की कमर ख़ुद उसके द्वारा पैदा किए गए विवादों ने तोड़कर रख दी है. हाल यह है कि क्रिस गेल का करियर लगभग ख़त्म माना जाने लगा है.

ग़ौरतलब है कि क्रिस गेल की टीम में वापसी की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है. वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड डब्ल्यूआईसीबी और गेल के बीच हुई गर्मागर्म बैठक के बाद अब इस विस्फोटक बल्लेबाज़ के करियर पर भी पूर्ण विराम लगता दिखाई दे रहा है. भारत के ख़िलाफ़ वन डे सीरीज में जगह न बना पाने के बाद गेल द्वारा टेस्ट टीम में स्थान तलाशने की कोशिश भी नाकाम हो गई. आप सोच रहे होंगे कि क्रिस गेल के साथ वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? दरअसल, इसमें कुछ क्रिकेट बोर्ड द्वारा पैदा की हुई ग़लतफ़हमियां तो हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़िम्मेदार ख़ुद गेल द्वारा पैदा किए गए विवाद हैं. इस बात से तो सभी वाक़िफ़ हैं कि क्रिस गेल और विवादों का साथ चोली-दामन जैसा है. दरअसल, इस विवाद की असली वजह यह थी कि डब्ल्यूआईसीए ने गेल को टीम की कप्तानी नहीं सौंपी थी. इसके पीछे वजह यह बताई गई कि उन्होंने बोर्ड के साथ रिटेनर क़रार नहीं किया था. जबकि इस खिलाड़ी को लगा कि क़रार पर हस्ताक्षर न करने का असर उसकी कप्तानी पर नहीं पड़ेगा. बोर्ड ने हालांकि कहा कि कप्तान बनने के लिए खिलाड़ी का रिटेनर क़रार पर हस्ताक्षर करना ज़रूरी है. बैठक के दौरान डब्ल्यूआईसीए चाहता था कि बोर्ड गेल को टीम में शामिल कर ले और रेडियो साक्षात्कार के दौरान की गईं उनकी टिप्पणियों को व्यक्तिगत माना जाए, जबकि बोर्ड चाहता है कि गेल उन बयानों का खंडन करें, लेकिन गेल ने क्रिकेट बोर्ड के पिछले महीने उसके ख़िलाफ़ रेडियो साक्षात्कार के दौरान की गई टिप्पणियों का खंडन करने के आग्रह को ख़ारिज कर दिया. इसी बात ने गेल के ख़िलाफ़ बोर्ड को भड़का दिया. इसके अलावा एक वजह यह भी थी कि आईपीएल के दौरान गेल ने अपने देश से ज़्यादा आईपीएल को तवज्जो दी.

सूत्रों के मुताबिक़, पिछले दिनों बोर्ड और गेल के बीच चार घंटे चली बैठक एक समय काफी उग्र हो गई थी और राम नारायण एक समय हिलेयर पर हमला करने के क़रीब थे. दरअसल, डब्ल्यूआईसीए और बोर्ड के बीच विवाद आईपीएल शुरू होने से पहले ही बढ़ गया था, क्योंकि गेल उसी स्थिति में वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम की ओर से खेलना चाहते थे, यदि बोर्ड उन्हें उतना पैसा चुकाए, जितना गेल को आईपीएल में मिल रहा है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर ने गेल को आठ लाख डॉलर की रकम देकर आईपीएल के लिए ख़रीदा था.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि गेल बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी तीखी प्रतिक्रिया ने हमेशा उन्हें कठघरे में खड़ा किया है. सिर्फ़ एक बयान ने क्रिस गेल को हाशिए पर ला दिया है. लेकिन यह पहली बार नहीं है, जब गेल ने बाग़ी तेवर दिखाए हैं. वर्ष 2005 में भी क्रिस और बोर्ड के बीच विवाद हो चुका है. 2005 तक वेस्टइंडीज क्रिकेट को केबल्स एंड वायरलेस नामक कंपनी प्रायोजित करती थी. बोर्ड के साथ कंपनी के कुछ खिलाड़ियों से निजी क़रार भी थे, लेकिन 2005 में विंडीज बोर्ड ने केबल्स एंड वायरलेस की प्रतिद्वंद्वी कंपनी डिजिसेल के साथ क़रार कर लिया. बोर्ड ने इस अनुबंध के तहत टीम के खिलाड़ियों को केबल्स एंड वायरलेस से संबंध तोड़ने के आदेश दिए, लेकिन क्रिस गेल समेत कुछ खिलाड़ियों ने बोर्ड की इस बात को मानने से इंकार कर दिया. नतीजतन, दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट से गेल समेत सभी बाग़ी खिलाड़ियों का पत्ता साफ हो गया. हालांकि गेल ने बोर्ड के आगे झुकते हुए केबल्स एंड वायरलेस से क़रार ख़त्म कर लिया और उन्हें दूसरे टेस्ट की टीम में शामिल कर लिया गया. इसके बाद 2006 में गेल स्लेजिंग के प्रकरणों में लिप्त रहे. पहले न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट मैच में गेल अपना आपा खो बैठे. उसके बाद भारत में आयोजित चैंपियंस ट्राफी 2006 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच में वह माइकल क्लार्क से उलझ गए. गेल ने पहले क्लार्क पर ताना कसकर उन्हें उकसाया और फिर जब क्लार्क भड़क गए तो दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई.

मैदान पर तैनात अंपायरों ने टीम के कप्तान राम नरेश सरवन को गेल को संभालने की हिदायत दी. उस दौरान गेल को उनकी हरकत के लिए दंडित किया गया. 2007 में क्रिस गेल ने एक बार फिर बाग़ी तेवर दिखाते हुए वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड की सार्वजनिक तौर पर आलोचना कर डाली. इंग्लैंड दौरे पर हुई इस घटना से गुस्साए बोर्ड ने गेल को फटकार लगाई और चेतावनी दी. 2009 में इंग्लैंड दौरे पर ही क्रिस गेल ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि वह वेस्टइंडीज टीम की अगुवाई नहीं करना चाहते, क्योंकि यह बहुत तनाव भरा काम है. साथ ही उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह बहुत ख़ुश होंगे, यदि 20-20 क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट का खात्मा कर देता है. टेस्ट क्रिकेट के भविष्य पर दिए इस विवादास्पद बयान पर गेल की जमकर खिंचाई हुई थी. इन सबके बाद कैरिबियाई बोर्ड के रवैये पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठाकर गेल ने विवाद खड़ा कर दिया. एक साक्षात्कार के दौरान गेल द्वारा दिए गए इस बयान के बाद बोर्ड ने उन्हें टीम से बाहर कर दिया.

अगर इन सब विवादों पर ग़ौर किया जाए तो एक बात साफ हो जाती है कि अगर क्रिस गेल जैसा खिलाड़ी इतने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद टीम में अपनी जगह को लेकर संघर्ष कर रहा है तो इसमें बोर्ड से ज़्यादा ज़िम्मेदारी उसके ख़ुद के पैदा किए विवादों की है. इन विवादों से जितना नुक़सान इस खिलाड़ी का होगा, उससे कहीं ज़्यादा उनके चाहने वाले हज़ारों प्रशंसकों और बेहतरीन क्रिकेट के शौकीनों का होगा.

rajeshy@chauthiduniya.com

28 साल बाद लौटा खिलाड़ी

पहले ही मैच में एक शतक और एक दोहरा शतक लगाने वाले लारेंस रोव ने अपने वतन लौटने का फ़ैसला किया है. रंगभेद युग के दौरान दक्षिण अफ़्रीका का दौरा करने के कारण टीम से निकाल दिए गए बाग़ी खिलाड़ी लारेंस रोव ने 28 साल बाद वेस्टइंडीज क्रिकेट के प्रशंसकों से अपने किए पर माफी मांगी है. रोव ने कहा, मैं अपने किए के लिए जमैका क्रिकेट संघ और सभी क्रिकेट प्रेमियों से माफी मांगता हूं. रोव वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज़ों में से एक थे. कैरिबियाई दिग्गज गैरी सोबर्स ने रोव के लिए कहा था, रोव एक शानदार खिलाड़ी है. मुझे नहीं लगता, इससे बेहतर तकनीक किसी और खिलाड़ी के पास होगी. वह वेस्टइंडीज का सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ बनने की क्षमता रखता है. यही नहीं, पूर्व गेंदबाज़ी दिग्गज माइकल होल्डिंग ने कहा था, मैंने आज तक ऐसा बल्लेबाज़ नहीं देखा. कितनी सफाई से वह गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाते हैं, यह वाकई अद्‌भुत है. रोव के करियर पर काला धब्बा साल 1982 में लगा, जब वह रंगभेद दौर से गुजर रहे दक्षिण अफ़्रीका के विवादास्पद दौरे पर गए थे. स्थानीय लोगों ने इस हरकत की जमकर आलोचना की. इसके बाद रोव को जमैका में बहिष्कृत कर दिया गया था. अपने लोगों का बहिष्कार झेलने वाले रोव इस कांड के बाद अमेरिका के मियामी शहर में जाकर बस गए थे, लेकिन 28 साल बाद रोव अपने देश लौटने का मन बना रहे हैं. वेस्टइंडीज के इस पूर्व बल्लेबाज़ ने अपने पदार्पण मैच की पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में दोहरा शतक जमाया था. इस रिकार्ड को आज तक कोई बल्लेबाज़ नहीं तोड़ पाया है. 31 साल की उम्र में घास से एलर्जी और कम होती आंखों की रोशनी के कारण रोव ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

ईडन गार्डन का कमबैक

भारत में क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन को घरेलू मैचों के तहत तीन मैचों की मेजबानी मिली है, जिससे बीसीसीआई काफी खुश है. बीसीसीआई प्रमुख जगमोहन डालमिया ने इस बात पर खुशी प्रकट करते हुए कहा कि वाकई में क्रिकेट कोलकाता और ईडन गार्डन दोनों के लिए काफी अच्छा है. इस बात से बंगाल क्रिकेट संघ (कैब) भी काफी खुश है. डालमिया ने कहा, जब हमसे इंग्लैंड वाले मैच की मेजबानी छीनी गई थी, तब मैं बहुत ज्यादा निराश था, लेकिन एक बार फिर से हम पर भरोसा किया गया है. यह खुश होने वाली बात है. बीसीसीआई कार्यक्रम निर्धारण समिति की बैठक में इंग्लैंड के खिलाफ एकमात्र ट्वेंटी-20 मैच के अलावा पांच वन डे मैचों की सीरीज के एक मैच और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में से एक मैच की मेजबानी ईडन गार्डन को सौंपी गई.

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 4 जुलाई–10 जुलाई 2011

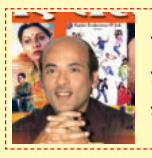

फिल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद की कहानी एक इतिहास है. फिल्म लोगों को ख़ूब पसंद आ रही थी. जिन गानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वही गाने अभूतपूर्व कामयाबी की वजह बन गए.

हिट शो के लिए तरसते शो मैन–2

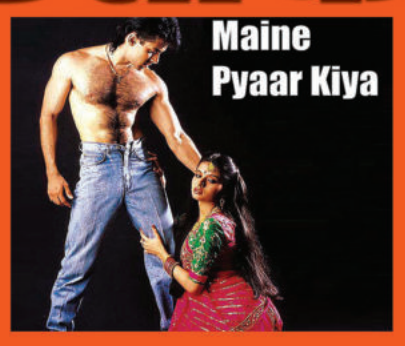

परिवार में फंसे प्रेम के सूरज

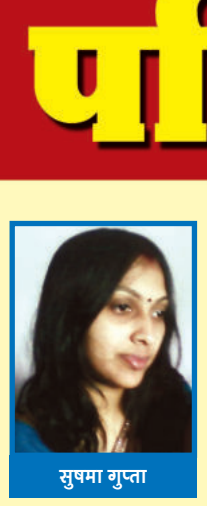

सुषमा गुप्ता

हिंदी फिल्मों में सूरज बड़जात्या की तूती बोलती थी, लेकिन आज वे हिट के लिए तरस रहे हैं. 1994 में पांच साल के इंतज़ार के बाद सूरज बड़जात्या अपनी दूसरी फिल्म हम आपके हैं कौन लेकर आने को तैयार थे. फिल्म से पहले संगीत रिलीज़ हुआ. संगीत के बाज़ार में आते ही सूरज बड़जात्या की आलोचना शुरू हो गई. समीक्षकों ने गाने में मैंने प्यार किया की धुन इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए. गानों की संख्या को लेकर भी सवाल उठाए गए कि इतने गानों के बाद फिल्म में बचेगा क्या? आलोचनाओं से बेपरवाह सूरज बड़जात्या फिल्म की रिलीज़ को लेकर रणनीति बना रहे थे. यह वह दौर था, जब सिनेमा पर टीवी और पायरेसी का ख़तरा मंडरा रहा था. सूरज बड़जात्या को यह भी साबित करना था कि उनकी पहली हिट महज़ इत्तेफ़ाक़ नहीं, वह सिनेमाई समझ रखने वाले कलाकार हैं. हम आपके हैं कौन रिलीज़ हुई. तकनीक के साथ और बेहद कम प्रिंटों में. मुंबई जैसे शहर में यह फिल्म केवल एक प्रिंट में रिलीज़ हुई. दरअसल, जिन थिएटरों में फिल्म लगी, राजश्री वालों ने पहले उन्हें दुरुस्त कराया और फिर डिजिटल फिल्म एवं डॉल्बी साउंड के साथ फिल्म रिलीज़ की.

फिल्म रिलीज़ हुई और उसके बाद की कहानी एक इतिहास है. फिल्म लोगों को ख़ूब पसंद आ रही थी. जिन गानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, वही गाने अभूतपूर्व कामयाबी की वजह बन गए. बेहद सिचुएशनल और कहानी को आगे बढ़ाने वाले गाने. यह फिल्म नदिया के पार का आधुनिक वर्जन थी. फिल्म के केंद्र में एक शादी और उस शादी के इर्द-गिर्द पनपता एक प्यार, लेकिन जब परिवार का सवाल आता है तो प्यार करने वाले अपने प्यार का त्याग करने को तैयार हो जाते हैं. माधुरी की अदाएं, लता के गाए गाने, राम-लक्ष्मण का ज़ुबां पर चढ़ने वाला संगीत, कसा हुआ डायरेक्शन और शानदार पटकथा, सबने फिल्म को अभूतपूर्व कामयाबी दिलाई. लगातार चलने के मामले में इस फिल्म ने कमाल ही कर दिया. क़स्बानुमा शहरों में भी इसने 100 दिन पूरे किए. फिल्म के सफल होने की एक और वजह थी. यह वजह थी, माधुरी-सलमान की लव स्टोरी. दीदी के देवर और भाभी की बहन की नोंकझोंक के साथ उनका प्यार इशारों ही इशारों में चुपके-चुपके परवान चढ़ता है. ज़ुबां से नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज से प्यार की कहानी बयां करने की सूरज बड़जात्या की ख़ूबी ने कमाल कर दिया. इसके अलावा शादी के प्रसंग की हर छोटी-बड़ी बातें, फिल्म की उत्सवधर्मिता ने आम दर्शक को अपने साथ ऐसा जोड़ा कि सबको फिल्म में अपने रिश्ते, अपनी ख़ुशियां दिखाई दीं.

इसके अलावा फिल्म साफ-सुथरी होने और पारिवारिक प्रसंग के चलते काफी समय बाद हिंदी सिनेमा का दर्शक पूरे परिवार के साथ इसे देखने आ रहा था, जिसकेचलते फिल्म ने अभूतपूर्व कामयाबी हासिल की. कामयाबी के साथ सूरज बड़जात्या ने व्यापक असर डाला. जिस इंडस्ट्री में मारधाड़ और अंग प्रदर्शन के बिना किसी फिल्म की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वहां इस फिल्म ने पारिवारिक मूल्यों को लेकर फिल्म बनाने का नया ट्रेंड विकसित किया. अगले पंद्रह साल तक की फिल्मों पर बड़जात्या की इस छाप का असर दिखाई दिया. सूरज बड़जात्या की अगली फिल्म हम साथ-साथ हैं थी. यह बॉक्स आफिस पर हिट, किंतु रचना के स्तर पर अति सामान्य साबित हुई. बड़जात्या ने फिल्म में तीन जोड़े रखे, लेकिन लव स्टोरी नहीं बनाई, विशुद्ध पारिवारिक फिल्म बनाई, वह भी रामायण पर, जिसकी कहानी बच्चे-बच्चे को पता थी. यानी फिल्म में दर्शकों के लिए कुछ भी नया नहीं था. हम आपके हैं कौन भी नदिया के पार का रिमेक थी, लेकिन उसकी पटकथा में नयापन था, पर हम साथ-साथ हैं में कोई सरप्राइज़िंग इलिमेंट नहीं था. यह फील गुड का ओवर डोज़ थी, जिसे दर्शक पचा नहीं पाए. पटकथा और संगीत दोनों ही दर्शकों को बांधने में पूरी तरह नाकाम रहे, जो सूरज बड़जात्या की फिल्मों की सबसे बड़ी ख़ूबी थी. सूरज का प्रेम शरारती से शर्मीला बन गया. अदाओं से दर्शकों को दीवाना बनाने वाली नायिका शांत और ख़ामोश हो गई. फिल्म में आदर्श और मूल्यों का बखान करने के चक्कर में इतने खो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि फिल्म से वह लव स्टोरी ग़ायब है, जिसका ताना-बाना वह पारिवारिक माहौल के बीच बुनते हैं.

सूरज यहीं से अपने रास्ते से भटक गए. इस फिल्म के बाद सूरज बड़जात्या को शायद लगा कि वह आज के दर्शकों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं, लिहाज़ा उन्होंने बिल्कुल नए तरीक़े से नए दौर के कलाकारों रितिक रोशन, अभिषेक बच्चन और करीना कपूर के साथ फिल्म बनाई-मैं प्रेम की दीवानी हूं, लेकिन यह फिल्म बड़जात्या की पहली फ्लॉप साबित हुई. फिल्म को देखने के बाद समझ में आया कि सूरज मार्ग से भटक गए हैं. हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ वक़्त लिया और फिल्म विवाह लेकर आए, जो सुपर हिट रही. यह फिल्म हम आपके हैं कौन और हम साथ-साथ हैं के बीच की थी. विवाह अरेंज मैरिज से पहले की छोटी सी लव स्टोरी थी, जिसमें दायरे में रहते हुए प्यार की ख़ूबसूरती को दिखाया गया. सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी यह आख़िरी फिल्म थी. इसके बाद उन्होंने यशराज बैनर की तर्ज पर राजश्री के अंतर्गत नए निर्देशकों को मौक़ा दिया, लेकिन ये फिल्में कमाल नहीं दिखा सकीं. उन्होंने एक विवाह ऐसा भी फिल्म लिखी, जो राजश्री की पुरानी फिल्म तपस्या का रिमेक थी, लेकिन यह फिल्म कुछ हिस्सों में ही चल पाई. इसके बाद उनकी देखरेख में राजश्री की कुछ और फिल्में आईं, लेकिन ये कब आईं और कब चली गईं, किसी को पता भी नहीं चला. दरअसल,

जो बड़जात्या इंडस्ट्री में साफ-सुथरी लव स्टोरी का दौर लेकर आए थे, वह बड़जात्या बीस साल बाद विशुद्ध पारिवारिक फिल्मकार बन चुके हैं. परिवार के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया, पर प्रेम के प्रति घटता गया. नए दौर से तालमेल बैठाने के लिए उन्होंने कभी हीरो-हीरोइन बदले, किरदार बदला, कभी संगीत बदला तो कभी पोशाक, पर कहानी, स्क्रिप्ट और संगीत पर ध्यान कम कर दिया, जिसे उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी यूएसपी माना जाता था.

सूरज बड़जात्या की देखरेख में बनने वाली राजश्री की आज की फिल्मों को देखने से उनकी उलझन भी नज़र आती है. एक तरफ़ वह आज के दर्शकों के साथ तालमेल बैठाने के लिए युवाओं को ध्यान में रखकर फिल्में बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ़ आदर्श किरदारों को नहीं छोड़ना चाहते, जो उनकी फिल्मों को बनावटी बनाते हैं. उनकी फिल्मों की परंपरावादी हीरोइन जब शादी से पहले शारीरिक संबंधों की बात हीरो से करती है तो सीन बेहद बचकाना और बनावटी लगता है. अगर इन मुद्दों पर बात करनी है तो किरदार बदलने चाहिए, कहानी बदलनी चाहिए. दरअसल, बड़जात्या को समझना होगा कि इन बीस वर्षों में भारतीय सिनेमा के दर्शक मैच्योर हो गए हैं. टीवी और इंटरनेट ने उनकी मनोरंजक सोच को विकसित किया है. इसलिए आज के दौर में एक्सपेरीमेंटल फिल्में ज़्यादा पसंद की जा रही हैं. ऐसा नहीं है कि आज के दौर में सूरज बड़जात्या छाप फिल्में नहीं चलेंगी, बल्कि ऐसी फिल्मों की सख्त ज़रूरत है और भारतीय फिल्मोद्योग की पहचान ऐसी ही फिल्मों से होगी, पर उन्हें ऐसी फिल्मों को ज़्यादा रीयल बनाना होगा, जैसा कि राजू हीरानी कर रहे हैं. फील गुड के ओवरडोज़ से बचना होगा. फिल्मों में ऐसे पात्रों को शामिल करना होगा, जो साजिश रचकर कहानी में मोड़ लाएं. सूरज को अपनी आगे की फिल्मों के लिए हम आपके हैं कौन की ओर नहीं, बल्कि मैंने प्यार किया की ओर देखना चाहिए.

feedback@chauthiduniya.com

फिल्म प्रीव्यू

चिल्लर पार्टी

सलमान ख़ान की ताजा फिल्म रेडी ने बॉक्स आफिस पर धमाल मचा दिया. बतौर को-प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म आ रही है चिल्लर पार्टी. इस फिल्म में उन्होंने ट्रेलर्स की लाइनें ख़ुद ही लिखी हैं. हुआ यह कि जब उन्होंने उसका थिएट्रिकल ट्रेलर देखा तो उन्हें कुछ कमी लगी. फिर क्या था, वहीं के वहीं उन्होंने उसमें संवाद डाल दिए. ख़ुद ही लिखे और फटाफट अपनी आवाज़ में डब भी कर दिए. कहने की बात यह है कि सलमान शायद जानते हैं कि एक्टिंग, पेंटिंग और गाने के बाद अब उनकी स्क्रिप्ट को सुनने लोग दौड़े चले आएंगे. ज़ाहिर है, सलमान का सेंस ऑफ ह्यूमर उनकी स्क्रिप्ट में भी दिखाई देगा. सलमान की यह फिल्म मासूम, लेकिन हुल्लड़बाज़ बच्चों की कहानी है, जो चंदन नगर के रहने वाले हैं. चिल्लर पार्टी के सदस्यों के नाम हैं एनसाइक्लोपीडिया, जांघ्या, अकरम, सेकंडहैंड, पनौती, साइलेंसर, अफलातून और शाओलिन. इनकी ज़िंदगी में फटका और भीडू नामक दो अजनबी आते हैं और चिल्लर पार्टी का हर सदस्य उनका मुक़ाबला करता है. सलमान की कंपनी सलमान ख़ान बींग ह्यूमन प्रोडक्शंस और यूटीवी ने इसका निर्माण किया है. नितेश तिवारी और विकास बहल ने इसका निर्देशन किया है. फिल्म बताती है कि इन बच्चों के इर्द-गिर्द किस तरह की घटनाएं होती हैं. सलमान से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू शायद ही इस समय किसी सितारे की हो. सलमान इसका जमकर फ़ायदा उठाते नज़र आ रहे हैं. अपनी फिल्मों को चलाने, जागरूकता अभियान और अपने किसी भी प्रयास के लिए सलमान अपने नाम का जमकर इस्तेमाल करते हैं. यह फिल्म आगामी आठ जुलाई को रिलीज होगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

मल्लिका को बधाइयां

मल्लिका शेरावत एक तरफ़ बिन बुलाए बाराती के आइटम सांग शालू के ठुमके में मुन्नी और शीला का मिक्स तड़का लगाकर लोगों को लुभा रही हैं तो दूसरी तरफ़ डबल धमाल में डांस नंबर जलेबी बाई के ज़रिए नया जलवा दिखा रही हैं. इससे पहले वह कॉन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली बार रेड कार्पेट पर क़दमताल करके सुपर सेलिब्रिटी की तरह सुर्ख़ियां बटोर चुकी हैं. कॉन फेस्टिवल के दौरान मैरियट होटल में आयोजित एक हाई प्रोफाइल पार्टी में मौजूद हस्तियों ने मल्लिका को घेर लिया और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की चुनावी हलचल पर बनी फिल्म पॉलिटिक्स ऑफ लव के लिए बधाइयों का ढेर लगा दिया. शीघ्र ही रिलीज होने वाली इस हॉलीवुड फिल्म में मल्लिका ने लीड रोल प्ले किया है. ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में मौजूदगी ओबामा के साथ टी पार्टी और व्हाइट हाउस में डिनर जैसे उनके सपने पहले ही पूरे हो चुके हैं. हरियाणा के रोहतक से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट तक का कामयाब सफर और इंटरनेशनल स्टारडम मल्लिका के ऊंचे ख्वाबों, दूरगामी सोच, मज़बूत रणनीति और बुलंद इरादों का नतीजा है. सब जानते हैं कि मल्लिका ने एयरहोस्टेस की नौकरी छोड़कर म्यूज़िक वीडियो के रास्ते ग्लैमर वर्ल्ड का रुख़ किया. वाशु भगनानी की फिल्म जीना सिर्फ़ मेरे लिए में करीना की सहेली का मामूली रोल करके अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली मल्लिका ने कामयाबी और शोहरत पाने के लिए अपने फिगर को हथियार बनाया और एक्सपोज़र का शॉर्टकट रास्ता अपनाया. ख्वाहिश और मर्डर के बोल्ड किरदारों ने उन्हें हॉट हीरोइन बना दिया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

शमिता की नई पारी

शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत एक्टिंग से की थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली. अंतत: उन्होंने एक्टिंग को टाटा बाय-बाय कह दिया है. ख़बर है कि शमिता ने लंदन में बहन बहनोई के साथ बसने का इरादा कर लिया है. पिछले दिनों वह दोनों के साथ लंदन चली गईं. लंदन में वह अपना इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स पूरा करेंगी और फिर वापस आएंगी. उन्होंने बताया कि वह लंदन के सेंट्रल संत मार्टिन कॉलेज ऑफ आर्ट और डिज़ाइन में दाख़िला लेंगी और वहां से इंटीरियर का स्पेशल कोर्स करेंगी. शमिता ने फिल्म मोहब्बतें से शुरुआत की थी और यह फिल्म यशराज प्रोडक्शन की फिल्म थी. इसके बावजूद उनका करियर आगे नहीं बढ़ पाया. उन्होंने कहा कि कोर्स पूरा करने के बाद वह अपनी बहन की प्रोडक्शन कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर केरूप में काम करेंगी. शमिता चाहती हैं कि वापस मुंबई आकर वह अपना कोई नया कारोबार शुरू करें. शमिता, ऑल द बेस्ट, नई पारी की शुरुआत के लिए. हमारी कामना है कि आप कामयाब हों.

आई एम कलाम मेरे दिल के क़रीब है : पांडा

आगामी पांच अगस्त को रिलीज़ होने वाली फिल्म आई एम कलाम के निर्देशक नीला माधब पांडा कहते हैं कि यह फिल्म मेरे दिल के बहुत क़रीब है. यह अब तक कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है. इस फिल्म का निर्माण स्माइल फाउंडेशन द्वारा किया गया है. पांडा दिल्ली निवासी हैं. उन्हें इस फिल्म के लिए बतौर सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक वर्ष 2011 के अरविंदन पुरस्कार से नवाज़ा गया है. उन्होंने दिल्ली में रहते हुए इतनी सशक्त फिल्म का निर्माण किया है. इस फिल्म की शूटिंग दिल्ली और राजस्थान में हुई है. इसमें मुख्य किरदार हर्ष मायर ने निभाया है, जिसे इस फिल्म के लिए बतौर सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार 58वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार (2011) मिला है. नीला पांडा ने कहा कि हमारे देश में दर्शक ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं, जो असल ज़िंदगी से मेल खाती हो और सामाजिक सरोकार रखती हो, जिसमें असली भारत का चेहरा दिखता हो. वह कहते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसी फ़िल्में बनती नहीं हैं. हमारे देश में भी ऐसी फ़िल्में बनती हैं, परंतु दर्शकों तक पहुंचने का मार्ग आसानी से नहीं मिलता. आई एम कलाम एक ऐसी ही फिल्म है, जिसकी कहानी ढाबों से लेकर सड़क के किनारे बनी दुकानों में काम करने वाले उस छोटू की है, जिसे हर कोई इसी नाम से बुलाता है और उसे भी यही लगता है कि यह उसका असली नाम है. आई एम कलाम एक स्वतंत्र रूप से कलात्मक सोच द्वारा तैयार की गई फिल्म है, जिसमें असल भारत को एक मनोरंजक तरीक़े से दर्शकों के सामने पेश किया गया है. आई एम कलाम दर्शकों के लिए कुछ नया लेकर आएगी और उनके मन में अपनी एक पहचान क़ायम करेगी.

चौथी दुनिया

दिल्ली, 4 जुलाई-10 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

संपूर्णता की ओर विदर्भ का स्वप्न

एक साल पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में सिंचाई के साथ ऊर्जा पैदा करने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मंज़ूरी प्रदान करने केबाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज़ ने बताया था कि जिन 14 परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा, उनमें पश्चिम बंगाल का तीस्ता बैराज, पंजाब रावी नदी पर शाहपुर खांदी, जम्मू-कश्मीर में चनाब पर बरसार, रावी-व्यास लिंक परियोजना, चनाब पर ही जम्मू-कश्मीर में उज्झ बहुउद्देश्यीय परियोजना, हिमाचल प्रदेश में चनाब पर जिस्पा परियोजना, यमुना पर लखवार व्यासी, किसाऊ, यमुना की सहायक नदी रेणुका परियोजना और महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना को शामिल किया गया था.

प्रवीण महाजन

विदर्भ ही नहीं समूचे महाराष्ट्र की महत्वाकांक्षी परियोजना बन चुके गोसीखुर्द प्रकल्प के लिए अब यह ख़ुशी की बात है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले तीन साल में यह परियोजना पूरी हो जाएगी. ढाई लाख हेक्टेयर ज़मीन में सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी. नागपुर और भंडारा ज़िलों के 85 गांवों का पुनर्वसन पूरा हो जाएगा. अगर इस वृहद परियोजना के डुबान क्षेत्र में आने वाले गांवों के प्रतिनिधियों ने सच्चाई से विस्थापितों का पक्ष रखा और प्रशासन ने सही दिशा में प्रयास किए तो इस परियोजना से न सिर्फ़ सिंचाई की व्यवस्था की जा सकेगी, बल्कि इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा. रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे. विदर्भ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. मत्स्य व्यवसाय से 500 करोड़ रुपये की आय भी हो सकेगी. इसके साथ ही जिन 250000 कृषक परिवारों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, वे साल में दो या तीन फ़सल ले सकेंगे, जिससे उनकी आय में कई गुना वृद्धि हो जाएगी.

भंडारा ज़िले के पवनी तहसील के वैनगंगा नदी पर गोसीखुर्द गांव में परियोजना का भूमि पूजन 22 अप्रैल 1985 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था, उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले 20 साल तक इस महत्वाकांक्षी परियोजना को सरकार की उपेक्षा झेलनी पड़ेगी. वर्ष 2007 के बाद परिदृश्य बदलने लगे. इसे नई दिल्ली स्थित केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाकार समिति की मान्यता मिली. 27 फरवरी 2008 को 7777.824 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और 26 फरवरी 2009 को इसे राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में मान्यता मिल गई. दरअसल, एक साल पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने देश में सिंचाई के साथ ऊर्जा पैदा करने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में मंज़ूरी प्रदान करने के बाद केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सैफ़ुद्दीन सोज़ ने बताया था कि जिन 14 परियोजनाओं को इसका लाभ मिलेगा, उनमें पश्चिम बंगाल का तीस्ता बैराज, पंजाब रावी नदी पर शाहपुर खांदी, जम्मू-कश्मीर में चनाब पर बरसार, रावी-व्यास लिंक परियोजना, चनाब पर ही जम्मू-कश्मीर में उज्झ बहुउद्देश्यीय परियोजना, हिमाचल प्रदेश में चनाब पर जिस्पा परियोजना, यमुना पर लखवार व्यासी, किसाऊ, यमुना की सहायक नदी रेणुका परियोजना और महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना को शामिल किया गया था. इन परियोजनाओं में 90 फ़ीसदी ख़र्च अब केंद्र सरकार और 10 फ़ीसदी ख़र्च राज्य सरकार को करना था. मामला साफ़ है, अब ख़र्च का बोझ राज्य सरकार के मत्थे नहीं आने वाला है. इसलिए काम में तेज़ी आई. अब अधिकारी भी तेज़ी से काम पूरा करने में जुट गए.

राज्य की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा इसका भूमिपूजन करने के बाद आशा थी कि यह परियजना जल्द पूरी हो जाएगी, लेकिन हुआ इसके उलट. बांध का काम शुरू होने में पूरे 13 साल लग गए. इन तेरह वर्षों में राज्य सरकार को निधि का प्रावधान करने में अड़चनें आईं. सबसे बड़ी दिक्क़त आई वन विभाग की अनुमति लेने में, जिन नहरों का निर्माण होना था, उनका काफ़ी हिस्सा वन क्षेत्रों से होकर जाता था. इस कारण वन विभाग की स्वीकृति आवश्यक थी. 1988 में वन विभाग की स्वीकृति का काम पूरा हुआ.

यह बात अलग है कि पूरी स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी दो साल पहले गांवों के पास झुड़पी जंगल के नाम पर एक बार फिर वन विभाग ने गोसीखुर्द परियोजना के काम में रोड़ा अटका दिया. 1997 तक राज्य सरकार इस वृहद परियोजना को कुछ लाख रुपये की निधि रोटी के टुकड़ों की तरह फेंकती रही, जो प्रशासनिक ख़र्चों में व्यय होते गए. 1997 में विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडल (विदर्भ सिंचाई विकास महामंडल, वीआईडीसी) अस्तित्व में आया. इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि छोटे-छोटे कामों के लिए या फिर हर फाइल की स्वीकृति के लिए मुंबई मंत्रालय की दौड़ न लगानी पड़े. इसका फ़ायदा भी गोसीखुर्द के साथ विदर्भ की अन्य परियोजनाओं को मिला. 1997 में वीआईडीसी ने बाक़ायदा बॉन्ड जारी कर बाज़ार से धन इकट्ठा किया. सोच यह थी कि गोसीखुर्द के लिए यह रुपये जमा किए जाएंगे और फिर इसे निवेशकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा. सन 2000 तक तो सबकुछ ठीकठाक चला. जब तक गोसीखुर्द को वीआईडीसी के बॉन्ड के रुपये मिलते गए तब तक सरकार की तरफ़ या यूं कहें मुंबई की ओर ताकने की नौबत नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब निवेशकों की रुचि इसमें कम होने लगी या यह कहना ज़्यादा उचित होगा कि बांड में निवेश ख़त्म हो गया तो एक बार फिर वही पुरानी स्थिति आ गई यानी एक-एक पाई के लिए मुंबई की ख़ुशामद. जो स्वायत्तता वीआईडीसी की आड़ में इस परियोजना को मिली थी, वह अघोषित रूप से समाप्त हो गई. अब सब कुछ सरकार पर निर्भर हो गया. हर काम के लिए बजट में प्रावधान ज़रूरी हो गया. फिर वही क्रम चलने लगा यानी कुछ लाख रुपये आने लगे, जो प्रशासनिक ख़र्च में व्यय हो जाते थे. नतीजा यह हुआ कि 2001 से 2003 तक इस परियोजना का काम पूरी तरह ठप हो गया. सन 2003 से कुछ निधि का आवंटन ज़रूर शुरू हुआ, लेकिन सन 2005 में अजीत पवार के जल संसाधन मंत्री बनने के बाद गोसीखुर्द परियोजना को अच्छी ख़ासी निधि मिली. इस कारण इस परियोजना का काम तेज़ी से आगे बढ़ा. यह बात अलग है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अजीत पवार द्वारा विदर्भ पर किए गए इस उपकार को जनता के बीच प्रचारित नहीं कर पाए, लेकिन दबी ज़ुबान से ही सही, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि अजीत पवार का गोसीखुर्द परियोजना के लिए रुझान मील का पत्थर साबित हुआ. सन 2005 में निधि प्राप्त होने का ही परिणाम था कि 2007 में भिवापुर के पास घाट उमरी में पहला विस्थापित गांव बसाया जा सका. इसके बाद सन 2008 में बांध की लाइन पर बसे मेंढा गांव को विस्थापित किया गया. इन तीन वर्षों में ही बांध में पानी का स्तर 229 मीटर तक पहुंच चुका था. 2008 में बांध का काम पूरा हो चुका था और उसके एक साल पहले ही यह निर्णय लिया जा चुका था कि अब बांध में पानी भरना चाहिए. वर्तमान में इस बांध में 237.20 मीटर तक पानी पहुंच चुका है, जबकि पुनर्वसन प्राधिकरण की 10 अगस्त 2010 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि प्रथम चरण में गोसीखुर्द बांध का तलांक 239 मीटर किया जा सकता है. चूंकि अभी विस्थापन का काम पूरा नहीं हो पाया है इसलिए विभागीय आयुक्त ने इस पर स्टे दे दिया है. इसके लिए नागपुर ज़िले के 11 और भंडारा ज़िले के 3 गांवों में से 9 गांवों को पूरी तरह विस्थापित किया जा चुका है. 5 गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया जारी है. दूसरे चरण में 242 मीटर सन 2011-12 तक (20 टीएमसी) पानी, तीसरे चरण में 245.50 मीटर (40.47 टीएमसी) पानी सन 2012-13 तक पहुंचाने का लक्ष्य है. इस प्रकल्प से कुल 2 लाख 50 हज़ार 800 हेक्टेयर ज़मीन की सिंचाई हो सकेगी. इसमें 1 लाख 64 हज़ार 908 हेक्टेयर नहर द्वारा और 85 हज़ार 892 हेक्टेयर लिफ्ट इरिगेशन द्वारा सिंचाई की जाएगी. भंडारा ज़िले की 89 हज़ार 856 हेक्टेयर ज़मीन, नागपुर ज़िले की 19481 हेक्टेयर और चंद्रपुर ज़िले की 1 लाख 41 हज़ार 463 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो जाएगी. इस बांध में 1146 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का संग्रह होगा. इसके साथ ही आसोलामेंढा तालाब में 120.568 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित किया जाएगा. पानी का इस्तेमाल 1634 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रस्तावित है.

राष्ट्रीय प्रकल्प के अनुरूप भव्यता देंगे: झपके

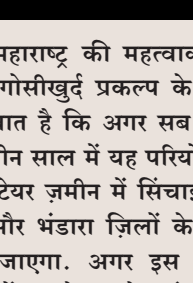

विदर्भ पाटबंधारे (सिंचाई) विकास महामंडल (वीआईडीसी) के कार्यकारी निदेशक प्र.च. झपके गोसीखुर्द प्रकल्प को राष्ट्रीय प्रकल्प के अनुरूप ही भव्यता प्रदान करने के लिए कटिबद्ध हैं. उनका कहना है कि राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित होने के बाद इसका काम तेज़ी से चल रहा है. अब पुनर्वसन के मामले में एक पेंच अटक गया है. राज्य की पुनर्वसन नीति के तहत जो 18 बिंदु निर्धारित किए गए थे, उन्हें हमने पूरा कर दिया है. मगर अब राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित होने के बाद राष्ट्रीय पुनर्वसन नीति के 26 बिंदुओं को लागू करने के लिए दबाव डाला जा रहा है. उधर बांध में पानी का जल स्तर बढ़ने का भी दबाव है. प्रकल्प काफ़ी पुराना है और राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित हुए अभी दो साल ही हुए हैं. ऐसे में 26 बिंदुओं को लागू करने के लिए अतिरिक्त 900 करोड़ रुपये की ज़रूरत होगी, जिसे केंद्र की मदद से पूरा कर भी लिया जाएगा, लेकिन राज्य की अन्य परियोजना के विस्थापित भी इन सुविधाओं की मांग करने लगे हैं. इससे प्रशासन-शासन के सामने असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है. अगर राज्य की सभी परियोजनाओं को पुनर्वास की 26 बिंदुओं की सुविधाएं दी जाएं तो इसमें लगभग 20 हज़ार करोड़ का ख़र्च आएगा. इतना ख़र्च करना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं होगा. वैसे अभी इसकी प्रक्रिया शुरू है और इस प्रस्ताव को पहले राज्य कैबिनेट को मंज़ूर करना होगा और उसके बाद केंद्र को इस अतिरिक्त भार 900 करोड़ रुपए की मंज़ूरी देनी चाहिए, तभी पुनर्वसन के 26 बिंदुओं के काम पूरे किए जा सकते हैं. वैसे राज्य सरकार के 18 बिंदुओं के काम पूरे हो चुके हैं और लोगों को अब पुनर्वास गांवों में चला जाना चाहिए. फ़िलहाल केंद्र से 4013 करोड़ और राज्य सरकार से 446 करोड़ रुपए प्राप्त होने हैं. वीआईडीसी के उद्देश्यों की असफलता के बारे में पूछने पर झपके कहते हैं कि यह महामंडल अपने उद्देश्यों पर पूरी तरह खरा उतरा है.

प्रशासनिक स्तर पर पूरा प्रयास: ठाकरे

गोसीखुर्द परियोजना के अधीक्षक अभियंता आर. एन. ठाकरे का मानना है कि अब तक अधिकारियों ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए अच्छा काम किया है और आगे भी हम प्रशासनिक स्तर पर इसे समय पर पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं. अब इस परियोजना की लागत 13,628 करोड़ रुपये हो जाएगी. यह प्रकल्प विदर्भ की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है. हम इस आशा पर खरा उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं. फंड भी समय पर आ रहा है और अब किसी का भुगतान भी पेंडिंग नहीं है. 2014-15 तक परियोजना को पूरी तरह कंप्लीट करने का लक्ष्य है.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

छोटे किसानों का आरोप है कि बड़ी मात्रा में बीजों की कालाबाज़ारी की जा रही है. इसके पहले अनुदान पर और प्रायोगिक तौर पर बीजों का वितरण कृषि विभाग द्वारा किया जाता था.

ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 70,000 रुपये, पालिका के लाभार्थी को 50,000 रुपये, महानगर पालिका के लाभार्थियों को दो लाख रुपये अपना घर बनाने के लिए दिए जाने वाले थे.

चौथी दुनिया

एक तहसील : 6 दुकानें

राज्य सरकार का नया फ़रमान

शासन ने तहसील स्तर पर सिर्फ़ 6 बीज केंद्रों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है. पहले हर गांव के 30 से 35 लोगों को प्रायोगिक तौर पर कृषि विभाग के सहायक के द्वारा परमिट दिया जाता था. इस वजह से किसानों को समय पर बीज नहीं मिल पा रहे हैं.

सोनू सावजी

मानसून के आते ही राज्य के किसान ख़रीफ़ की फ़सल बोने की तैयारी में जुट गए हैं. सरकार ने उनकी सुविधा के लिए 50 प्रतिशत अनुदान पर विविध प्रकार के बीज प्रायोगिक तौर पर हर तहसील में मात्र 6 कृषि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है. बीजों के लिए कृषि केंद्रों पर जहां लंबी-लंबी कतारें लग रही हैं, वहीं इसका फ़ायदा उठा कर बीजों की कालाबाज़ारी भी शुरू हो गई है. इससे कई-कई घंटे कतारों में खड़े रहने के बाद भी बीज न मिलने से किसानों को निराश होकर लौटना पड़ता है या मजबूरन खुले बाज़ार से अधिक क़ीमत पर बीज ख़रीदना पड़ रहा है. चूंकि सबसे अधिक सोयाबीन के बीजों की मांग है इसलिए सर्वाधिक कालाबाज़ारी भी इसी के बीजों की हो रही है. साथ ही सोयाबीन के बीज का निम्न स्तर का होना चिंता का विषय बना हुआ है.

सबसे अधिक परेशानी इस बात की है कि शासन ने तहसील स्तर पर सिर्फ़ 6 बीज केंद्रों को इसके लिए अधिकृत कर दिया है. पहले हर गांव के 30 से 35 लोगों को प्रायोगिक तौर पर कृषि विभाग के सहायक द्वारा परमिट दिया जाता था. इस आधार पर उन लोगों को बीज 50 फ़ीसदी क़ीमत पर मिल जाते थे. अब शासन ने सभी लोगों के लिए तहसील में सिर्फ़ 6 केंद्र निर्धारित कर दिए हैं. इसके पीछे का कारण अब तक किसी की समझ में नहीं आया है. पहले हर गांव में कृषि सेवा केंद्र भी हुआ करते थे, जहां से किसान बीज ख़रीद लिया करते थे. अब पूरा भार इन 6 केंद्रों पर ही है. इसके पीछे जानकार किसी बड़े घोटाले या मिलीभगत की आशंका व्यक्त कर रहे हैं.

ग़ौरतलब है कि विख्यात बीज कंपनियों के बीज बाज़ार में ज़्यादा क़ीमतों में बिक रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में ज़िला व तहसील के कृषि केंद्रों को नियुक्त किया है, मगर सरकार अधिकृत कृषि केंद्र अपने फ़ायदे के लिए अनुदान वाले बीजों की कालाबाज़ारी करने में जुट गए हैं. इससे सामान्य किसानों को बीज नहीं मिल पा रहे हैं. इसके चलते 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज मिलने से ख़ुश किसानों की ख़ुशी क्षणिक ही साबित हुई और चिंता का कारण बन गई है.

आकोट तहसील के लिए शासन के कृषि विभाग द्वारा तुअर, सोयाबीन और मूंग के 1841 क्विंटल 40 किलो बीज किसानों को वितरित करने के लिए उपलब्ध कराए गए थे. इसके लिए स्थानीय बीज वितरण के लिए ख़रीदी-बिक्री संघ, गोपालकृष्ण कृषि सेवा केंद्र, झुनझुनवाला कृषि सेवा केंद्र, वृषाली कृषि सेवा केंद्र को शासन ने अधिकृत किया था. इन कृषि सेवा केंद्रों को आकोट सहित चोहोट्टा व मुडगांव में बीज वितरण करना था. अब तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आकोट व उसके आसपास के क्षेत्र में 1000 क्विंटल, चोहोट्टा में 190 क्विंटल और मुडगांव में क़रीब 160 क्विंटल बीजों का वितरण किया जा चुका है. इसी तरह उर्वरित 500 क्विंटल बीजों का वितरण ख़रीदी-बिक्री केंद्र पर शुरू है. शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर सोयाबीन बीज के 30 किलो बैग के लिए किसानों को 588 रुपये भुगतान करना पड़ रहा है. इसी तरह तुअर के दो किलो बैग के लिए 77 रुपये, मूंग के 5 किलो बैग हेतु 187.50 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. किसानों ने सर्वाधिक बीज सोयाबीन के लिए हैं. इस कारण से तुअर के उपलब्ध 40 क्विंटल बीज की अपेक्षा मात्र 15 क्विंटल बीज ही कृषकों ने उठाए हैं. इसी तरह 15 क्विंटल में से मात्र 5 क्विंटल मूंग के बीज अब तक बिके हैं. इससे लगता है कि किसानों को बीज आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं, पर बीज की मांग अधिक होने से ख़रीदी-बिक्री केंद्र पर किसानों की लंबी-लंबी कतारें हर रोज़ लगी रहती हैं. इन कतारों में महिला कृषकों की भी बड़ी संख्या रहती है.

स्थानीय कृषि विभाग के अंतर्गत प्रायोगिक तौर पर अनुदानित बीजों का वितरण प्रत्येक गांव में प्रत्येक किसान को एक बैग के हिसाब से किया जाना था. मगर जिन किसानों ने अपनी मर्ज़ी से बीज लेने से इंकार कर दिया उससे बचे बीजों का वितरण किया जा रहा है, ऐसी चर्चा ग्रामीण क्षेत्र में है. बताया जा रहा है कि शासन अधिकृत कृषि सेवा केंद्रों द्वारा किसानों से खेतों का सातबारा और अ-8 मांगा जाता है तभी अनुदानित बीज दिया जाता है. इनके बिना बीज नहीं मिलता है. बड़े किसानों ने उक्त काग़ज़ात को एकत्र कर बड़ी मात्रा में बीज इकट्ठा कर लिया है. इससे कतार में खड़े किसानों को थोड़े ही बीज मिल पाते हैं. छोटे किसानों का आरोप है कि बड़ी मात्रा में बीजों की कालाबाज़ारी की जा रही है.

इसके पहले अनुदान पर और प्रायोगिक तौर पर बीजों का वितरण कृषि विभाग द्वारा किया जाता था. इसके तहत प्रत्येक गांव के इच्छुक किसानों को कृषि सहायक की मार्फ़त परमिट दिया जाता था. तब बडाकी देशमुख, सातारा, मंचनपुर, आसेगांव में भी बीज वितरण किया जाता था. उसके बाद से स्थानीय कृषि अधिकारियों द्वारा सभी गांवों के केंद्र बंद करने के बाद से अब उक्त गांवों के किसानों को आकोट जाकर बीज लाना पड़ता है. इसके कारण बीज वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ लग जाती है और सभी में होड़ शुरू हो जाती है कि उसका नंबर कितनी जल्दी आ जाए. अपना नंबर पहले लगाने के चक्कर में किसानों के बीच वितरण केंद्र पर रोज़ झगड़े होते हैं.

कई किसानों का कहना है कि पहले की तरह परमिट के आधार पर हर गांव में बीज वितरण की पद्धति ही ठीक थी. किसानों का कहना है कि सभी को सामान्य रूप से बीज वितरण की व्यवस्था शासन को करनी चाहिए, ताकि कृषकों को आकोट आने जाने का समय व पैसे दोनों की बचत हो.

विख्यात बीज कंपनियों के बीज बाज़ार में ज़्यादा क़ीमतों में बिक रहे हैं. इस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अपने प्रतिनिधि के रूप में ज़िला व तहसील के कृषि केंद्रों को नियुक्त किया है. मगर सरकार अधिकृत कृषि केंद्र अपने फ़ायदे के लिए अनुदान वाले बीजों की कालाबाज़ारी करने में जुट गए हैं. इससे सामान्य किसानों को बीज नहीं मिल पा रहा है. इसके चलते किसानों की ख़ुशी क्षणिक ही साबित हुई.

feedback@chauthiduniya.com

जे डे हत्याकांड

बेशर्म सरकार निर्लज्ज पुलिस

राजेश नामदेव

वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या को एक माह पूरा हो चुका है, लेकिन उनके हत्यारे पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं. मुंबई पुलिस, नागरी सुरक्षा से जुड़ी तमाम एजेंसियां ख़ासकर सरकार में बैठे ज़िम्मेदार अफ़सरों और नेताओं ने निर्लज्जता की तमाम हदें पार कर दी हैं. यह पहला मामला नहीं है जब महाराष्ट्र की पुलिस ख़ासकर मुंबई पुलिस और इस पर भी ख़ास तौर पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड (एटीएस) के कारनामों के मनगढ़ंत क़िस्से, एंकाउंटर की गढ़ी गई कहानियां मामलों के न्यायालय पहुंचने के बाद सामने आती हैं. डे के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है. हो सकता है इस ख़बर के छपने तक अपराधी (पुलिस के अनुसार) गिरफ्त में आ जाएं, लेकिन अब समय आ गया है कि पुलिस को अपनी शर्मनाक छवि को बचाने के लिए ठोस क़दम उठाने ही होंगे. जहां डॉ. भूषण कुमार उपाध्याय जैसे ईमानदार अफ़सर को आसवासन में भेज दिया जाता है और तेलगी कांड में फंसे शर्मा जैसे अधिकारी को तब तक नहीं हटाया जाता है, जब तक क़ानून का फंदा गले तक नहीं पहुंच जाता.

पत्रकारों की सुरक्षा प्रदान करने की मांग राज्य के पत्रकार संगठन पहले से कर रहे हैं. मगर मिड डे अख़बार के वरिष्ठ पत्रकार ज्योतिर्मय (जॉय) डे की सरेआम हत्या के बाद यह मांग और ज़ोर-शोर से उठाई जा रही है, लेकिन पत्रकार सुरक्षा की मांग किससे कर रहे हैं—यह एक विचारणीय सवाल है. वजह है डे हत्याकांड से सामने आने वाले तथ्य, जिन पर ग़ौर किए जाने की ज़रूरत है. इस हत्याकांड के संबंध में जो तथ्य उभर कर सामने आ रहे हैं, उनसे सरकार और पुलिस दोनों ही संदेह के घेरे में हैं. हत्याकांड से संबंधित कहानी बार-बार बदल रही है. वहीं दूसरी ओर इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को सरकार द्वारा ठुकरा जाने के बाद मुंबई के पत्रकारों ने पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति बना ली. विरोध ज़ारी रखने के लिए भूख हड़ताल अनशन करने का ऐलान किया है. यहां सबसे अहम सवाल उठता है कि सीबीआई क्या निष्पक्ष तरीक़े से जांच कर पाएगी? यह सवाल इसलिए लाज़िमी है, क्योंकि यदि इस हत्या के सूत्र भी माफ़िया सरगनाओं से जुड़े हुए हैं, तो मामला लंबा खिंच सकता है. इसमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई में सक्रिय माफ़िया गिरोहों के मधुर संबंध सत्ता-पुलिस दोनों से किस तरह हैं. बार-बार आरोप लगने के बाद भी उनका आज तक कोई बाल-बांका नहीं कर सका है.

डे हत्याकांड में चार कहानियां उभर कर सामने आई हैं. जे. डे की हत्या की ख़बर जिस दिन सभी अख़बारों में प्रकाशित हुई, उस दिन आशंकाएं जताई गईं कि स्वर्गीय डे की हत्या में कुछ सत्ताधीशों और पुलिसवालों की भूमिका हो सकती है. चूंकि जे. डे एक नितांत निर्भीक पत्रकार थे और किसी क्राइम स्टोरी पर काम कर रहे थे, जिसके ख़ुलासे के बाद कई नेताओं और पुलिस महकमे के वरिष्ठ लोग संकट में पड़ सकते थे. इसलिए उनके द्वारा किसी माफ़िया के शूटरों को सुपारी देकर यह हत्या कराई गई है. इसके बाद जो दूसरी स्टोरी सामने आई उसमें आशंका ज़ाहिर की गई कि जे. डे की हत्या में तेल माफ़िया की भूमिका हो सकती है. जिस तेल माफ़िया ने अपर कलेक्टर यशवंत सोनवाने की हत्या की थी, वह इस हत्याकांड में शामिल हो सकता है. तीसरी कहानी के रूप में जो तथ्य सामने आए उनमें कहा गया कि जे. डे की हत्या में उम्मेद नामक व्यक्ति पर संदेह जताया गया. उम्मेद वह व्यक्ति है जिस पर मुंबई की पुलिस को माफ़िया सरगना दाऊद के भाई इक़बाल कासकर के वाहन चालक की हत्या करने का संदेह है. वजह है- डे ने कुछ ही दिन पहले उम्मेद की मां की ज़िंदगी के संबंध में अपनी एक स्टोरी में विस्तार से लिखा था. इससे उम्मेद डे से चिढ़ गया था जिसके परिणामस्वरूप इस घटना को अंजाम दिया हो. चौथी कहानी में जे. डे हत्या के सूत्र दुबई से जुड़े होने के तथ्य उभर कर सामने आए. इसमें कहा गया कि जे.डे की हत्या का कनेक्शन दुबई के चंदन तस्कर जाफ़र कासिम से जुड़े हैं. इस संबंध में पुलिस ने संदेह के आधार पर तीन लोगों को पकड़ा भी है. पकड़े गए लोगों में अनवर हटेला, मतीन शेख़ उर्फ़ टकला और नदीम उर्फ़ बॉबी शामिल हैं, पर सामान्य पूछताछ कर उन्हें छोड़ भी दिया गया. इससे पुलिस की जांच सवालों के घेरे में आ जाती है. नदीम उर्फ़ बॉबी पुलिस का मुख़बिर है और नदीम ने ही जे.डे को जाफ़र कासिम के चंदन तस्करी के नेटवर्क की जानकारी दी थी. माफ़िया डॉन छोटा शकील ग्रुप के जाफ़र कासिम द्वारा महाराष्ट्र के कोने-कोने से चुराए गए चंदन की तस्करी करने के प्रमाण नदीम ने जे. डे को दिए थे, जिनके आधार पर डे इस प्रकरण का ख़ुलासा करने वाले थे. मगर मामले नया मोड़ तब आ गया जब कुछ दिनों बाद नदीम ने चंदन तस्करी का मामला प्रकाशित न करने का डे से अनुरोध किया और दस लाख रुपये देने की पेशकश की. यह बात डे को पची नहीं और उन्होंने मामला प्रकाशित करने का अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया. इस पर नदीम ने डे की बात सीधे कासिम से कराई. इसके बावजूद डे अपने निश्चय से डिगे नहीं. तदोपरांत कासिम ने अनवर हटेला और मतीन शेख़ उर्फ़ टकला को डे की हत्या की सुपारी दे दी, नतीजतन यह हत्याकांड हुआ. अब इन कहानियों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच एजेंसियां तय करेंगी. मगर चारों कहानियों में एक तथ्य जो कॉमन है- वह है माफ़िया द्वारा हत्याकांड को अंजाम देना.

पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट हत्यारे

राज्य के गृहमंत्री आर.आर. पाटिल अब तो यहां तक मान रहे हैं कि जे. डे के क़ातिल पुलिस से ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई सुराग़ नहीं छोड़ा है. इसका तो यही मतलब हुआ कि पुलिस के पास अब तक हत्यारों तक पहुंचने का कोई सूत्र नहीं है. यह बात गृहमंत्री ने 17 जून को पत्रकारों से बात करते समय कही है. उनका कहना है कि अपराधिकों की स्मार्टनेस के कारण जांच में थोड़ी मुश्किल हो रही है. इस बयान के आते ही विपक्षी पार्टियों ने गृहमंत्री के इस्तीफ़े की मांग करना शुरू कर दिया है.

अब सीबीआई जांच करने की मांग करने वाले हमारे पत्रकार बंधुओं को यह तथ्य भी ध्यान रखना चाहिए कि पहली कहानी के आधार पर यदि यह मान लिया जाए कि इस हत्या में किसी सत्ताधीश-राजनीतिज्ञ-पुलिस अफ़सर की भूमिका है तो क्या उसे सीबीआई सज़ा दिलवा पाएगी. राजनीति का अपराधीकरण भ्रष्ट राजनेता-भ्रष्ट पुलिस अफ़सरों के कारण ही बढ़ता जा रहा है. यह समूह अपना दामन बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है. दूसरी कहानी के अनुसार यदि यह माना जाए कि डे की हत्या तेल माफ़िया ने कराई है तो हमें अपर कलेक्टर यशवंत सोनवाने की हत्या के नतीजे को ज़ेहन में लाना चाहिए. कुछ तेल मिलावटख़ोरों के ख़िलाफ़ ही कार्रवाई हुई. तेल माफ़िया के सरगनाओं के विरुद्ध कोई एक्शन लिया गया क्या? तीसरी स्टोरी में जिस शूटर उम्मेद का नाम आया है, उस व्यक्ति पर जब पहले ही एक शख़्स पर हमला करने का संदेह है तो पुलिस ने उसे अब तक पकड़ा क्यों नहीं? खुला क्यों छोड़े रखा? चौथी में जिस नदीम उर्फ़ बॉबी का नाम आया है, वह यदि पुलिस का मुख़बिर था तो चंदन तस्कर जाफ़र कासिम के नेटवर्क की सूचना और सबूत पुलिस को क्यों नहीं दिए? डे को क्यों दिए? फिर गिरफ्तार किए गए तीनों अपराधियों को पूछताछ के बाद छोड़ क्यों दिया गया? चौथी कहानी का यह पेंच ही गहरा रहस्यमय है. दूसरी बात की चंदन तस्कर जाफ़र कासिम दुबई में रहता है, जहां से उसे भारत लाना महाराष्ट्र पुलिस व सीबीआई के लिए पेंचीदा मामला है, क्योंकि हर माफ़िया से किसी न किसी बड़े नेता की डोर जुड़ी रहती है जो उसके नेटवर्क को संरक्षित करता है. सो इस हत्याकांड की जांच को पुलिस या सीबीआई कहां तक पहुंचा पाएगी? अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर यानी पत्रकारों की सुरक्षा का मामला. पत्रकार किससे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? पत्रकारिता के संबंध में कहा जाता है कि इसको अपनाना दोधारी तलवार पर चलने के समान होता है. इस तलवार की एक धार हमेशा अपनी ओर ही होती है. इस दोधारी तलवार पर ईमानदार ही चलता है, जिसके चलते जे. डे को शहीद होना पड़ा. इसलिए मेरा सवाल है कि हम किससे सुरक्षा मांग रहे हैं? जो पत्रकारों को अपनी साख बनाने-बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं- उनसे. जो सत्ता भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देती है- उससे. जिस सरकार का एक मंत्री यह कहता हो कि ये पत्रकार पिटने के ही क़ाबिल होते हैं- उस सरकार से. जिनके आदेश पर पत्रकारों पर पुलिस लाठी भांजती है-उनसे. अब ख़ुद ही देख लीजिए कि मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को सुरक्षा देने संबंधी विधेयक का प्रारूप जब 15 जून को मंत्रिमंडल की हुई बैठक में पेश किया तो क्या हश्र हुआ. जे. डे हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व गृहमंत्री आर.आर. पाटिल सरकार की हो रही बदनामी के डर से इस विधेयक को अंतिम रूप देना चाहते हैं, वहीं कई मंत्री इस पर जल्दबाज़ी करने के पक्ष में नहीं हैं. कई तो इसके बनाने के पक्ष में ही नहीं हैं. वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व वन मंत्री पतंगराव क़दम ने तो पत्रकारों को सुरक्षा देने के पहले, पत्रकारों की ओर से किए जाने वाले अन्याय से सुरक्षा दिलाने की मांग तक कर डाली. कुछ मंत्रियों ने पत्रकारों द्वारा धमकाने का मुद्दा उठाया. इसका साफ़ मतलब है कि सरकार में पत्रकारों को सुरक्षा देने को लेकर क़ानून बनाने में आम सहमति नहीं है. इसलिए बैठक में उद्योग मंत्री नारायण राणे ने जो कहा वह ग़ौर करने लायक़ है. बैठक में प्रस्तावित विधेयक का विरोध करते हुए राणे ने कहा कि आज यदि पत्रकारों को संरक्षण देने का क़ानून बनाया तो भविष्य में उद्योग जगत के लोग अलग से संरक्षण देने वाला क़ानून बनाने की मांग करेंगे. राज्य के विविध संगठन ऐसे ही अपने-अपने लिए अलग-अलग सुरक्षा क़ानून बनाने की मांग करेंगे तो क्या प्रत्येक के लिए नए-नए क़ानून बनाते जाएंगे? उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए इसमें कोई दो मत नहीं है, पर इसमें व्यापक विचार-विमर्श की ज़रूरत है. वे ख़ुद एक अख़बार का संपादक होने का दावा भी करते हैं. अब यह विधेयक पुनः विचारणीय हो गया है. हां, इस पर अब राजनीति शुरू हो गई और विपक्षी पार्टियों द्वारा जल्द से जल्द पत्रकारों की सुरक्षा संबंधी विधेयक लाने की मांग की जा रही है, लेकिन जब पत्रकार दोधारी तलवार की राह पर चलते हैं तो पत्रकारों को स्वयं सचेत रहकर का काम करना होगा.

बहरहाल जे. डे हत्याकांड के मामले में पुलिस की जांच अंधेरे में भटक रही है. पुलिस के हाथ अब तक कोई सुराग़ नहीं लगा है, बस जांच जारी है. अब उच्च न्यायालय ने भी जवाब-तलब करना शुरू कर दिया है. हम सब यही चाहते हैं कि इस हत्याकांड की हक़ीक़त सामने आए और हत्या के लिए ज़िम्मेदार लोगों को दंडित किया जाए. यही जे. डे को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

feedback@chauthiduniya.com

बजट मिला, आवेदन मिले

मगर योजना ठप

हर इंसान की मूलभूत ज़रूरत होती है- रोटी, कपड़ा और मकान. पहली व दूसरी ज़रूरत यानी रोटी-कपड़े का जुगाड़ हर इंसान किसी न किसी तरह कर लेता है फिर चाहे वह कितना ही ग़रीब क्यों न हो. मगर तीसरी ज़रूरत यानी एक सुरक्षित आवास को पूरा करने के लिए हर इंसान को वर्षों इंतज़ार करना पड़ता है. हर अमीर-ग़रीब इंसान ख़ुद का घर बनाने का सपना देखता है. अमीर अपने घरौंदे के सपने आसानी से पूरे कर लेता है, क्योंकि उसके पास धन की कमी नहीं होती है, पर ग़रीब के लिए आज के दौर में ख़ुद का घर होना एक ऐसा सपना है जो आसानी से पूरा नहीं होता है. इसी तथ्य के मद्देनज़र सरकारें उनके ख़ुद के घरौंदे के सपने को पूरा करने के लिए आवासीय योजनाएं संचालित करती हैं, अनुदान देती हैं. आज़ादी के बाद से केंद्र व राज्य सरकार ग़रीबों के कल्याण के लिए समय-समय पर जब विविध योजनाओं की घोषणा करती हैं तो ऐसा लगता है कि देश या राज्य से ग़रीबी कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाएगी. सभी के पास घर होने का सपना शीघ्र ही पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है. वजह है योजनाओं को क्रियान्वयन करने की ज़िम्मेदारी जिनके पास है वे भ्रष्ट और निकम्मे हैं. इसका ताज़ा उदाहरण देखने को मिला महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में, जहां 21 हज़ार दलितों का अपना घर होने का सपना लापरवाह प्रशासन के कारण भंग हो गया है. राज्य में ग़रीबों के हित में संचालित इंदिरा आवास योजना हो या झोपड़पट्टी उन्मूलन योजना, सभी भ्रष्टाचारियों के बाहुपाश में दम तोड़ती नज़र आती हैं. नतीजतन ग़रीबों का सपना अधूरा ही रह जाता है.

राज्य में अनुसूचित जाति और नवबौद्धों के सामाजिक उत्थान के लिए सरकार ने सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग द्वारा आवास उपलब्ध कराने की योजना 18 नवंबर 2008 को शुरू करने की घोषणा की थी. इस योजना को नाम दिया गया था- अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक घरकुल (आवास) योजना. इस योजना का लाभ लेने के लिए अनुसूचित जाति व नवबौद्धों से 31 जनवरी 2009 तक आवेदन मंगाया गया था. योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 21 हज़ार 781 लोगों ने ज़िला विशेष समाज कल्याण अधिकारी, नागपुर के समक्ष आवेदन किया था. मगर विशेष समाज कल्याण अधिकारी ने आए आवेदनों पर विचार करने की ज़हमत उठाने की कोशिश भी नहीं की. विभागीय सूत्रों के अनुसार अब तक इन आवेदनों की छंटनी तक नहीं हुई है. मतलब साफ़ है कि योजना के क्रियान्वित होने के तीन साल गुज़र जाने के बाद भी एक भी आवास को मंज़ूरी नहीं दी गई. इससे पता चलता है कि राज्य प्रशासन ग़रीबों के प्रति कितना असंवेदनशील और निष्क्रिय है. विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि अनुसूचित जाति व नवबौद्ध वर्ग आवास योजना के लिए 24 दिसंबर 2010 को इस योजना के लिए 480 करोड़ 20 लाख 6 हज़ार रुपये का प्रावधान किया था. प्रस्तावित रक़म में से पहली क़िस्त के रूप में 359 करोड़ 62 लाख 50 हज़ार रुपये जारी किए गए. इस राशि का वितरण योजना के तहत महाराष्ट्र के प्रत्येक ज़िला विशेष समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त आवेदनों के आधार पर किया गया. योजना के लाभार्थियों को वितरित करने के लिए नागपुर ज़िले के हिस्से में 8 करोड़ 86 लाख की राशि आई. इस राशि में से नगर

परिषद क्षेत्र के 369 लाभार्थियों के लिए 4 करोड़ 91 हज़ार रुपये दिए जाने थे. बाक़ी 4 करोड़ 85 लाख 9 हज़ार रुपये का वितरण महानगर पालिका क्षेत्र में किया जाना था. परन्तु प्रशासन की असंवेदनशीलता के चलते इस योजना का लाभ पाने से अनुसूचित जाति व नवबौद्ध समुदाय लोग अब तक वंचित हैं. सरकार ने अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक आवास योजना के लिए प्रस्तावित रकम का उपयोग सिर्फ़ संबंधितों को आवास उपलब्ध कराने में ख़र्च की जाए, इसके लिए ज़िला विशेष समाज कल्याण अधिकारियों को पूर्णरूप से स्वतंत्र अधिकार दिए थे. योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 70,000 रुपये, पालिका क्षेत्र के लाभार्थी को 50,000 रुपये और महानगर पालिका क्षेत्र के लाभार्थियों को दो लाख रुपये अपना घर बनाने के लिए दिए जाने वाले थे. इस आवास योजना के तहत नागपुर ज़िले में 31 दिसंबर तक नागपुर की सभी तहसीलों से, नागपुर शहर व ज़िले ग्रामीण क्षेत्र से 21,781 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनकी तीन साल मे छटनी भी नहीं की गई. लिहाजा अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक आवास योजना अफ़सरशही के मकड़जाल में उलझ कर रह गई है. नागपुर समाज कल्याण विभाग में संपर्क करने पर एक कर्मचारी ने बताया कि योजना के तहत अनुसूचित जाति व नवबौद्धों का आवंटित होने वाले घरकुलों में पहले शौचालय का प्रावधान नहीं था. इस लिए मीटिंग पर मीटिंग होती रही और समय लंबा खिंचता गया. अब सरकार ने मकान के साथ शौचालय के प्रावधान को मंज़ूरी दे दी है. अब काम चालू हो गया है, लेकिन उसने अब तक एक भी घरकुल को मंज़ूरी न दिए जाने पर चुप्पी साध ली. उस कर्मचारी ने यह भी बताया कि शासन द्वारा अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घरकुल योजना के लिए जो राशि आवंटित की गई है, वह राशि ज़िला परिषद और महानगर पालिका को दे दी गई है, क्योंकि योजना का क्रियान्वयन उन्हीं के माध्यम से किया जाना है.

सूत्रों का कहना है यह हालत सिर्फ़ नागपुर की ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सभी ज़िलों में योजना का यही हाल है. अब सवाल यह उठता है कि जब योजना के तहत एक भी घरकुल (आवास) को मंज़ूरी नहीं दी गई तो योजना के लिए आवंटित करोड़ों की रक़म कहां गई? इस सवाल का जवाब समाज कल्याण विभाग के किसी अधिकारी के पास नहीं है. इस योजना के प्रति राज्य के समाज कल्याण मंत्री शिवाजीराव मोघे की उदासीनता साफ़ नज़र आती है. उन्होंने कभी योजना की प्रगति का जायज़ा लेने की ज़रूरत नहीं समझी. मामला उजागर होने के बाद भी उनकी चुप्पी समझ के परे है. इस योजना के संबंध मज़ेदार बात यह है कि अनुसूचित जाति व नवबौद्धों के आवास के पहले से आवंटित करोड़ों की रक़म अब तक ख़र्च नहीं हुई है, जबकि चालू आर्थिक वर्ष में इस योजना के लिए पहले से दोगुनी रक़म आवंटित की गई है. अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटक घरकुल (आवास) योजना के लिए 800 करोड़ की रक़म का प्रावधान 2011-12 आर्थिक वर्ष के लिए किया गया है. इस रकम से क्या अनुसूचित जाति व नवबौद्धों के घर का सपना साकार हो पाएगा? क्या प्रशासन चालू आर्थिक वर्ष में आवंटित रकम का सदुपयोग करेगा? इन सवालों का जवाब वंचितों को कब मिलेगा, कहना मुश्किल है, पर अब कुछ सामाजिक, राजनीतिक संगठनों ने शासन को जगाने के लिए आंदोलन करने हेतु कमर कसनी शुरू कर दी है. इस सबके बीच अनुसूचित जाति व नवबौद्ध वर्ग के ग़रीबों की आंखों में अपना घर होने का सपना अभी दूर की कौड़ी लगती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

महाराष्ट्र हलचल

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुतले पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए भाजपा कार्यकर्ता.

भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी की कांग्रेस पर आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता.

मिहान की बैठक को संबोधित करते एमएडीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यू.पी.एस. मदान

पूर्व क्रिकेटर दिलीप वेंगसकर के साथ बैंकर्स स्पोर्ट्स काउंसिल के पुरस्कार विजेता.

रिपब्लिकन ऑफ़ स्लोवेनिया की वित्त मंत्री दारजा रेडिक से चर्चा करते हुए सार्वजनिक व पर्यटन मंत्री छगन भुजबल.

नर्मल ग्राम पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन पुणे में किया गया. इस अवसर पर उपस्थित राज्यपाल के. शंकरनारायणन, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजीत पवान व अन्य.

भारतीय जनता पार्टी की बैठक समाप्त होने के बाद विधान भवन, मुंबई से बाहर निकलते हुए विरोधी पक्ष नेता एकनाथ खडसे, पांडुरंग फुंडकर, सुधीर मुनगंटीवार व अन्य.

चौथी दुनिया महाराष्ट्र
आवश्यकता
विज्ञापन व्यवस्थापक (पांच साल का अनुभव)
विज्ञापन प्रतिनिधि (कम से कम तीन साल का अनुभव)
प्रसार व्यवस्थापक (कम से कम तीन साल का अनुभव)
जिला प्रतिनिधि (महाराष्ट्र के हर जिले में- मानधन + कमीशन बेस पर)
वितरण एजेंट (महाराष्ट्र के हर जिले में)
संपर्क
आशीर्वाद पब्लिकेशन प्रा.लि.
२७, पिसे कॉम्प्लेक्स, धंतोली रेलवे पुल के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर- ४४०००३ फोन नं. - ०७१२- २७०७४१४/१५
Email :- chauthiduniya@gmail.com

ये क्या हो रहा है...

खुलकर सामने आइए गडकरी जी

फोटो- प्रभात पाण्डेय

देश में घोटाले पर घोटाले होते जा रहे हैं गडकरी जी. आप धरना देते जा रहे हैं गडकरी जी. प्रेस कांफ्रेंस करते जा रहे हैं. अपनी पार्टी के मनमुटाव को दूर करते जा रहे हैं. मगर इस बार लगता है आप अपने पुराने और घर के दुश्मन को निपटाने में थोड़ा पीछे रह गए. मुंडे की बग़ावत रंग ला रही है. ख़ैर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम महाराष्ट्र वासियों को आपसे काफ़ी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं. शरद पवार के बाद आप ही एकमात्र ऐसे नेता हमें मिले हैं, जो सही अर्थों में राष्ट्रीय स्तर के नेता बने हैं. शरद पवार तो एक क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं. हां, यह बात अलग है कि उनकी पहुंच दिल्ली में अच्छी है, लेकिन उन पर दाग़-धब्बे काफ़ी अधिक है. दाग़ तो आप पर भी आपके विरोधी लगाते हैं, लेकिन उस स्तर पर नहीं लगा पाए हैं, जिस स्तर पर देश के बड़े नेताओं पर लगाए जाते रहे हैं. कम से कम महाराष्ट्र की जनता की नज़रों में तो आप पाक-साफ़ हैं. आप विकासपरक नेता हैं. आप विकास के जनक हैं. आप कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के विकल्प हैं. आप भ्रष्ट कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ फेंकने के एकमात्र रहनुमा बन कर देश में उभरे हैं, क्योंकि आपका दामन साफ़ है. लेकिन गडकरीजी ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मुंडे जी को अपने आप पर इतना घमंड क्यों है? क्यों मुंडे भाजपा को कमज़ोर करना चाहते हैं? क्या मुंडे उमा भरती और कल्याण सिंह जैसे नेताओं से सबक़ नहीं लेना चाहते? क्या मुंडे अपने को उमा भारती और कल्याण सिंह से ज़्यादा प्रभावशाली नेता समझते हैं. और रहा सवाल कांग्रेस में जाने का तो नारायण राणे का हश्र क्या उनसे छिपा हुआ है? ख़ैर हम यहां बात मुंडे की नहीं कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं आपके राष्ट्रीय नेतृत्व की. गडकरी जी, आपने नागपुर को नेतृत्व प्रदान किया, आपने विदर्भ को नेतृत्व प्रदान किया, आपने महाराष्ट्र को नेतृत्व प्रदान किया. या यूं कहें आपने सभी को सफल नेतृत्व प्रदान किया. महाराष्ट्र में रहते हुए आपने समूचे राज्यों में रास्तों का जाल बिछाया. आपने कम आय वालों को आर्थिक उन्नति के रास्ते दिखाए. आपने विकास की नई अवधारणा दिखाई. जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो एक बारगी लगा कि अब ये सब बातें पूरे देश में लागू होंगी, लेकिन अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. पहले तो आपका पाला पड़ा राजनाथ सिंह की बनाई लॉबी से. दिल्ली की हाथी और लोमड़ी की चाल चलने वाली राष्ट्रीय मीडिया से. वह तो भला हो पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का जिन्होंने आपको दिल्ली की मीडिया में पहला ब्रेक दिया. ख़ैर, यह भी हमारा विषय नहीं है. गडकरी जी, लगता है कि दिल्ली की तिकड़ी (आपको अच्छे से मालूम है हम किसकी बात कर रहे हैं) के बीच आप कहीं खोते जा रहे हैं. इस तिकड़ी की मीडिया के बीच पकड़ अच्छी है. झारखंड में भाजपा की सरकार बनाकर आपने जिस परिपक्वता और दृढ़ता का परिचय दिया वह क़ाबिले-तारीफ़ था. कर्नाटक के मुद्दे पर सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के बीच का विवाद आपने जिस दृढ़ता और ख़ामोशी से निपटा दिया, किसी को कानो-कान ख़बर तक नहीं हुई. हमें मालूम है मुंडे भी निपट जाएंगे, लेकिन गडकरी जी, एक बात समझ में नहीं आई. आपने जसवंत सिंह, उमा भारती को भाजपा में लाकर अच्छा काम किया. लेकिन भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार को लेकर आपने अब तक कोई भी ठोस क़दम क्यों नहीं उठाया. रात के 1 बजे क्रूरता से रामदेव बाबा के कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा जाता है. क्या यह लोकतंत्र है? हर सच्चे भारतीय का ख़ून खौल उठा था और आपने सिर्फ़ राजघाट पर धरना देकर अपने कर्तव्य का ख़ात्मा कर दिया. क्यों गडकरी साहब? ऐसा क्यों किया आपने? कब भाजपा सच्चे विपक्ष की भूमिका में आएगी. क्यों नहीं देशव्यापी क्रांति हो सकती है. क्या आपका जनाधार समाप्त हो गया है? क्या आपके कार्यकर्ता सिर्फ़ पैसों के पीछे भागने लगे हैं? सीवीसी की नियुक्ति, अरबों का टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला, बीएसएनएल का वीएएस घोटाला, सीडब्ल्यूजी घोटाला, 26 लाख का कोयला घोटाला, अमरावती का सोफिया का पानी घोटाला जैसे कई घोटाले सामने हैं. फिर भी केंद्र सरकार की यह हिम्मत कि आधी रात सोते लोगों को लाठियों से पीटे और आप उपवास करके शांत हो जाएं. लगता है देश में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है गडकरी जी. दिल्ली की मीडिया को मैनेज करने के लिए आपने अब तक जिन पर भी भरोसा किया है, अब उन्हें छोड़िये और नई रणनीति बनाइए. गडकरी साहब, जनता के बीच जाइए, हम जैसों को फिर से विश्वास में लीजिए. नहीं तो हम फिर कहेंगे, यह क्या हो रहा है गडकरी जी!

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

भंडारा और नागपुर के मछली पकड़ने वाले लोग बांध में पानी के ऊपर तैरने वाली छोटी-छोटी मछलियां पकड़ते हैं और फिर उन्हें औने-पौने दामों में बेच देते हैं.

किसी और का न हो ऐसा हश्र

वो शर्मनाक 25 साल

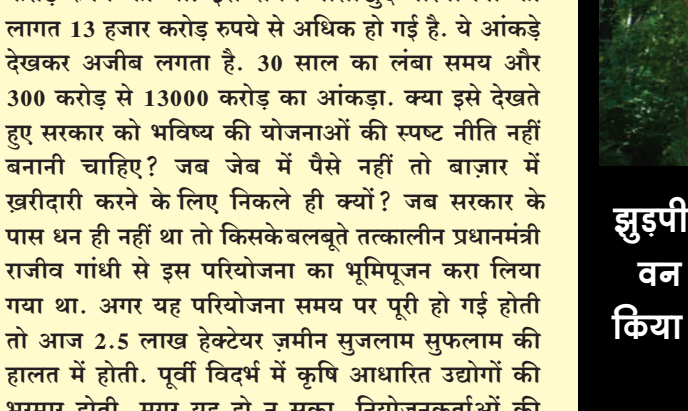

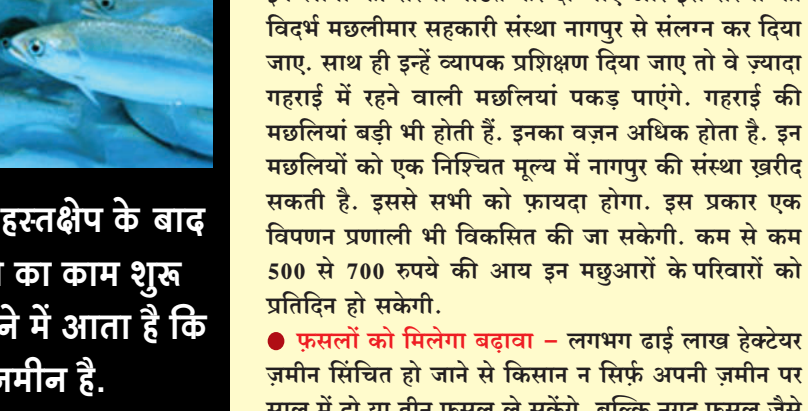

हमारे देश में एक परंपरा स्थापित हो गई है. वह यह है कि किसी भी शासकीय कार्य की अपूर्णता के लिए तत्काल संबंधित अधिकारी को दोषी क़रार दे दिया जाए. गोसीखुर्द के लिए भी जिन लोगों को अंदरूनी सच्चाई मालूम नहीं थी, वे 25 साल तक इसकी विफलता के लिए अधिकारियों को ही ज़िम्मेदार ठहराते रहे. कुछ तो यहां तक कहते थे कि देखो, पैसे नहीं हैं तो इनकी गाड़ी और बंगले का ख़र्च कहां से आता है. लेकिन गोसीखुर्द के शिलान्यास और उसकी पूर्णता (संभवत: 2017 अगर अब किसी ने रोड़ा नहीं अटकाया तो) में लगभग 30 साल लग जाएंगे. इस बीच इसमें लगने वाले रॉ मैटेरियल की क़ीमतें भी 15 से 20 गुना बढ़ गईं. 1983 में इसकी प्रथम प्रशासकीय मान्यता मात्र 372.22 करोड़ रुपये की थी. 2007 में द्वितीय सुधारित मान्यता 5659.09 करोड़ रुपये और 2008 में केंद्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की मान्यता 7777.824 करोड़ रुपये की थी. इस समय गोसीखुर्द परियोजना की लागत 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गई है. ये आंकड़े देखकर अजीब लगता है. 30 साल का लंबा समय और 300 करोड़ से 13000 करोड़ का आंकड़ा. क्या इसे देखते हुए सरकार को भविष्य की योजनाओं की स्पष्ट नीति नहीं बनानी चाहिए? जब जेब में पैसे नहीं तो बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए निकले ही क्यों? जब सरकार के पास धन ही नहीं था तो किसके बलबूते तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से इस परियोजना का भूमिपूजन करा लिया गया था. अगर यह परियोजना समय पर पूरी हो गई होती तो आज 2.5 लाख हेक्टेयर ज़मीन सुजलाम सुफलाम की हालत में होती. पूर्वी विदर्भ में कृषि आधारित उद्योगों की भरमार होती. मगर यह हो न सका. नियोजनकर्ताओं की दूरदृष्टि मुंबई नामक मायानगरी की माया में सिमट कर रह गई. विदर्भ के नेताओं की बोलती बंद कर दी गई. उनका ध्यान मायानगरी की रंगीनियों में भटका दिया गया. 1997–98 से 2003–2004 के बीच ज़रूर विदर्भ पाटबंधारे (सिंचाई) महामंडल ने बांड जारी कर 1678.99 करोड़ रुपये जमा किए. इससे गोसीखुर्द का काम कुछ आगे बढ़ा. इसमें से 1477 करोड़ रुपये बॉन्ड के वापस भी कर दिए गए. मानना तो पड़ेगा अजीत पवार को, जिन्होंने जल संसाधन मंत्रालय की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद 2005 से जो निधि का आवंटन शुरू किया. फिर सांसद विलास मुत्तेमवार, विलासराव देशमुख, शरद पवार आदि के प्रयासों से इसे राष्ट्रीय प्रकल्प का दर्जा मिला तो सन 2005 से सन 2010–11 तक इस प्रकल्प को 3326.100 करोड़ मिल चुके हैं और इसके निर्माण कार्य पर 3880.085 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं. यह भी ग़ौर करने वाली बात है कि जब 2005 से निधि मिलनी शुरू हुई तो 2008 में डैम का काम पूरा हो गया. अब भी अगर समय पर दिल्ली से निधि मिलती रही तो दोनों नहरों का काम पूरा हो जाएगा और विस्थापितों की समस्या भी हल हो जाएगी. आज इस परियोजना की सबसे बड़ी अड़चन विस्थापितों की समस्या ही है. मंत्री से लेकर अधिकारी हर स्तर पर उसकी तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है.

● **राष्ट्रीय परियजना बनने की कहानी–** नागपुर के वर्तमान सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद विलास मुत्तेमवार के बारे में यह तथ्य कम लोगों को ही मालूम है कि गोसीखुर्द परियोजना की आधारशिला रखने में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई. भूमिपूजन के समय मुत्तेमवार चिमूर के सांसद हुआ करते थे. बताते हैं कि राजीव गांधी को भूमिपूजन के लिए आमंत्रित करने में उनकी ख़ासी भूमिका थी. इसके बाद भी उन्होंने लगातार इस परियोजना के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर प्रयास जारी रखे. विलासराव देशमुख के मुख्यमंत्रीत्व काल में 27 मई 2007 को दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय विज्ञान परिषद की बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री की हैसियत से देशमुख ने गोसीखुर्द को केंद्र से मदद मिलने की ज़ोरदार वकालत की थी. देशमुख ने कहा था कि इस परियोजना को 41 हज़ार करोड़ रुपये की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 4 हज़ार करोड़ रुपये ही दे सकती है. इस बैठक में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, योजना आयोग के अध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया सहित संबंधित सभी वरिष्ठ अधिकारी व मंत्री उपस्थित थे. देशमुख ने गोसीखुर्द के पूरे होने के फ़ायदे भी गिनाए थे. इसमें कृषि के फ़ायदे, जल की उपलब्धता और भूजल स्तर से होने वाले फ़ायदे शामिल थे. इसके बाद सेंटर वॉटर कमीशन ने भी जब इस पर ध्यान दिया तो पाया कि यह तो मेगा प्रोजेक्ट है और इसे पूरा करना राज्य के बस की बात नहीं है. इसकी फंडिंग स्टेट नहीं कर सकता है. इस बीच केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में कृषि की स्थिति और बारिश पर कृषि की निर्भरता का मुद्दा उठता रहा. कृषि मंत्री के रूप में शरद पवार ने सिंचाई परियोजनाओं की दुर्दशा का पक्ष गंभीरता से रखा, उसमें महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना प्रमुख थी. विचार–विमर्श का दौर चलता रहा. वैसे तो सन 2004 से ही केंद्रीय सहायता की मांग की जाती रही थी, लेकिन 2008 का सूर्य नया संदेश लेकर आया, जब लोगों को पता चला कि केंद्रीय कैबिनेट ने देश के 14 प्रकल्पों को राष्ट्रीय प्रकल्प घोषित कर दिया है. उसमें महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना भी शामिल है. 8 फ़रवरी 2008 को फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई और तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दासमुंशी ने घोषणा की कि गोसीखुर्द के लिए जल संसाधन मंत्रालय व योजना आयोग को फाइनल फंडिंग बनाने का काम करने को कहा गया है. इस समय जल संसाधन मंत्री सैफुद्दीन सोज़ ने भी कहा कि ये राष्ट्रीय परियोजनाएं लैंडमार्क साबित होंगी. केंद्रीय जल आयोग दिल्ली की तकनीकी सलाहकार समिति ने 27 फ़रवरी 2008 को 7777.824 करोड़ रुपये की स्वीकृति (दर सूची 2007–08) के आधार पर दे दी. अंतत: 26 फ़रवरी 2009 को इसे राष्ट्रीय प्रकल्प के रूप में मान्यता मिल गई.

झुड़पी जंगल के लिए अलग-अलग अवधारणाएं हैं. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग ने कुछ ज़मीन को झुड़पी जंगल के रूप में चिह्नित करने का काम शुरू किया था. झुड़पी जंगल का मतलब है वह ज़मीन जहां घास हो. देखने में आता है कि कई ऐसी जगहें भी हैं, जहां झुड़पी जंगल के नाम पर बंजर ज़मीन है.

● **झुड़पी जंगल सबसे बड़ा विलेन –** 2005 के बाद जब इस परियोजना के काम ने गति पकड़ी और सन 2008 में बांध का निर्माण पूरा हो गया. सन 2007 में जब यह निर्णय लिया गया कि यहां पानी संग्रहण भी शुरू किया जाना है तो फिर झुड़पी जंगल का मामला सामने आया. फिर डेढ़ साल इसकी स्वीकृति में लग गए. इससे पहले परियोजना के लिए 2961.102 हेक्टेयर वन प्रस्ताव को वन व पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली की 19 फ़रवरी 1988 को मान्यता मिल गई थी. इसमें बांध व डुबान क्षेत्र के लिए 1487.61 हेक्टेयर व दाहिने नहर के लिए 1473.492 हेक्टेयर वन ज़मीन शामिल थी. इसके बाद जब जल संग्रह करने की बात सामने आई तो पता चला कि कुछ गांवों से लगी हुई क़रीब 700 हेक्टेयर की ज़मीन तो झुड़पी जंगल के अंतर्गत आती है यानी एक बार फिर वन विभाग से स्वीकृति के लिए वर्षों के लंबे संघर्ष की तैयारी. मगर सिंचाई विभाग ने एक नया रास्ता खोज निकाला. दाहिनी नहर की डिजाइन में परिवर्तन कर जो 1473.492 हेक्टेयर वन ज़मीन अधिग्रहित की गई थी, उसमें से 700 हेक्टेयर ज़मीन वन विभाग को वापस कर दी गई और बाद में डेढ़ साल के इंतज़ार के बाद अंतत: मई 2008 में वन विभाग की स्वीकृति मिल गई. वैसे भी झुड़पी जंगल के लिए अलग-अलग अवधारणाएं हैं. सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वन विभाग ने कुछ ज़मीन को झुड़पी जंगल के रूप में चिह्नित करने का काम शुरू किया था. झुड़पी जंगल का मतलब है वह ज़मीन जहां घास हो. देखने में आता है कि कई ऐसी जगहें भी हैं, जहां झुड़पी जंगल के नाम पर बंजर ज़मीन है यानी वेस्ट लैंड. उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता. फिर भी उस पर वन विभाग का क़ब्ज़ा है.

● **मत्स्य पालन से हो सकता है 500 करोड़ का व्यवसाय –** गोसीखुर्द परियोजना के एक सबसे उत्पादक और लाभकारी पहलू को अब तक नज़र अंदाज़ किया जा रहा है, वह है मत्स्य पालन व्यवसाय. एक अनुमान के मुताबिक़ अगर सुनियोजित ढंग से इस व्यवसाय का विकास किया जाए तो कुल 500 करोड़ रुपए का व्यवसयाय हो सकता है. अब तक होता यह है कि भंडारा और नागपुर के मछली पकड़ने वाले लोग बांध में पानी के ऊपर तैरने वाली छोटी–छोटी मछलियां पकड़ते हैं और फिर उन्हें औने–पौने दामों में बेच देते हैं. इससे उन्हें कुछ ख़ास लाभ नहीं मिल पाता. दिन भर में कुछ 70–80 रुपये ही कमा पाते हैं. अगर इन लोगों की संस्था गठित कर दी जाए और इस संस्था को विदर्भ मछलीमार सहकारी संस्था नागपुर से संलग्न कर दिया जाए. साथ ही इन्हें व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए तो वे ज़्यादा गहराई में रहने वाली मछलियां पकड़ पाएंगे. गहराई की मछलियां बड़ी भी होती हैं. इनका वज़न अधिक होता है. इन मछलियों को एक निश्चित मूल्य में नागपुर की संस्था ख़रीद सकती है. इससे सभी को फ़ायदा होगा. इस प्रकार एक विपणन प्रणाली भी विकसित की जा सकेगी. कम से कम 500 से 700 रुपये की आय इन मछुआरों के परिवारों को प्रतिदिन हो सकेगी.

● **फ़सलों को मिलेगा बढ़ावा –** लगभग ढाई लाख हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो जाने से किसान न सिर्फ़ अपनी ज़मीन पर साल में दो या तीन फ़सल ले सकेंगे, बल्कि नग़द फ़सल जैसे गन्ना, हल्दी, केला, फूल, मिर्ची का उत्पादन भी बढ़ेगा. इसके साथ ही धान, गेहूं, कपास, सोयाबीन की पैदावार भी बढ़ेगी. भूजल स्तर बढ़ने से सिंचाई पंप लगाए जा सकेंगे. सबसे बड़ी बात इन फ़सलों पर आधारित उद्योग इस समूचे विदर्भ की आर्थिक उन्नति में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करेंगे.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 4 जुलाई-10 जुलाई 2011

www.chauthiduniya.com

Website : sanjeevanibuildcon.in

"संजीवनी का है ऐलान, झारखण्ड-बिहार में हो सबका मकान"

AISHWARIYA RESIDENCY
Argora-Kathalmore Road, Ranchi
PLOT 6 LAC | DUPLEX 18 LAC

THE DYNASTY
Sidhu Kanhu Park, Kanke Road
PLOT 13 LAC | DUPLEX 25 LAC

SANJEEVANI HIGHWAY
Ranchi Patna Highway Road
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI TOWNSHIP
4 Lane, Kanke Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

SANJEEVANI STATION
BIT Pithoria, Road, Ranchi
PLOT 3 LAC | BUNGLOW 10 LAC

9661337777 / 9472722024

9472727767 / 9162779209

बाग़ियों ने फूंका बिगुल

दिग्विजय सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौक़े पर बिहार में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. मोर्चे के शिल्पकारों में एक बार फिर नीतीश से ख़फ़ा नेता ही हैं, लेकिन कई मायनों में यह पहले प्रयास से बिल्कुल अलग है. बाग़ियों द्वारा बनाए गए बिहार नवनिर्माण मंच का भविष्य क्या होगा, यह एक रोचक विषय है.

सरोज सिंह

बात अप्रैल 2009 से शुरू करते हैं. बिहार में सांसद दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तीसरे मोर्चे की सुगबुगहाट शुरू हो गई थी. नीतीश व लालू से नाराज़ और विकल्प की तलाश कर रहे नेताओं को दिग्विजय सिंह से एक उम्मीद बंध रही थी. किसान महापंचायत के बैनर तले ज़िले के दौरे शुरू हो गए और जनता के अपार समर्थन से सत्ता शीर्ष पर बैठे नेताओं की नींद उड़ने लगी, लेकिन दिग्विजय सिंह के अचानक चले जाने से सब धरा का धरा रह गया और तीसरा मोर्चा बनने से पहले ही बिखर गया. दिग्विजय सिंह की पहली पुण्यतिथि के मौक़े पर बिहार में एक बार फिर तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. मोर्चे के शिल्पकारों में एक बार फिर नीतीश से ख़फ़ा नेता ही हैं, लेकिन कई मायनों में यह पहले प्रयास से बिल्कुल अलग है. सबसे पहले हम बात करते हैं बाग़ियों द्वारा बनाए गए बिहार नवनिर्माण मंच की. मंच के संयोजक उपेंद्र कुशवाहा बनाए गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि यह मंच ग़ैर राजनीतिक है और बिहार का भला चाहने वाले चाहे वे किसी भी दल के क्यों न हों, इसमें शामिल हो सकते हैं. दरअसल बिहार में एक ज़िम्मेदार विपक्ष की कमी ने इस मंच की बुनियाद रखने में अहम भूमिका निभाई. महीनों माथा पच्ची और शुरुआती झिझक के बाद आख़िरकार दिल्ली व पटना के तार जैसे ही जुड़े मंच के गठन का काम आसान हो गया. उपेंद्र कुशवाहा, मंगनीलाल मंडल, अरुण कुमार, एजाज़ अली, प्रेम कुमार मणि, रामबिहारी सिंह आदि नेताओं ने 20 जून को पूरे बिहार से आए लगभग एक हज़ार सक्रिय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर यह तय किया कि बिहार नवनिर्माण मंच बनाकर बिहार के ज्वलंत मुद्दों पर संघर्ष किया जाए और सूबे के लोगों का भरोसा जीता जाए. भरोसेमंद सूत्रों पर भरोसा करें तो पटना और दिल्ली का तार जोड़ने में लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने पूरा ज़ोर लगाया.

इसके पीछे बहुत सारी वजहें बताई जा रही हैं. पहली और सबसे महत्वपूर्ण वजह लोजपा का यह आंकलन है कि लालू प्रसाद अब यादवों के एकछत्र नेता नहीं रह गए हैं. पिछले चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण से लोजपा के कुछ नेता इस नतीजे पर पहुंचे कि ग़ैर यादव उम्मीदवारों को यादवों का वोट दिलाने में लालू प्रसाद ज़्यादातर सीटों पर असफल साबित हुए हैं. जिन सीटों पर राजद लोजपा गठबंधन का ग़ैर यादव उम्मीदवार मैदान में था, वहां लालू प्रसाद का जादू नहीं चल पाया, जबकि रामविलास दलित वोटों को दिलाने में कामयाब रहे. इस नए नतीजे ने राजद व लोजपा की दूरी बढ़ा दी, जिसका प्रमाण पूर्णिया उपचुनाव में मिला, जहां राजद ने माकपा को तो लोजपा ने कांग्रेस का समर्थन किया. रामविलास पासवान व उपेंद्र कुशवाहा के नज़दीक आने की एक दूसरी वजह 2012 में यूपी का होने वाला विधानसभा चुनाव भी है. यह बात पहले से ही चर्चा में है कि रामविलास को मनमोहन की टीम में जगह मिल सकती है. यूपी के चुनाव ने इस संभावना को और भी बल दिया है.

कांग्रेस चाहती है कि पिछड़े व दलित वोटरों को रिझाने के लिए रामविलास पासवान यूपी में जमकर प्रचार करें. अगर बात बनती चली गई तो उपेंद्र कुशवाहा भी इस काम में रामविलास पासवान का साथ दे सकते हैं. दरअसल कांग्रेस यूपी और बिहार के मोर्चे पर एक साथ काम शुरू कर देना चाहती है. यही वजह है कि राहुल व सोनिया गांधी के साथ कई दौर की बातचीत के बाद रामविलास पासवान ने बिहार में नीतीश विरोधियों की गुटबंदी शुरू कर दी. दिल्ली के दरबार में ललन सिंह व अखिलेश सिंह के घटते क़द ने उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता आसान कर दिया. आहत ललन सिंह ने तो बयान जारी कर कहा कि नवगठित मंच से उनका कोई लेना-देना नहीं है. बिहार में लालू प्रसाद की घटती लोकप्रियता और यूपी चुनाव के कारण बनी परिस्थिति ने रामविलास पासवान व उपेंद्र कुशवाहा को एक किया और बिहार नवनिर्माण मोर्चा ज़मीन पर उतरा. यह मोर्चा 21 अगस्त को पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में एक सम्मेलन के बाद नवंबर में गांधी मैदान में एक बड़ी रैली कर अपनी ताक़त का अहसास कराएगा और संभव है इसी दिन यह मंच किसी दल में बदल जाएगा. इतना तय है कि इस दल का अलग अस्तित्व बना रहेगा और अगर सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से हुआ तो लोजपा व कांग्रेस से सीटों का तालमेल कर यह नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ पूरी मज़बूती से चुनावी मैदान में उतरेगा. तीसरे मोर्चे के अहम शिल्पकार रामबिहारी सिंह कहते हैं कि अभी चुनावी राजनीति या तालमेल की कोई बात नहीं है. मंच तड़पते व बिलखते बिहार के आंसू पोछने के लिए बना है. नक़ली विकास का सपना दिखाकर लोगों को ठगने का काम करने वालों को बेनक़ाब करने के लिए यह मंच बना है. उपेंद्र कुशवाहा की अगुआई में यह मंच पूरे बिहार का दौरा कर सरकार की ग़लत नीतियों का सड़कों पर विरोध करेगा और यह प्रयास करेगा कि बिहार के लोगों के दुख-दर्द को दूर किया जाए. जनसमस्याओं पर संघर्ष करके हम जनता का भरोसा जीतेंगे. पूर्व सांसद अरुण कुमार भी कहते हैं कि सपने बेचने वालों से बिहार की जनता को सावधान करने के लिए यह मंच बना है. हम राजनीतिक लोग हैं तो स्वाभाविक है कि तालमेल भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे, पर फ़िलहाल एकमात्र मक़सद जनजागरण करना है. जनता की समस्याओं पर संघर्ष कर इसका हल निकालना तथा सरकार के तानाशाही रवैये का विरोध करना मंच का मुख्य ऐजेंडा है. उपेंद्र कुशवाहा साफ़ करते हैं कि कुछ लोग भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ दिखावे का धर्मयुद्ध छेड़े हुए हैं, पर बिहार नव निर्माण मंच सही मायनों में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हल्ला बोलेगा. वह कहते हैं कि चुनावी राजनीति अभी एजेंडे में नहीं है. पहला लक्ष्य बिहार की कराह रही जनता के दुखों को समझना और इसे दूर करना है. पूरे बिहार में घूमकर हम कोशिश करेंगे कि जनता को न्याय मिले.

मंच के नेताओं के हौसले तो बुलंद हैं, पर मंच के सामने जो चुनौतियां हैं इसका ज़िक्र भी ज़रूरी है. पहला सवाल तो भरोसे का ही उठ रहा है. कहा जा रहा है कि जदयू के सांसद व पार्षद बने रहते नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ ईमानदारी से लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है. विश्लेषक मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अगर राज्यसभा से इस्तीफ़ा देकर बिहार की जनता का भरोसा जीतें तो उन्हें काफ़ी जनसमर्थन मिलेगा और मंच पर लोग विश्वास करेंगे. दूसरी बात उपेंद्र कुशवाहा और अरुण कुमार के अस्थिर मन की भी आती है. बार-बार दल बदलने से भी उनकी छवि गड़बड़ हुई है, इसलिए जनता के बीच जाकर उन्हें अपनी छवि बनाने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा. मंच में आने वाले दिनों में शामिल होने वाले नेताओं की इमेज का भी इन दोनों नेताओं को ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जनता नया व साफ़ सुथरा चेहरा चाहती है और इसी से उसका भरोसा भी जीता जा सकता है. नीतीश कुमार ने तो सारी कवायद पर बस इतना ही कहा कि यह उनका फंडामेंटल राइट है, पर उनके प्रवक्ता संजय सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा से मांग की है कि वह अपने दस साल के आय-व्यय का हिसाब जनता के सामने सार्वजनिक करें. यह आरोप-प्रत्यारोप चलता रहेगा, पर बिहार नवनिर्माण मंच के हर एक क़दम पर सभी दलों की नज़र रहेगी, यह तय है. अब यह मंच के नेताओं पर है कि वे एकजुट होकर किस तरह अपनी ताक़त व भरोसे का अहसास बिहार की जनता को करा पाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

Ph:0612-3296829, 9334252869, 9386941721

Approved by Govt. of India

...The Way to Grow

SKY CONSULTANCY SERVICE PVT. LTD

DIRECT & CONFIRM ADMISSION

Contact : 604, 6th Floor LUV-Kush Tower Exhibition Road, Patna-1

Engineering | MBA/PGDBM | MBBS | MCA | B.Ed

B.Pharma | Polytechnic | BBA | ITI

Ph: 0612-3296829
9334252869
9386941721

Branch: Yadav Market, Near Circut House Pakri Chowk Ara,
Mob;9798662051, 9334006756, Muzaffarpur Chhapra
Email : consultancy.sky.patna@gmail.com

बथानी थाने में दर्ज किए गए दोनों मामले एक तरह से झूठे ही हैं, लेकिन परेशानी पुलिस प्रशासन की बढ़ी और बदनामी सुशासन की हुई.

हर साल रोहिणी नक्षत्र में दो लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन में धान के बिचड़े डाल दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका.

हिरण बेमौत मर रहे हैं

शिकारियों के अलावा अब प्रकृति की मार से भी दुर्लभ हिरणों के अस्तित्व पर संकट आ गया है. पानी की कमी के कारण हिरणों की मौत हो रही है. बक्सर ज़िले के विभिन्न भागों में बड़े पैमाने पर हिरण पाए जाते हैं. इन वन्य जीवों की कई प्रजातियों में यहां काले दुर्लभ हिरणों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन कृष्ण मृग की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है. बक्सर के बसौली तथा बरूणा, डुमरांवा के नेनुआं अरांव, राजपुर के कोचड़ी तथा ब्रह्मपुर प्रखंड के नैनीजोर दियारा तथा कांट गांव के आसपास बड़ी संख्या में हिरण पाए जाते हैं, लेकिन प्रकृति के स्वच्छंद विचरण करने वाले इन मनोरम जीवों पर वर्षों से शिकारियों की नज़र लगी है. वन्य जीवों के दुश्मन शिकारियों ने खाल, मांस, चर्म तथा सींग के लिए अनगिनत हिरणों की हत्या कर दी. इन शिकारियों के तस्करों से भी ताल्लुक़ात रहे हैं. बक्सर में कई जगह कृष्ण मग (काले हिरण) भी पाए जाते हैं. इनमें केसर तथा कस्तूरी बहुतायात से पाए जाते हैं. ऐसे मृगों को खोज–खोज कर मारा गया. अब ये नाममात्र के रह गए हैं. इस प्रजाति के मृग विलुप्त होने की स्थिति में पहुंच गए हैं. पहली बार जून 2011 में हिरणों की हत्या का मामला पुलिस वन विभाग की नज़रों में आया. उस समय राजपुर थाना के कोचाढ़ी गांव के आसपास कुछ ख़ास लोगों द्वारा मांस भोज के लिए दर्जनों हिरणों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. ग्रामीणों की सक्रियता से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राजपुर थाने में हिरण हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई. छापेमारी में पुलिस ने हड्डियां तथा चर्म भी बरामद कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया. फिर वन्य जंतु सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत राजपुर थाना के हिरण बाहुल्य क्षेत्र को शिकार के लिए वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया. चारों तरफ़ सूचना पट भी लगाए गए, लेकिन विभाग द्वारा निगरानी के अभाव में शिकार का सिलसिला चलता रहा. फिर मई 2003 में बसौली गांव में तीन हिरणों की हत्या के बाद ग्रामीणों की तत्परता से बक्सर औद्योगिक थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, कुछ और मामले भी दर्ज हुए, पर परिणाम सिफ़र ही रहा. कुल मिलाकर काग़ज़ी औपचारिकता के अलावा इन वन्य जीवों को बचाने के लिए ज़मीनी प्रयास नहीं किया गया. जानकार तो यह भी बताते हैं कि यहां के हिरणों पर अंतरराष्ट्रीय तस्करों की नज़र लग गई है और आर्थिक लाभ के लिए शिकार की आड़ में वर्षों से हिरणों की हत्या हो रही है. इनके चर्म तथा सिंह की अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में काफ़ी मांग है और इसके बदले में अच्छी क़ीमत भी मिलती है. इसके अलावा इन जीवों पर प्रकृति के प्रकोपों का भी असर पड़ा है. अब तो पानी के अभाव में ये बेमौत मरने को विवश हैं. बक्सर में लगातार दो साल से सूखे के कारण आहार, पोखर तथा नदी–नाले सूख जाने के कारण हिरणों को पानी नहीं मिल रहा है. प्यास की त्रासदी झेलते पानी की तलाश में दूर–दूर तक भटकते हिरणों पर मृग तृष्णा की लोकोक्ति चरितार्थ हो रही है. हिरण खेतों में भटकने के बाद गांवों में आकर प्यास बुझाते देखे जा रहे हैं. गत वर्ष प्यास के कारण अनेक हिरण मर गए थे और इस बार भी वैसी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है.

बक्सर

ग्रामीणों की सक्रियता से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा राजपुर थाने में हिरण हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई गई. छापेमारी में पुलिस ने हड्डियां तथा चर्म भी बरामद कर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया.

जयमंगल पांडेय
feedback@chauthiduniya.com

ऋण सुविधा
वाहन ऋण, सावधि ऋण, कैश क्रेडिट, पैक्सों के वास्ते
ऋण, सुविधा सस्ते ब्याज दर पर उपलब्ध है
विशेष जानकारी के लिए सम्पर्क करें
दि कोशी सेन्ट्रल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड
प्रधान कार्यालय - साहू मार्केट, गांधी पथ सहरसा
फोन - 06478-224763, मुकेश - 9709695125, संजय - 9128668231, सौरभ - 9431864426

Enjoy with Nature
MOULDED FURNITURE
1 YEAR WARRANTY शर्तें लागू
आइये आनन्द उठाएँ प्रकृति के संग
प्रकृति की गोद में और करें बातें अपनी, अपनों से.....
मजबूती और ख़ूबसूरती का शानदार नमूना बस 'नेचर' की ही हो सकती है जो रखती है आपके लिए खास ख्याल।
NATURE MOULDED FURNITURE
Mfd. By: CENTURY POLYPLAST INDUSTRIES
For trade enquirey Contact
9386595926, 9334115955 or e-mail:centurypolyplast@gmail.com

BALMUKUND SUPER
TMT ही नहीं SUPER TMT
When red hot steel bar is passed through our unique TMT process (Thermo Mechanically treated), it's outer layer becomes HARD thereby making it extra strong corrosion & fire resistant and the inside part or the steel bar becomes SOFT AND DUCTILE-just like a Cocunut. it makes BALMUKUND SUPER TMT Steel bar the best choice to build your dream home.
Business excellance Award
मेरा मकान... सुरक्षित और सॉलीड निर्माण !!
TMT ही नहीं SUPER TMT
BALMUKUND SUPER TMT
EXTRA STRONG-ECONOMICAL-CORROSION RESISTANT-FIRE RESISTANT

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Estd 2000
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
- ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
- Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website : www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph : 0612-6455019, Mob. : 9334107607, 9835042835, 9234729075

नरक देखना हो तो समस्तीपुर आइए

विकास कुमार

बिहार लोकल बॉडीज़ इंपलाईज फेडरेशन से संबद्ध समस्तीपुर नगर परिषद कर्मचारी संघ की 43 दिन से चली आ रही हड़ताल भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन हड़ताल को ख़त्म कराने एवं शहर को गंदगी और दुर्गंध से मुक्ति दिलाने में नगर परिषद प्रशासन समेत वॉर्ड पार्षदों द्वारा बरती गई संवेदनहीनता ने शहरी क्षेत्र के सभी 29 वॉर्डों की जनता को जागरूक बना दिया है. समस्तीपुर नगर परिषद क्षेत्र की तक़रीबन 90 हज़ार की आबादी को बेहतर नागरिक सुविधा उपलब्ध कराना सत्ता–शासन का मुख्य कर्तव्य है, लेकिन सरकार द्वारा लाखों–करोड़ों रुपये ख़र्च करने के बावजूद शहर में सुविधाओं के नाम क्या–क्या उपलब्ध है, इस मामले में सब की पोल 43 दिन तक चली नगर परिषद कर्मियों की हड़ताल ने खोलकर रख दी है.

शहर के लोग दुर्गंधयुक्त वातावरण में कसमसाते रहे, जल जमाव एवं कीचड़मय सड़क पर चलते रहे, लेकिन इस समस्या के निराकरण में न तो नगर परिषद प्रशासन ने दिलचस्पी दिखाई और न ही जनता के द्वारा चुने गए उनके प्रतिनिधियों ने ही कोई ख़ास भूमिका निभाई. अंत में शहर के प्रबुद्धजनों, व्यवसायियों, स्वंयसेवी संगठनों एवं जदयू–भाजपा को छोड़ प्राय: सभी राजनीतिक दलों ने संयुक्त मोर्चा का गठन कर चरणबद्ध आंदोलन प्रारंभ किया. आंदोलन का असर होते देख कई वॉर्ड पार्षदों ने भी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से आंदोलन को समर्थन दिया. इस दौरान राजद के प्रदेश महासचिव सह संयुक्त मोर्चा के संयोजक फ़ैज़उर्रहमान फ़ैज़ के नेतृत्व में थानेश्वर स्थान चौक, काली मंदिर चौक, गणेश चौक, रामबाबू चौक, मारवाड़ी बाज़ार, स्टेशन चौक आदि स्थानों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन कर समस्तीपुर बंद की घोषणा की गई और शहर के कूड़े–कचरे और नालियों की सफ़ाई करने, जल निकासी हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के अलावा दर्जनों जनसमस्यों के निदान हेतु स्टेशन चौक से राजद, डीवाईएफआई, लोजपा, सीपीएम, सीपीआई, उनौस, आईसा, कांग्रेस, सीटू, टार्गेट, शक्ति युवा मंच आदि संगठनों के कार्यकर्ताओं ने शहर के मारवाड़ी बाज़ार, गोला रोड, स्टेशन रोड, रामबाबू चौक, गुदड़ी बाज़ार, मगरदही घाट, पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड, आर्य समाज रोड, बहादुरपुर, मालगोदाम चौक, बस पड़ाव आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुए व्यवसायियों एवं आमजनों का सहयोग और समर्थन लिया और बंद को अभूतपूर्व सफलता दिलाई. बंद के असर को देखते हुए प्रशासनिक तंद्रा भंग हुई. 14 जुलाई को अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में हड़ताली कर्मचारियों एवं संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई. विभिन्न 11 बिंदुओं पर चर्चा और सहमति होने के बाद 43 दिन पुरानी हड़ताल समाप्त हो गई, लेकिन हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद भी शहर में जल जमाव की समस्या जस की तस पड़ी है. स्थिति इतनी बदतर है कि इक्की–दुक्की सड़कों को छोड़कर कहीं भी पैदल चलना नामुमकिन है. अधिकारी या जनप्रतिनिधि तो स्कॉर्पियो, बुलेरो या अन्य लग्जरी गाड़ियों से कीचड़मय सड़क पार कर जाते हैं, लेकिन छात्र–छात्राओं एवं महिलाओं को सर्वाधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. ज़िलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा इसे आपदा के रूप में लेते हुए अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई करने का फ़रमान जारी किया गया, लेकिन सिर्फ़ फरमान जारी करने से संबंधित विभागीय अधिकारियों में कोई सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है. जल निकासी हेतु नाला निर्माण से जुड़ी दर्जनों योजनाएं अभी भी फाइलों में ही दबी हुई हैं. जहां नाले बने हुए हैं, वहां हल्की सी भी बारिश से समस्या फिर वहीं हो जाती है. मानसून की पहली बारिश में ही शहर पानी में तैरता नज़र आ रहा है. विभिन्न सड़कों और गलियों में जल जमाव से निपटने हेतु जो नालियां बनी हैं, उनकी स्थिति काफ़ी बदतर है. हड़ताल की अवधि में कूड़े का जो अंबार लगा है, उससे ही निपटने में सफ़ाईकर्मियों को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं. स्टेशन रोड, रामबाबू चौक, ताजपुर रोड, आरपी मिश्रा रोड, महिला कॉलेज रोड, प्रोफेसर कॉलोनी आदि स्थानों पर बने नाले अस्तित्वहीन हो चुके हैं. अधिकांश मोहल्लों में प्रस्तावित नाले का निर्माण भी नहीं हो सका है. नगर की समस्याओं के निदान एवं सौंदर्यीकरण हेतु ज़िलाधिकारी का फ़रमान अब तक फाइलों में ही सिमटा हुआ है.

feedback@chauthiduniya.com

शाहाबाद: प्यासी धरती कैसे उगलेगी अनाज

इंद्रपुरी बैराज से इस पूरे क्षेत्र के लिए निकली दर्जनों नहरें आरा व बक्सर मुख्य नहर के अलावा, गारा मुख्य नहर, पश्चिमी उच्च स्तरीय जगजीवन कैनाल, चौसा लाइन, डुमराव लाइन, धनसोई रजवाहा सहित कई नहरें जून महीने के उत्तरार्द्ध तक सूखी रह गईं.

20 वर्षों के इतिहास में पहली बार ऐसा मौक़ा आया, जब शाहाबाद की नस–नस में दौड़ने वाली सोन कैनाल की नहरों में निर्धारित समय से एक महीना बाद भी पानी नहीं मिला. इस क्षेत्र के खेत प्यासे रह गए और पानी के इंतज़ार में प्रतिवर्ष रोहिणी नक्षत्र में पड़ने वाले 25 फ़ीसदी धान के बिचड़े नहीं डाले जा सके. हर साल रोहिणी नक्षत्र में दो लाख हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन में धान के बिचड़े डाल दिए जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका. इंद्रपुरी बैराज से इस पूरे क्षेत्र के लिए निकली दर्जनों नहरें आरा व बक्सर मुख्य नहर के अलावा गारा मुख्य नहर, पश्चिमी उच्च स्तरीय जगजीवन कैनाल, चौसा लाइन, डुमराव लाइन, धनसोई रजवाहा सहित कई नहरें जून महीने के उत्तरार्ध तक सूखी रह गईं. इन हालात में राज्य सरकार शाहाबाद से इस वर्ष रिकॉर्ड चावल उत्पादन की उम्मीदें लगाए बैठी है. उधर, बाणसागर ने बिहार की हिस्सेदारी नहीं दी. रिहंद जलाशय ने पहले से ही हाथ खड़े कर रखे हैं.

ऐसी बात नहीं कि राज्य सरकार को इस समस्या की जानकारी पहले नहीं थी, क्योंकि रबी फ़सल पटवन के समय से ही बाणसागर एवं रिहंद से पानी लेने में समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं. सिंचाई विभाग के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रतिवर्ष इंद्रपुरी जलाशय से ख़रीफ़ फ़सल की खेती की शुरुआत करने के लिए दोनों संयोजक नहरों से क़रीब 11 हज़ार क्यूसेक पानी मिल ही जाता था. इस पानी में से 6 हज़ार क्यूसेक पश्चिमी संयोजक आरा मुख्य नहर एवं इसकी शाख़ाओं को दिया जाता था और शेष पानी पूर्वी संयोजक नहर पटना मुख्य नहर को दिया जाता था. इसके बाद जब रोपनी का कार्य शुरू होता था तो प्रतिदिन 24 हज़ार क्यूसेक पानी की ज़रूरत पड़ती थी, जो पिछले तीन वर्षों से लगातार कम होता जा रहा है. इस वर्ष जून महीने में 16 तारीख़ तक महज़ 11 सौ क्यूसेक पानी ही मिला, इससे अच्छी फ़सल की उम्मीद करना कितना उचित है. इसी ऐन वक़्त पर मौसम ने भी किसानों को दग़ा दिया है. रोहिणी नक्षत्र में तो एक बूंद पानी नहीं बरसा. इधर, भारतीय किसान महासंघ के नेता रामा शंकर सरकार ने इस समस्या को लेकर आंदोलन का ऐलान कर दिया है तो उधर राजद के पूर्व विधायक ललन पासवान ने जून के अंतिम सप्ताह में सिंचाई समस्या को लेकर ज़िले में डेरा डालो, घेरा डालो आंदोलन का ऐलान किया है, लेकिन किसानों की रोहिणी नक्षत्र में धान के बिचड़े डालने एवं इस वर्ष अच्छी उपज निकालने की योजना तो धरी की धरी रह गई है. हालात से मायूस ये किसान कभी दौड़ कर नहरों की तरफ़ जाते हैं और उन्हें सूखी देखकर लौटकर खेतों में बैठकर आसमान को निहारते हैं कि कहीं से तो दो बूंद पानी गिरे, ताकि प्यासी धरती का हलक़ तर हो सके.

ममता चौहान
feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र

हमार देवदास की सीडी का लोकार्पण

प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक किरणकांत वर्मा के निर्देशन में बन कर तैयार हो चुकी भोजपुरी फिल्म देवदास की वीसीडी पिछले दिनों रिलीज की गई. सीडी का लोकार्पण बांकीपुर क्लब के सभागार में राज्य के कला संस्कृति एवं खेल विभाग की मंत्री सुखदा पांडे, खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग के मंत्री श्याम रजक एवं शिक्षाविद समाजसेवी तथा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने संयुक्त रूप से किया. मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के मंत्री प्रेम कुमार भी उपस्थित थे. इस अवसर पर फिल्म समीक्षक डॉ. शंकर प्रसाद अवकाश प्राप्त भा.प्र.से. अधिकारी आर एन दास कुमार , अनुपम एवं फिल्म के निर्देशक किरणकांत वर्मा समेत बड़ी संख्या में कलाकार एवं पत्रकार उपस्थित थे.

रंजना रानी ने सामान्य सीट पर क़ब्ज़ा जमाया

प्रतिभा को कभी आरक्षण या किसी के उपकार अनुकंपा की आवश्यकता नहीं होती है एवं उसे छिपा कर भी नहीं रखा जा सकता है. वैशाली ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 36 से (सहदेई बुज़ुर्ग प्रखंड) जो कि सामान्य सीट थी, जहां से पांच पुरुष उम्मीदवार थे. इन सबके बीच सुल्तानपुर निवासी रंजना रानी शिक्षक की नौकरी को लात मारकर चुनाव मैदान में कूदीं और पांचों पुरुषों को हराकर ज़िला परिषद निर्वाचित हो गईं. रानी को कुल 95,00 मत प्राप्त हुए तथा प्रतिद्वंद्वी को 6,000 मत प्राप्त हुए. सामान्य सीट से एक महिला की जीत होने पर लोगों ने रानी की प्रशंसा की है एवं उन्हें सम्मानित करने की मांग मुख्यमंत्री से की है. विदित हो कि रानी एक बार पूर्व भी इस क्षेत्र से भाग्य आज़मा चुकी हैं, किंतु 2006 में वह हार गई थीं.

– चौथी दुनिया ब्यूरो

डीएसपी पर हत्या की साज़िश रचने का आरोप

रोसड़ा नरसंहार के मुख्य आरोपी एवं रोसड़ा उपकारा के बंदी कुंदन सिंह ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सैफ़ुर्रहमान पर अपनी हत्या की साज़िश रचने का आरोप लगाया है. इस संबंध में उन्होंने पुलिस कप्तान दलजीत सिंह, मानवाधिकार आयोग, पुलिस महानिदेशक आदि को आवेदन लिखकर जानकारी दी है कि उन्होंने क़ानून पर विश्वास जताते हुए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था, लेकिन जेल के अंदर प्रशासनिक मिलीभगत से उनकी हत्या की साज़िश रची जा रही है. उन्होंने अपनी पत्नी व ज़िला परिषद् की पूर्व उपाध्यक्ष सुनीता सिंह को भी किसी फ़र्ज़ी मुक़दमे में फंसाए जाने की आशंका व्यक्त करते हुए उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है.

– विकास कुमार

सांसद की अनुपस्थिति से कार्यकर्ताओं में आक्रोश

लगभग दो वर्षों से क्षेत्र से ग़ायब रहने को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में सांसद रामसुंदर दास के विरुद्ध आक्रोश पनप चुका है. इस बारे में भाजपा नेता संजय मिश्र प्रियरंजन दास, डॉ. प्रेमनाथ सिंह, दिलीप कुमार सिंह, आनंद जायावाल, जदयू नेता कपिलेश्वर सिंह कुशवाहा, श्याम बाबू साह, बटेश्वर राय, रामलगन सहनी, मो. नसीम इत्यादि ने कहा कि हाजीपुर की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर दो वर्ष पूर्व रामविलास पासवान को हराया था, किंतु वर्तमान सांसद को चिराग़ लेकर ढूंढना पड़ रहा है. आम जनता समस्याओं की सूची लेकर हम लोगों को पकड़ रही है तथा कार्यालयों में जाने पर वहां कोई सुनने वाला नहीं है. इस स्थिति में सांसद–विधायक से भेंट नहीं हो पा रही है. इन लोगों ने यह भी कहा कि दो वर्षों में सांसद ने एक बार भी जनसमस्याओं के संबंध में या किसी सरकारी कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र का दौरा नहीं किया है.

– अंजुम परवेज़

जदयू विधायक पर फायरिंग: आधी हक़ीक़त आधा फ़साना

सुनील सौरभ

बिहार में नीतीश कुमार सुशासन देने का लाख दावा करें, लेकिन गया ज़िले के अतरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णनंदन यादव पर फायरिंग के मामले ने साबित कर दिया है कि सबकुछ ठीकठाक नहीं है. विधायक द्वारा बथानी थाने में जिस तरह ख़ुद पर हुए हमले की लिखित शिकायत की गई, उसने भी इस मामले को संदेह के घेरे में ला दिया है. हालांकि कृष्णनंदन यादव द्वारा पूर्व राजद विधायक राजेंद्र यादव और कुंती देवी के परिजनों पर फायरिंग का आरोप लगाए जाने के बाद विधायक विरोधी लोगों ने भी सैकड़ों की संख्या में थाने पर पहुंचकर विधायक पर जानलेवा हमले करने की प्राथमिकी दर्ज कराई. इसी के बाद पूरा मामला विवाद के घेरे में आ गया और तरह–तरह की बातें अफ़वाह के रूप में फैलने लगीं. सच बात तो यह है कि बथानी थाने में दर्ज किए गए दोनों मामले एक तरह से झूठे ही हैं, लेकिन परेशानी पुलिस प्रशासन की बढ़ी और बदनामी सुशासन की हुई. आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सरकार या पुलिस प्रशासन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है. गया ज़िले का इमामगंज विधानसभा क्षेत्र नक्सलियों की समानांतर सरकार के लिए चर्चित है, वहीं अतरी विधनसभा क्षेत्र का बथानी प्रखंड पूर्व राजद विधायक राजेंद्र यादव, कुंती यादव के परिवार वालों के वर्चस्व के लिए चर्चित रहा है. अभी संपन्न हुए पंचायत चुनाव में पूर्व विधायक के कई परिजनों को विभिन्न पदों पर सफलता मिली. मामला यहीं पर आकर फंसा है. वर्तमान जदयू विधयक बथानी प्रखंड में होने वाले प्रमुख–उप प्रमुख के चुनाव में अपनी राजनीतिक ताक़त दिखाना चाहते थे, लेकिन पूर्व विधायक कुंती देवी के पुत्र रणजीत यादव अपने वर्चस्व को क़ायम रखना चहते हैं. आठ जून को घटना के दिन विधायक कृष्णनंदन यादव अपने समर्थक सुमिरन यादव को छुड़ाने के लिए बथानी थाना गए थे. सुमिरन को तीन दिनों से बथानी थाने में किसी मामले में पूछताछ के लिए रखा गया था.

कृष्णनंदन यादव, कुंती देवी, पूर्व एम.एल.ए (अतरी)

बताया जाता है कि बथानी थाने पर पूर्व विधायक राजेंद्र यादव के पुत्र रणजीत यादव की इतनी पकड़ है कि उसने थाने पर पहुंचकर सुमिरन यादव से जमकर दुर्व्यवहार किया. इस बात की जानकारी पर कृष्णनंदन यादव बथानी पहुंचे थे, लेकिन सुमिरन यादव को वह थाने से छुड़ाने में विफल रहे. सच बात है कि पंचायत चुनाव में रणजीत यादव पंचायत समिति सदस्य के रूप में जीतकर आया और प्रमुख पद का प्रबल दावेदार है. घटना के दिन विधायक कृष्णनंदन यादव वहां अपनी स्थिति दयनीय देखकर थाने पहुंचे और मुंशी रामायण दुबे को प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित आवेदन दिया, जिसमें कृष्णनंदन यादव ने पूर्व विधायक राजेंद्र यादव के पुत्र रणजीत यादव पर अपने दस–बारह समर्थकों के साथ बथानी मठ के पास जानलेवा हमला करने की नीयत से हवाई फायरिंग करने का आरोप लगाया. विधायक के तीन अंगरक्षक जब पोजिशन लेते हुए फायरिंग करने वाले युवकों की ओर बढ़े तो उनके भाग जाने की बात कही जाती है. हालांकि जितनी आसानी से विधायक अपने लिखित आवेदन को बथानी थाने के मुंशी रामायण दुबे के पास छोड़ आए, वहीं दूसरी ओर पूरे ज़िले में जदयू विधायक पर फायरिंग का मामला आग की तरह फैल गया तथा ज़िला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक के पुत्र रणजीत यादव को जब इस बात की जानकारी मिली तो वह भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बथानी थाना पहुंचा और विधायक कृष्णनंदन यादव समेत उनके तीन अन्य समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई. इस मामले की जांच करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक शफ़ीउल्ल हक़ ने कहा कि दोनों ओर से दर्ज मामले में इतनी बात सामने आई है कि वहां पर सात–आठ राउंड फायरिंग हुई है और फायरिंग करने वाले ख़ाली कारतूस भी उठाकर लेकर चले गए. सहायक पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विधायक ने फायरिंग नहीं की है. मामले की जांच की जा रही है और स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है.

विधायक कृष्णनंदन यादव पर अतरी विधानसभा क्षेत्र के एक अभियुक्त चंद्रिका यादव का बचाव करने का भी आरोप लगाया जा रहा है, जिसकी पुष्टि नीमचक बथानी अनुमंडल के पुलिस उपाधीक्षक द्वारा वरीय पदाधिकारी को दी गई जांच रिपोर्ट में की गई है. ऐसा बताया जा रहा है कि फायरिंग के मामले पर राज्य के मुखिया की ओर से जदयू विधायक कृष्णनंदन यादव को राजनीति करने तथा वर्चस्व क़ायम करने के लिए अजीबो–ग़रीब हरकत करने से बाज़ आने की सलाह दी गई है. कुल मिलाकर फायरिंग की यह घटना आधी हक़ीक़त आधा फ़साना बनकर रह गई है.

feedback@chauthiduniya.com

Designing Your Feature
NALANDA EDUVENTURES PVT. LTD.
IIT-JEE/KVPY/NTSE/OLYMPIADS/AIEEE/AIPMT
E-mail Id :- rkpsir@hotmail.com Website : www.nalanda.ac.in
MOST POWERFULL TRAINEERS FROM BANSAL CLASSES, KOTA
PHYSICS •R.K.P. Sir (M Tech, IIT Kanpur) •T.M Sir (B Tech, IIT Roorkee)
CHEMISTRY •Dr. R.K. Dubey (M.Tech. Phd, IIT Kanpur) •Shukla Sir (B.Tech. IIT BHU)
MATH •Dr. Jagdish Prasad (Phd IIT Kanpur) • Anil Sir (B.Tech. NIIT)
BIOLOGY •K.Prasad. (Msc.) • V.R. Sir (M.sc.DU)
Up to 100% Scholorship for Ranker's Batch/State Topper/NTSE/KVPY/OLYMPIADS SCHOLARS

Mission: To enhance the quality teaching for excellence in career education like IIT-JEE & other Engg. Entrance exam
Vision: To create successful individuals which make nation powerful.
Work Popicy: Professionalism, High quality, Hard work, Striving for perfection.
Values: To get leadership in Industry of career education at various level through integrity & transparency in our action.
Team Work: Teamwork is ability to work together between mamagemant &Academic team to achive common objective and produce coherence to provide unparallel service in country.
Eligibility: LAKSHAY COURSE – X appeard/XI Studying; SANKALP COURSE – XI appeard/XII Studying; TAPASYA COURSE – XII Pass; CRASH COURSE – XII Appeared/Pass
- Introductory classes.
- Doubt discussion classes.
- Extra classes(if require).
- Motivation & Boost-up classes (by-G.F.).
- Regular test system.
- Student Academic Performance Analysis Reports.
- Performance Awards.
- Batch Reshuffling System According to their Performance in class And test.
- Awareness about competitive Examinations.
- Student satisfaction survey.

Dear Student,
Swami Vivekananda while addressing the youth of India quoted from Upanished. This is more true for the students today aspiring for IIT-JEE then any one else. Arise, Awake and do not rest till your GOAL is achieved.
Constant perseverence, diligence and concentration the keys to success. IITians symbolizes excellence; they have excelled in all the fields whether it is corporate or scientific and engineering research and applications not only in India but all over the world.
I congratulate you to set your high inspiring aim to be an engineering professional through the prestigious Iits.
Here we in Nalanda Eduventure aim andinspire our stuents for hard work, sincerity and academic excellence by affactionate care and guidance. Teams of qualified and experienced faculty train the students with appropriate subject matter, regular test, problem solving akill and time management and encourage them to excell. The teams of Nalanda Eduventure are all devoted to your success, however you must be focused to your goal and put hardwork to realize it becouse II-JEE is an examination which reflects your real merit. Hence success and the rank in the examination depend wholly on your preparedness for it and accordingly you have to invest your time wisely well before the actual JEE.
We welcome you at Nalanda Eduventure and believe that your dream to become an IITian will be fulfilled.
Best Wishes
R.K.Prasad
CMD.
M.Tech IIT Kanpure
First Floor, Club Road, City Center, Opposite- Gossner College Ranchi (JHARKHAND), Ph 0651-6520374, 9199441995, 9905050374